आने वाले इंकलाबी तूफ़ानों के लिए तैयारी करो

हिन्दोस्तान किस दिशा में?

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी
नई दिल्ली

हिन्दोस्तान

किस दिशा में?

पहला संस्करण मार्च 1996
पुनः अनुवादित संस्करण, नवंबर 2016

मूल्यः 40/– रुपये

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के लिये
लोक आवाज पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
ई–392, संजय कालोनी
ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज़–2
नई दिल्ली–110020 द्वारा प्रकाशित और वितरित

© लोक आवाज पब्लिशर्स 1996

प्रकाशक की टिप्पणी

यह दस्तावेज़, *हिन्दोस्तान किस दिशा में?* हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव लाल सिंह द्वारा पार्टी की केन्द्रीय समिति की ओर से 23-24 दिसम्बर 1995 को नई दिल्ली में हुए पार्टी के तीसरे सलाहकार सम्मेलन में पेश की गयी रिपोर्ट है। इसका पहला संस्करण तीसरे सलाहकार सम्मेलन के फैसले के तहत चर्चा के लिये मार्च 1996 में जारी किया गया था। बाद में केन्द्रीय समिति ने उसे स्वीकार किया और अक्टूबर 1998 में हुए द्वितीय महाअधिवेशन ने, आम कार्यदिशा प्रस्थापित करने के काम में इसे एक महत्वपूर्ण मीलपत्थर माना है। दूसरा पुनः अनुवादित संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है।

विषय सूची

परिचय 1

भाग 1
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी और क्रांति के पीछे हटने का दौर 9

भाग 2
सोशल-डेमोक्रेसी के साथ समझौता करने वालों के खिलाफ़ संघर्ष को अंत तक ले जाना 23

भाग 3
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी और विचारधारात्मक तथा विवादात्मक संघर्ष 35

भाग 4
हिन्दोस्तानी सिद्धांत की आवश्यकता 51

भाग 5
हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों की एकता की पुनः स्थापना 67

भाग 6
राजनीतिक एकता पर 81

भाग 7
लोकतांत्रिक नव-निर्माण और उपनिवेशवाद-विरोधी क्रांति को अंतिम पड़ाव तक ले जाना 95

भाग 8
क्रांति का पड़ाव 109

भाग 9
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की रणनीति और कार्य योजना 115

परिचय

साथियों,

आज हम हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ की दहलीज पर खड़े हैं। हम, हिन्दोस्तानी ग़दर पार्टी (विदेश निवासी हिन्दोस्तानी मार्क्सवादी-लेनिनवादियों का संगठन) के सितम्बर 1977 में हुए महाअधिवेशन, तथा 25 दिसंबर 1980 को हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की स्थापना के दिनों से एक लम्बा रास्ता तय करके, अब इस महत्वपूर्ण तीसरी सलाहकार गोष्ठी पर पहुंचे हैं। मज़दूर वर्ग की एक ही हिरावल पार्टी स्थापित करने तथा पूरे समाज पर मज़दूर वर्ग की अगुवा भूमिका को विकसित करने के लिये तैयारी का एक पूरा दौर अब खत्म हो गया है और एक नये दौर की शुरुआत हो रही है।

1977 में हमने यह समझा कि पूरा कम्युनिस्ट आंदोलन, विश्व के दो-ध्रुवीय विभाजन के दबाव के तले टुकड़े-टुकड़े हो रहा था। आधुनिक संशोधनवाद की विभिन्न किस्में, संसदीय लोकतंत्र पर टिककर, और यथास्थिति को चुनौती देने वाली हर प्रकार की ताक़त को खत्म करने के लिये राज्य के साथ एकता बनाकर, तोड़-फोड़ करने की अपनी क्रांति-विरोधी भूमिका अदा कर रही थीं। पूंजीवाद पनप रहा था तथा सामंती अवशेषों, उपनिवेशवादी प्रभुत्व और बढ़ते साम्राज्यवादी हस्तक्षेप को लोगों के खिलाफ़ इस्तेमाल कर रहा था। यह पनप रहा पूंजीवाद ही इन सामंती अवशेषों, उपनिवेशवादी प्रभुत्व और साम्राज्यवादी हस्तक्षेप को सुरक्षा दे रहा था। यही विशाल जनसमूह की बद से बदतर हो रही हालतों के लिये जिम्मेदार था। संशोधनवाद की एक धारा इस पूंजीवादी विकास तथा प्रसार को "गैर-पूंजीवादी विकास" का रास्ता कह रही थी। इस प्रकार का संशोधनवाद, हिन्दोस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ तथा अंतरराष्ट्रीय तौर पर सोवियत सामाजिक साम्राज्यवाद के साथ खुलेआम समझौता कर रहा था। उन हालातों के

अंतर्गत, हमने हिन्दोस्तानी मज़दूर वर्ग की एक हिरावल पार्टी स्थापित करने का फैसला लिया, जिसके अंदर सभी हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट काम कर सकें; एक ऐसी पार्टी जो मज़दूर वर्ग तथा मेहनतकश लोगों की राजनीतिक एकता बनायेगी तथा समाज की प्रगति का रास्ता खोलेगी; एक ऐसी पार्टी जो सब प्रकार के संशोधनवाद व मौकापरस्ती के खिलाफ़, मार्क्सवाद-लेनिनवाद की सैद्धांतिक सोच पर आधारित होगी।

उस वक्त हम सबको मालूम था कि तय किया गया काम बेहद कठिन होगा, परंतु हमें यह भी मालूम था कि यह एक असंभव कार्य नहीं है। आज भी हम ऐसा ही मानते हैं। क्रांति के समस्त उतार-चढ़ावों के बावजूद और क्रांति के पीछे हटने के बावजूद, हम मज़दूर वर्ग की एक ही हिरावल पार्टी स्थापित करने की अपनी योजना से नहीं भटके, जिस पार्टी के अंदर सभी हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट काम करेंगे।

साथियों, हमें इस कार्य में प्रारंभिक सफलता मिली है। हमारे पास अपनी पार्टी है, लेकिन समस्त कम्युनिस्ट आंदोलन अभी भी बंटा हुआ है। दुनिया एक ऐतिहासिक मोड़ से गुज़री है। हमें अवश्य ही अपनी योजना पर कार्य जारी रखना चाहिये तथा वर्तमान समय के लिये आम कार्य दिशा स्थापित करनी चाहिये। हमें अवश्य ही हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों की एकता को पुनः स्थापित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिये। समाज को संकट से निकालने के लिये लोकतांत्रिक नव-निर्माण के एक ही कार्यक्रम के इर्द-गिर्द, मज़दूर वर्ग व विशाल जनसमूह की क्रांतिकारी राजनीतिक एकता बनाने के कार्य को लागू करने के दौरान, हमें अवश्य ही यह एकता पुनः स्थापित करनी चाहिये। इसके अलावा, साथियों, हमें एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की भूमिका की एक स्पष्ट आधुनिक परिभाषा देने का काम जारी रखना चाहिये, जो पार्टी विशाल जनसमूह को खुद अपना शासन करने में अगुवाई देने के लिये मज़दूर वर्ग को संगठित करती है। हमारा रणनैतिक लक्ष्य, अभी भी क्रांति द्वारा पूंजीवाद का तख्ता पलट कर समाजवाद के निर्माण का लक्ष्य है।

वर्तमान समय, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के लिये तथा सभी हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों के लिये अति निर्णायक समय है। आज हरेक मुद्दा बहस व चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले छः से अधिक वर्षों के दौरान विश्व-स्तर पर अचानक तब्दीलियां हुई हैं। इन हालातों के अंदर काम करती हुई, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी, द्वंद्वात्मक दर्शनशास्त्र के अनुसार, इन तब्दीलियों के अनुकूल और मार्क्सवाद, लेनिनवाद तथा समकालीन मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा के कार्यक्रम व निष्कर्षों के अनुकूल, एक आम कार्यदिशा तथा कार्यक्रम विकसित कर रही है।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के कार्यक्रम और सोच को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत करने के लिये, हमें वर्तमान हालातों से प्रारंभ करना चाहिये, सारी वस्तुगत व आत्मगत गतिविधियों की समीक्षा करनी चाहिये और उचित निष्कर्ष निकालने चाहियें। खासकर समाजवादी क्रांति व समाजवाद के निर्माण के विशाल क्षेत्र में बहुत-सी गतिविधियां हुई हैं। समाजवाद की बर्बादी और प्रतिक्रांति का नकारात्मक अनुभव भी हमारे सामने है। इस दौर के अंदर क्रांति के पीछे हटने के हालात के बावजूद भी हमारे युग का स्वभाव बदला नहीं है, अर्थात अब भी यह साम्राज्यवाद और श्रमजीवी क्रांति का युग ही है। ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं, कि हालात जल्द ही बदलने वाले हैं, उतराव से चढ़ाव में तब्दील होने के संकेत हैं, हालांकि क्रांति का पीछे हटना अभी भी हावी है। इन सभी गतिविधियों की समीक्षा न सिर्फ हमारी सोच को समृद्ध बनाती है, बल्कि हमारे द्वंद्वात्मक दर्शनशास्त्र को भी वर्तमान की ज़रूरतों के अनुकूल बनाती है। यह कार्य, हिन्दोस्तानी क्रांतिकारी सिद्धांत की रचना के लिये अति आवश्यक है, जिस (सिद्धांत) के बगैर एक क्रांतिकारी आंदोलन संभव नहीं है।

सभी समीक्षाओं को करने के लिये, एक मार्गदर्शक के तौर पर क्लासिकी मार्क्सवादी-लेनिनवादी रचनाओं को इस्तेमाल करना आज भी उतना ही आवश्यक है जितना कि बीते समय में था। हमें मालूम है कि फ्रेडरिक

ऐंगेल्स ने कहा था कि सच्चाई – जिसके बोध को उन्होंने दर्शनशास्त्र का मुख्य कार्य माना था – को एक ऐसी वस्तु नहीं समझना चाहिये "जो तैयार हठधर्मी बयानों का समूह हो और जिसे एक बार खोज कर सिर्फ रट्टा लगाने की ही ज़रूरत हो"।[1] बल्कि इसके विपरीत, ऐंगेल्स के मुताबिक, द्वंद्वात्मक दर्शनशास्त्र "प्रत्येक वस्तु के तथा प्रत्येक वस्तु के अंदर के परिवर्तनशील स्वभाव को जाहिर करता है; इसके सामने, अस्तित्व में आने व खत्म हो जाने की, नीचे से ऊपर तक चढ़ने की अनवरत प्रक्रिया, के अलावा अन्य कुछ भी टिक नहीं सकता। और द्वंद्वात्मक दर्शनशास्त्र स्वयं, एक सोचने वाले दिमाग के भीतर इस प्रक्रिया की मात्र एक झलक के सिवाय और कुछ नहीं है। इसका, निस्संदेह, एक रूढ़ीवादी पक्ष भी है; यह मानता है कि ज्ञान और समाज के निश्चित पड़ाव, अपने समयों व हालातों के लिये मुनासिब हैं; बस इतना ही। इस प्रकार के दृष्टिकोण का रूढ़ीवाद तुलनात्मक है; इसका क्रांतिकारी स्वभाव अपरिवर्तनशील है और द्वंद्वात्मक दर्शनशास्त्र इसी एकमात्र अपरिवर्तनशीलता को मानता है।"[2]

ऐंगेल्स के इन निष्कर्षों को मानते हुये, यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को, वर्तमान से प्रारंभ करके, साम्राज्यवाद तथा श्रमजीवी क्रांति के इस युग के समूचे अनुभव की समीक्षा करने का काम जारी रखना चाहिये, जो कि यह इस वक्त कर रही है। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को उन विनाशवादियों के चंगुल में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिये, जो कहते हैं कि कोई भी क्रांतिकारी उपलब्धि तब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक उनके पास एक अचूक व अंतिम ज्ञान न हो। हमें समीक्षा के कार्य को, क्रांति और समाजवाद की जीत के लिये मज़दूर वर्ग को संगठित करने के काम के साथ-साथ जारी रखना चाहिये।

---

[1] फ्रेडरिक ऐंगेल्स, "लुडविग फ़ायरबाख़ तथा क्लासिकी जर्मन दर्शनशास्त्र का अंत", मार्क्स तथा ऐंगेल्स, संकलित रचनायें, प्रोग्रेस पब्लिशर्स 1968, अंग्रेजी संस्करण, पृष्ठ 588

[2] *उपरोक्त,* पृष्ठ 588

लेनिन ने भी ऐंगेल्स जैसे ही निष्कर्ष निकाले थे, जब उन्होंने लिखा था : "ठीक इसीलिये कि मार्क्सवाद एक बेजान हठधर्म नहीं है, एक अंतिम, संपूर्ण व तैयारशुदा अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है, बल्कि कार्यवाही के लिये एक सजीव मार्ग-दर्शक है, अतः सामाजिक जीवन की हालतों में आश्चर्यजनक अचानक तब्दीलियों की झलक इसमें अनिवार्य है"।[3] कोई भी कम्युनिस्ट इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि दुनिया के अंदर बड़ी व अचानक तब्दीलियां आई हैं। ये उन सामाजिक ताकतों के उत्थान में नज़र आती हैं, जो मार्क्सवाद से वफ़ादारी का दावा करती हैं परन्तु वास्तव में सोशल-डेमोक्रेसी में पतित हो चुकी हैं या उसके साथ समझौता कर रही हैं। पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ की हुकूमतों के गिरने से, सोशल-डेमोक्रेसी का संकट और भी तेज़ हो गया है। "मुक्त बाज़ार अर्थव्यस्था" के साथ ही साथ, नकली समाजवाद और सोशल-डेमोक्रेसी बदनाम हो गये हैं। इससे ऐसी अनुकूल हालतें पैदा हुई हैं जिनका इस्तेमाल करके कम्युनिस्ट सोशल-डेमोक्रेसी से पूरी तरह से नाता तोड़कर, गहरी क्रांतिकारी तब्दीलियों के लिये उपलब्ध स्थान पर कब्ज़ा कर सकते हैं और इसका विस्तार कर सकते हैं। वक्त की मांग है कि कम्युनिस्ट प्रकट हो रहे घटनाक्रम द्वारा खड़ी की जा रही समस्याओं का निबटारा करें। इनमें से एक समस्या, सोशल-डमोक्रेसी के साथ समझौता करने वाले सभी के खिलाफ़ संघर्ष की समस्या है। कम्युनिस्टों के लिये ज़रूरी है कि समकालीन मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा की रक्षा करने तथा इसे और विकसित करने का कार्य जारी रखा जाये। यह कार्य, वर्तमान से प्रारंभ करके, साम्राज्यवाद तथा श्रमजीवी क्रांति के संपूर्ण युग के ऐतिहासिक अनुभव की समीक्षा के आधार पर करना चाहिये। समकालीन मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा, समाजवादी क्रांति तथा समाजवाद के निर्माण की हालतों पर और आधुनिक संशोधनवाद व पूंजीवाद की पुनः स्थापना के खिलाफ़ संघर्ष पर, मार्क्सवाद-लेनिनवाद

---

[3] वी. आई. लेनिन, "मार्क्सवाद के ऐतिहासिक विकास के कुछ लक्षण" संकलित रचनायें, प्रोग्रेस पब्लिशर्स, अंग्रेजी संस्करण ग्रंथ 17, पृष्ठ 42

को लागू करने के अनुभव का सारांश है। यह फासीवाद, सैन्यवाद तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ़ संघर्ष, और साथ ही साथ मध्य-युगवाद को खत्म करने के लोगों के संघर्ष पर मार्क्सवाद-लेनिनवाद को लागू करने के अनुभव का भी सारांश है। समकालीन मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा, क्रांति के अभ्यास से समृद्ध तथा विकसित हुआ मार्क्सवाद-लेनिनवाद है। यह, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के बुनियादी असूलों की पुष्टि है और उनका अधिक विकसित रूप है। समकालीन मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा, वर्तमान हालतों के अंतर्गत मार्क्सवाद-लेनिनवाद का अंतिम रूप नहीं है, बल्कि उसकी निरंतरता तथा समृद्धि है।

सामाजिक गतिविधियां एक ऐसी स्थिति में पहुंच गयी हैं कि एक सचेत व योजनाबद्ध आधार पर इतिहास को रचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह कार्य ठोस परिस्थितियों में द्वंद्वात्मक दर्शनशास्त्र को लागू करके किया जाये। इस पूर्व-इतिहास के दौर को, भाग्य, हठधर्मों व बेवजह वस्तुओं और घटनाओं के इस इतिहास को खत्म करना मज़दूर वर्ग की ऐतिहासिक नियति है। यह एक सचेत, भौतिकी, मानवीय इतिहास की शुरुआत करने की नियति है जो नये समाज की रचना करने में क्रांतिकारी वर्ग का विशेष कार्य है।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को इस गौरवपूर्ण ऐतिहासिक कार्य में मुख्य आत्मगत शक्ति, संगठित जागृति और मज़दूर वर्ग का हिरावल दस्ता व नेतृत्व होने पर गर्व है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मज़दूर वर्ग द्वारा सफलतापूर्वक मानव इतिहास रचने का समय आ गया है। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का कर्तव्य है कि हम, अपने सैद्धांतिक चिंतन को समकालीन मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा पर आधारित रखते हुये, अपनी संगठित करने व स्पष्टता लाने की भूमिका, मज़दूर वर्ग के संग्रामी हिरावल दस्ते की भूमिका को अदा करे। कम्युनिस्ट आंदोलन, मार्क्सवाद-लेनिनवाद की बुनियादी असूलों पर दृढ़ता के साथ चलते हुये, मज़दूर वर्ग व विशाल जनसमूह

को इस युग के निश्चित अमली कार्यों के लिये एकताबद्ध कर सकेगा, जो कार्य इस प्रकार हैं : सरमायदारों के निजीकरण और उदारीकरण के मज़दूर-विरोधी, लोक-विरोधी व राष्ट्र-विराधी कार्यक्रम को तुरंत खत्म करना; लोकतांत्रिक नवनिर्माण करना और समाज को संकट से निकालना; लोकतांत्रिक, उपनिवेशवाद-विरोधी, सामंतवाद-विरोधी तथा साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष को जीत तक पहुंचाने की एक लाज़मी शर्त बतौर पूंजीवाद का तख्ता पलट करना; और क्रांति लाकर समाजवाद का निर्माण करना।

भाग एक

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी और क्रांति के पीछे हटने का दौर

साथियों,

दुनिया की वर्तमान हालत, क्रांति के पीछे हटने, कम्युनिज़्म के खिलाफ़ एक जबरदस्त हमले, मज़दूर वर्ग और मेहनतकश लोगों के खिलाफ़ एक सबतरफे समाज-विरोधी हमले में उलझी हुई है। दुनिया एक गहरे संकट में है और अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा अपनी हुक्मशाही के नीचे एक-ध्रुवीय विश्व की रचना के लिये की जा रही "अमन साज़ी" की वजह से हालत और भी बदतर होती जा रही है। कुछ अन्य ताक़तें भी हैं जो बहु-ध्रुवीय विश्व की स्थापना के लिये जोर लगा रही हैं, एक ऐसी दुनिया जो साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा आपस में फिर से बांटी गयी हो। इस हालात के अंदर, क्रांति और समाजवाद की जीत के लिये मज़दूर वर्ग को अगुवाई देने की महान जिम्मेदारी कम्युनिस्टों पर है।

हिन्दोस्तान में, कई अन्य देशों की तरह ही, कम्युनिस्ट राजनीतिक कार्य की अवधारणा को बिगाड़ देने से हालत और ज्यादा उलझ गई है। कम्युनिस्ट राजनीति को या तो राज्यतंत्र को चलाने में हिस्सा लेने तक सीमित किया गया है, या फिर हिन्दोस्तानी शासक वर्गों द्वारा मजबूत की जा रही हिंसा की पूजा और उसके प्रयोग में सीधे तौर पर भागीदारी तक गिरा दिया गया है। बड़े पैमाने पर राजनीति के अपराधीकरण तथा राजकीय आतंकवाद के इस्तेमाल को एक आम बात बना दिये जाने से सैकड़ों व हजारों लोगों को उनकी ज़िंदगियों तथा आज़ादियों से वंचित कर दिया गया है। इस कार्यवाही ने राजनीतिक कार्य का दायरा बहुत ही संकुचित कर दिया है, यहां तक कि इस कार्य को तरह-तरह के अपराधी तत्वों के हवाले कर दिया गया है। राज्य के ढांचे के अंदर ही

पदों तथा जिम्मेदारियों की बढ़ती लुभावनी पेशकशों ने हिन्दोस्तान में राजनीति के अपराधीकरण को जायज़ ठहराने में कुछ कम्युनिस्टों की भूमिका को और भी विस्तृत बना दिया है। हिन्दोस्तान में तथा विश्व के कई अन्य भागों में राजकीय आतंकवाद के इस्तेमाल और इसके साथ-साथ राज्य के ढांचे के अंदर ही कुछ कम्युनिस्टों को स्थान दिया जाना, कम्युनिस्टों के लिये मज़दूर वर्ग के हिरावल दस्ते बतौर अपनी ऐतिहासिक भूमिका अदा करने को असंभव बना रहा है। इस ऐतिहासिक भूमिका के रास्ते में एक अन्य रुकावट यह है कि कुछ कम्युनिस्ट पार्टियां तथा दल, इस बात को समझने में नाकाम रहे हैं कि विश्व के दो-ध्रुवीय बंटवारे के खत्म हो जाने का अर्थ यह है कि अब एक ही कम्युनिस्ट आंदोलन है और साम्राज्यवाद तथा सरमायदारी के साथ समझौता करने वाले सभी के खिलाफ़ एक ही संघर्ष है। नतीजे के तौर पर, यह नाकामयाबी मज़दूर वर्ग को समाजवादी समाज के निर्माता की अपनी ऐतिहासिक भूमिका अदा करने से रोकती है।

शीत युद्ध वाली यह मानसिकता अभी भी हावी है कि "मेरे दुश्मन का दुश्मन, मेरा दोस्त है"। अलग-अलग बहानों के तहत लगातार लोगों के कत्ल हो रहे हैं, चाहे यह हिन्दोस्तान में एक "नक्सलवादी", "माओवादी", "अलगाववादी" या "उग्रवादी" का कत्ल हो या अन्य देशों में, मिश्र, अलजीरिया या मध्यपूर्व, फिलीस्तीन, इस्राइल और लेबनान में एक "आतंकवादी" या "मुस्लिम कट्टरपंथी" का कत्ल हो। और कहीं भी इन कत्लों का कोई खास विरोध नहीं हो रहा है। इसके अलावा, जब बड़ी साम्राज्यवादी तथा अन्य शक्तियों के हित में हो, तो राजकीय आतंक तथा हिंसा की व्यक्तिगत कार्यवाहियों को पूरे-पूरे देशों के खिलाफ़, जैसे कि इरान, लिबिया, सूडान, क्यूबा और कुछ अन्य देशों के खिलाफ़, उचित करार दिया जाता है और कहा जाता है कि ये देश "अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद" को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अमरीकी साम्राज्यवाद तथा अन्य साम्राज्यवादी ताक़तें, पूरी दुनिया के अंदर अपने-अपने ग्राहक देशों को बेरोकटोक पैसा और हथियार दे रही हैं, यहां तक कि हैती जैसे कुछ देशों पर सैनिक कब्ज़ा कर लिया गया है,

और बोस्निया की हालत को बिगाड़ कर उसमें दखलंदाज़ी और उस पर कब्ज़ा किया जा रहा है। वे पूरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व कायम करने की एक विधि के तौर पर, साम्राज्यवादी "अमन बचाव" के स्तर से साम्राज्यवादी "अमन साज़ी" के स्तर तक पहुंच गये हैं। साम्राज्यवादी "अमन साज़ी" और एक-ध्रुवीय या बहु-ध्रुवीय विश्व की अवधारणायें एक तबाहकारी विश्व युद्ध के कारक हैं।

हिन्दोस्तान के पूंजीपति, अंतरराष्ट्रीय तौर पर बहुत आगे बढ़ने की संभावना से मदहोश होकर, अपने उदारीकरण के कार्यक्रम को बड़ी गैर-सावधानी के साथ बढ़ावा दे रहे हैं। वे हिन्दोस्तानी भूमि पर यह अवधारणा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूंजीपतियों के अलावा किसी और के प्रति समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हिन्दोस्तान के पूंजीपति वही भाषा बोल रहे हैं, जो अगुवा पूंजीवादी देशों में सबसे अधिक प्रचलित है। इस तर्क के अनुसार यह ऐलान किया जाता है कि शोषण को अति तीव्र करने के लिये, पूंजीवादी व्यवस्था को सुधारने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। वे ऐसे बात कर रहे हैं कि मानो कि खुशहाली की तरफ जाने का मात्र एक ही रास्ता है – मज़दूर वर्ग के शोषण को और तेज़ करना। अपनी खुद की खुशहाली को सबकी खुशहाली का नाम देकर, हिन्दोस्तान के बड़े पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों ने विस्तृत तौर पर एक समाज-विरोधी हमला शुरू कर दिया है। वे लोगों को बांटने के लिये, सांप्रदायिक हिंसा व अन्य भटकावों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि लोग उनके हमले का विरोध न कर सकें।

आज, 21वीं सदी की पूर्व संध्या के समय, कोई भी इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता कि लोग समाज में जन्म लेते हैं और उनकी खुशहाली सुनिश्चित करना समाज की जिम्मेदारी है। यह अधिकारों की आधुनिक परिभाषा के साथ मेल खाता है और हिन्दोस्तानी राजनीतिक विचारधारा के अहम पहलुओं में से भी एक है। लेकिन आज के "पश्चिमी" विद्वानों के अनुसार, वित्तीय अल्पतंत्रवादियों के सिवाय और किसी के भी प्रति, समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तथाकथित

व्यक्तिगत हित को सामूहिक हित तथा समाज के आम हितों से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। हिन्दोस्तान की धरती पर साम्राज्यवादी सिद्धांतों के इस प्रकार थोपे जाने से गंभीर उलझनें पैदा हो रही हैं। यह पूंजीवादी संकट को और भी गहरा बना रहा है और लोगों के अंदर अत्यंत क्रोध को जगा रहा है। बड़े पूंजीपति और बड़े जमींदार, लोगों की भलाई और समाज के भविष्य को गंभीर खतरे में डालने के लिये, इन सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर, क्रांति के पीछे हटने तथा कम्युनिज़्म के खिलाफ़ हमले के हालातों में, कम्युनिस्ट अपने-आप को समाजवाद और कम्युनिज़्म में अपनी आस्था को सिर्फ दोहराने तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं। इसके विपरीत उनको, हिन्दोस्तान में थोपी जा रही समाज की इन "पश्चिमी" अवधारणाओं को खत्म करने में लोगों को अगुवाई देनी चाहिये। मार्क्सवाद-लेनिनवाद के क्लासिकी ग्रंथों की पूजा करना, तथा उसके उपरांत दबे-कुचले और शोषित लोगों को यह मंत्र पढ़ कर सांत्वना दिलाना कि उनकी मुक्ति जल्द ही होने वाली है – इससे कम्युनिज़्म की शोभा नहीं बढ़ती। इससे न तो कम्युनिज़्म के लिये समाज में उपलब्ध स्थान को भर पायेंगे और न ही क्रांति के द्वारा उसमें पूरे समाज को शामिल करने के लिये उस स्थान का विस्तार कर पायेंगे।

निजीकरण और उदारीकरण के नारों तले चलाये जा रहे समाज-विरोधी हमले का विरोध करने के लिये उपलब्ध स्थान, इस वक्त इतना व्यापक है कि पूंजीवादी व्यवस्था को हमेशा के लिये जड़ से उखाड़ फेंकने के लिये, मज़दूर वर्ग और मेहनतकश लोगों को संगठित करने में कम्युनिस्टों को सबसे आगे होना चाहिये। इस आंदोलन के साथ ही साथ, कम्युनिस्टों को हिन्दोस्तानी सिद्धांत और वर्तमान समय के लिये आम कार्यदिशा को विस्तृत रूप से पेश करने के ज़रिये, राजनीतिक संस्कृति के स्तर को ऊपर उठाने के तरीके ढूंढ़ने चाहियें। कम्युनिस्टों को कदम दर कदम तरीके से सभी लड़ाकू क्रांतिकारी ताकतों की विचारधारात्मक एकता के लिये भी काम करना चाहिये; सभी को

यह एहसास करवाना चाहिये कि सोच और कार्यवाही में एकजुटता ही, एकता का सबसे उच्चतम रूप है और यह समाज को संकट से निकालने के लिये एक अनिवार्य शर्त है। उनको, कार्यवाही में सभी ताकतों की एकता, एक राजनीतिक एकता भी कायम करनी चाहिये जो किसी भी प्रकार के विचारधारात्मक सोच से परे हो।

क्रांति के पीछे हटने को जारी रखने में, आत्मगत तत्व मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। कुछ ऐसे राजनीतिक संगठन हैं, जिनकी विचारधारा व राजनीति मज़दूर वर्ग व मेहनतकश लोगों की इस दुर्दशा के लिये दोषी है। हिन्दोस्तान के अंदर, क्रांति के पीछे हटने को जारी रखने में मदद कर रहा एक आत्मगत कारक यह है कि सबसे ताक़तवर कम्युनिस्ट पार्टियां और दल, क्रांतिकारी असूलों का त्याग कर रहे हैं और संर्कीणता अपना रहे हैं तथा क्रांतिकारियों के खिलाफ़ राज्य को सहयोग दे रहे हैं। एक और कारक उनके द्वारा अंतर-साम्राज्यवादी भू-राजनीति को समर्थन देना है। देश के अंदर राज्यतंत्र के साथ अपने सहयोग और भूमिका का विस्तार करके, उन्होंने क्रांति के खिलाफ़ विश्वासघातक कार्य किया है तथा एक ऐसे आत्मगत कारक बन गये हैं जिससे क्रांति के पीछे हटने में मदद हुई है।

लेकिन, बस इतना ही नहीं। क्रांति के उठाव के बीते दौर का फायदा मज़दूर वर्ग आंदोलन इसलिये नहीं उठा सका क्योंकि साम्राज्यवाद, वैश्विक सरमायदारी तथा प्रतिक्रियावाद लोगों के विद्रोह को अपने हित में इस्तेमाल करने में कामयाब रहे। दुनिया भर की कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों का सोशल-डेमोक्रेसी में पतन होना सरमायदारों की इस कामयाबी में सहायक बना। इसमें उन्होंने भी सहायता की जिन्होंने सोशल-डेमोक्रेसी के साथ समझौता कर लिया। यह विश्वासघात सोवियत संघ व उन अन्य देशों में शुरू हुआ, जिन्होंने बहुत समय पहले ही क्रांतिकारी मार्क्सवाद-लेनिनवाद को त्याग दिया था और अपने-अपने देशों में नकली समाजवादी समाज कायम कर लिया था।

सोवियत संघ तथा फासीवाद के खिलाफ़ संघर्ष करने वाले सभी लोग दूसरे विश्वयुद्ध से विजयी निकले। उपनिवेशवाद-विरोधी और साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जबकि अमरीकी साम्राज्यवाद ने कम्युनिज़्म का खात्मा कर देने का अडोल्फ हिटलर का चोगा धारण कर लिया था। निकिता ख्रुश्चेव तथा जे.बी. टीटो जैसे संशोधनवादियों और मौकापरस्तों ने, दूसरे विश्वयुद्ध के बाद सामाजिक जीवन की हालतों में आई अचानक और आश्चर्यजनक तब्दीली के जवाब में, क्रांति व समाजवाद की ज़रूरत को ही त्याग दिया।

शुरुआत के तौर पर, उन्होंने मार्क्सवाद-लेनिनवाद के क्रांतिकारी सिद्धांत पर सीधा हमला किया। क्रांति व समाजवाद के निर्माण के जारी कार्यों की ठोस समस्याओं पर मार्क्सवाद-लेनिनवाद को लागू करके इसे और समृद्ध बनाने की निरंतर ज़रूरत को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने यह भी बिल्कुल न सोचा कि ठोस परिस्थितियों द्वारा उछाली गई कुछ समस्याओं का समाधान करके, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धांत के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर करने और विकसित करने की ज़रूरत थी। उन्होंने मार्क्सवाद-लेनिनवाद को मात्र एक मुहावरा बना दिया और पूरे आंदोलन में कम्युनिज़्म के बारे में यह ख्वाब फैला दिया कि एक बार निर्मित किये जाने के बाद कम्युनिज़्म किसी बड़े झमेले के बगैर हमेशा के लिये कायम रहेगा। साम्राज्यवाद के बारे में भी ऐसे ही ख़तरनाक भ्रम फैलाये गये, कि यह अब "शांतिपूर्ण" बन गया है और अपने आप ही मिट जायेगा। उन्होंने सोशल-डेमोक्रेसी के साथ भी समझौता कर लिया। उन्होंने अमरीकी साम्राज्यवाद को लोगों पर हावी होने दिया, जो कि अडोल्फ हिटलर एक अत्यंत भयंकर युद्ध के द्वारा भी हासिल नहीं कर पाया था। उन्होंने, जीवन की हालतों में, खासकर अर्थव्यवस्था और राजनीति के क्षेत्र में, आई आश्चर्यजनक अचानक तब्दीली के फलस्वरूप मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धांत के सामने उत्पन्न हुई असली समस्याओं का समाधान करने के लिये कोई भी कदम नहीं उठाये। उन्होंने उस युग के सिद्धांत तथा निश्चित व्यवहारिक कार्यों के बीच कोई संबंध स्थापित करने से इनकार कर दिया।

बहुत ही घिनावने तरीके से, गपशप, अर्धसत्यों और खासकर अपने पद की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करते हुये, ख्रुश्चेव ने जे.वी. स्टालिन के व्यक्तित्व पर बहुत ही भयानक हमला किया। उसने स्टालिन के खिलाफ़ और क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ़ साम्राज्यवाद, सरमायदारी तथा वैश्विक प्रतिक्रियावाद के सभी आरोपों को दोहराया और इन्हें साख दी। ऐसा करके, उसने लोगों को यह बताया कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, खास कर उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद, हमला करना उसके व्यवहार का मूल्यांकन करने का एक जायज़ तरीका है। वस्तुगत और आत्मगत हालतों का विश्लेषण किये बगैर तथा सोवियत संघ और मार्क्सवाद-लेनिनवाद की समस्याओं का समाधान ढूंढ़े बगैर, ख्रुश्चेव ने समूचे माहौल को मिथ्यारोपण, परोक्ष संकेतों और सरमायदारी राजनीति के सबसे घटिया तरीकों से प्रदूषित कर दिया। किसी संगठन या व्यक्ति की, एक अच्छे या बुरे कम्युनिस्ट के तौर पर पहचान, इस आधार पर की जाने लगी कि क्या वह स्टालिन के व्यक्तित्व पर ख्रुश्चेव के हमले से सहमत था या नहीं। क्रांति व समाजवाद की समस्याओं का समाधान करने की बजाय, आंदोलन के अंदर चरित्र पर कीचड़ उछालने की पूंजीवादी, निम्न-पूंजीवादी तथा मौकापरस्त आदत प्रचलित कर दी गई।

इस तरह, सामाजिक जीवन की हालतों में आई आश्चर्यजनक अचानक तब्दीली से पैदा हुई क्रांतिकारी सिद्धांत की समस्याओं का हल करने की तरफ हरेक कम्युनिस्ट का ध्यान लगाने की फौरी ज़रूरत को सफलतापूर्वक नकार दिया गया। स्टालिन के जीवन व काम पर इस तरह हमला करके, पूरे आंदोलन के अंदर, गपशप और मिथ्यारोपण और वास्तविक दुनिया में कुछ असली प्रगति किये बगैर, सबसे नेक और लड़ाकू होने का स्वांग रचने की लापरवाह आदत की यह बीमारी फैला दी गई। ख्रुश्चेव ने द्वंद्वात्मक दर्शनशास्त्र को त्याग दिया और इसकी जगह पर बने-बनाये हठधर्मी बयानों की एक खिचड़ी को स्थापित किया।

ख्रुश्चेव ने, हाथ की सफाई से, मार्क्सवाद के मूल सिद्धांतों को भी त्याग दिया और इनके स्थान पर मार्क्सवाद-विरोधी बयानों का

सहारा लिया, जिनका सोवियत संघ के अंदर चल रहे जटिल संघर्ष का मार्गदर्शन करने तथा समाजवाद के विकास की समस्याओं का समाधान करने के साथ कोई वास्ता नहीं था। उसने मार्क्सवाद-लेनिनवाद के क्रांतिकारी सिद्धांत को, इसकी जीवन में मार्गदर्शक भूमिका से अलग कर दिया और स्टालिन पर हमले को एक तेज़ धार के तौर पर इस्तेमाल करके मार्क्सवाद-लेनिनवाद को बदनाम किया। उसने अर्थव्यवस्था में ठोस प्राबंधिक तकनीकों और कुशलता के इस्तेमाल की भूमिका को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और इस तरह, एकतरफा तौर पर वस्तुगत कारक को प्रधानता दी। "उन्नत समाजवाद" और "उत्पादन-सूचकांकों" के नारों के तहत उत्पादन के पुराने संबंध पुनर्स्थापित कर दिये गये। अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीति तथा संस्कृति के सभी क्षेत्रों में, श्रमजीवी अधिनायकत्व की नियामक भूमिका के स्थान पर जल्द ही उत्पादन की अराजकता फैल गई।

समाजवादी योजनाबंदी का संबंध, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मात्र उत्पादन के लक्ष्य तय करने के साथ ही नहीं है। इसमें मुख्य कार्य अर्थव्यवस्था, राजनीति तथा संस्कृति के संचालन में जनसमुदाय की भूमिका को बढ़ाने का कार्य है, यानी कि उत्पादन के संबंधों को निरंतर और अधिक क्रांतिकारी बनाने का कार्य। समाजवादी योजना के एकमात्र मार्गदर्शक उद्देश्य बतौर, उत्पादन के संबंधों को लगातार और क्रांतिकारी करना मुमकिन नहीं है अगर समाजवादी व्यवस्था के अंदर लोग अपने व्यक्तिगत हितों को सामूहिक हितों के साथ सामंजस्य में लाने तथा व्यक्तिगत व सामूहिक हितों को समाज के आम हितों के साथ सामंजस्य में लाने के आधार पर, अपने हितों के लिये संघर्ष नहीं करते। ऐसी समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब क्रांतिकारी सिद्धांत को अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति का सामना करने वाली हालतों के स्तर तक विकसित किया जाये।

आर्थिक सिद्धांत के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, वितरण समेत हरेक चीज़ को निर्धारित करने में मेहनतकश लोगों की भूमिका को अव्वल

दर्जे पर स्थापित करने की ज़रूरत थी। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में, राजनीतिक तंत्र के क्रांतिकारीकरण की ज़रूरत थी, ताकि लोग खुद अपना शासन करने में सीधे तौर पर भाग ले सकें। द्वंद्वात्मक दर्शनशास्त्र के अनुसार "इस प्रकार के दृष्टिकोण का रूढ़ीवाद तुलनात्मक है; इसका क्रांतिकारी स्वभाव अपरिवर्तनशील है और द्वंद्वात्मक दर्शनशास्त्र इसी एकमात्र अपरिवर्तनशीलता को मानता है"। दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में, यह ज़रूरत थी कि इस द्वंद्वात्मक दर्शनशास्त्र की भूमिका को समाजवादी जीवन के केंद्र में लाकर सीधे तौर पर स्थापित किया जाये, और सभी गतिविधियों में मानवीय तत्व और जागृति की अग्रगामी भूमिका हो।

लेनिन ने मार्क्सवादियों को संकेत दिया था और उन्हें बुलावा दिया था कि "अपने क्रांतिकारी विज्ञान के अंदर हठधर्म भरकर इसे मात्र एक किताबी सिद्धांत के स्तर तक नहीं गिराओ"। परन्तु ख्रुश्चेव के लिये यह दिशा-निर्देश कोई मायना नहीं रखता था। उसने बहुत से ऐसे मनगढ़ंत "सिद्धांत" बना लिये, जो सोवियत लोगों के जीवन के साथ बिल्कुल कोई नाता नहीं रखते थे। इन सिद्धांतों का उद्देश्य क्रांतिकारी सिद्धांत की समस्याओं और सोवियत संघ के अंदर तथा अंतरराष्ट्रीय तौर पर क्रांति और समाजवाद को पेश आ रही कठिनाइयों को हल करने की उसकी (ख्रुश्चेव की) अयोग्यता व अनिच्छा को छुपाना था। उसने मार्क्सवाद के कार्यक्रम और निष्कर्षों को ऊटपटांग रूप दे दिया।

श्रमजीवी सत्ता बतौर श्रमजीवी अधिनायकत्व, जिसमें मेहनतकश लोग खुद अपना शासन चलाना शुरू करते हैं, उसकी बजाय, ख्रुश्चेव ने "सभी लोगों के राज्य" की रट लगा दी। कम्युनिस्टों के गुण तथा कम्युनिस्ट पार्टी के श्रमजीवी क्रांतिकारी चरित्र को निरंतर बेहतर बनाने की बजाय, ख्रुश्चेव ने "सभी लोगों की पार्टी" स्थापित कर दी। अंतरराष्ट्रीय मज़दूर वर्ग द्वारा दुनिया के क्रांतिकारी परिवर्तन के लिये अपनी मांगें उठाने की बजाय, ख्रुश्चेव ने इस युग की उच्चतम कामयाबी बतौर "शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व" का नारा लगाया। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह किस किस्म की कम्युनिस्ट पार्टी रही होगी, और किस किस्म के कम्युनिस्ट ऐसी पार्टी

में सक्रिय रहे होंगे – "सभी लोगों की पार्टी के" ये कम्युनिस्ट, साम्राज्यवाद के साथ "शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व" बनाये रखने वाले "सभी लोगों के राज्य" की कम्युनिस्ट पार्टी के ये कम्युनिस्ट कैसे रहे होंगे।

इस वक्त, क्रांति के पीछे हटने के इस दौर में, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के कार्यक्रम तथा निष्कर्षों पर, दो तरफ से हमले किये जा रहे हैं। एक तरफ से दक्षिणपंथी हमला कर रहे हैं, जिन्होंने क्रांति की सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं तथा जो अपने-आप को निजीकरण व उदारीकरण की वैश्विक सरमायदारी की मांगों के अनुकूल ढाल रहे हैं। दूसरी तरफ से वाम पक्ष हमला कर रहा है, जो मार्क्सवाद को इसके सारतत्व, यानी द्वंद्वात्मक दर्शनशास्त्र से ही वंचित कर रहा है। वाम पक्ष भी दक्षिणपंथियों की तरह ही सक्रिय है। वाम पक्ष सामाजिक जीवन में हाल में आयी आश्चर्यजनक अचानक तब्दीलियों का विश्लेषण करने से बचने के लिये पुराने बयानों का सहारा ले रहा है। दक्षिणपंथी और वाम पक्ष, दोनों बीते समय की पूजा के पंडाल के शोर-शराबे में आपस में गले मिलते हैं, ताकि वर्तमान से निपटने की अपनी नाकामयाबी और अनिच्छा को पूजनीय बनाया जा सके। वे यह मानने से इनकार करते हैं कि कम्युनिस्ट आंदोलन एक ही है, जिसको मुख्य ख़तरा उन सभी से है जो सोशल-डेमोक्रेसी के साथ समझौता कर रहे हैं।

क्रांति के पीछे हटने के इस दौर की सबसे पहली मांग है कि इस युग के निश्चित व्यवहारिक कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला जाये। दूसरी मांग है कि मार्क्सवाद की नीवों को दृढ़ता के साथ लगातार बुलंद किया जाये, यानी कि समकालीन मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा और मार्क्सवाद के कार्यक्रम व निष्कर्षों को बुलंद किया जाये। इन दो मौलिक सिद्धांतों के प्रति वफादार रहने के लिये, सभी हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों के सामने सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक काम यह है कि उन्हें, बाकी सभी चिंताओं को एक तरफ रखकर, सिद्धांत को विकसित करने के, आम कार्यदिशा को स्थापित करने, लोगों की राजनीतिक एकता बनाने और समाज को संकट से बाहर निकालने के काम में लग जाना

चाहिये। इस कार्य को अंजाम देने के दौरान हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों की एकता का निर्माण होगा और हिन्दोस्तान की धरती पर मज़दूर वर्ग की एक ही अगुवा हिरावल पार्टी का उदय होगा। ऐसा सुनिश्चित करना ही, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का फौरी कार्य है।

हम भली-भांती जानते हैं कि मात्र यह उम्मीद करना कि, यह या वह पार्टी क्रांति की मशाल को जलाये रखेगी, यानी कि हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी इस मशाल को जलाये रखेगी, यह सिद्धांत को विस्तारपूर्वक पेश करने, आम कार्यदिशा तय करने, लोगों की राजनीतिक एकता का निर्माण करने तथा समाज को संकट से निकालने के कार्य के प्रति उदासीनता को जन्म देता है। इसके अलावा, यह कम्युनिस्टों के भीतर बंटवारों को गहरा करता है और राजनीतिक एकता का रास्ता रोक देता है। इससे हम पार्टी को खत्म करने के दबाव तले आ जाते हैं। 1962-64 की अवधि में, जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के भीतर फूट अनिवार्य बन गई थी, उसके बाद के करीब तीन दशकों की अवधि में, विभिन्न किस्म के कम्युनिस्टों ने, हजारों तरह के भटकावकारी कार्य किये हैं। उस समय, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर फूट पड़ने की वजह ही यह थी कि उन हालतों के अंदर कम्युनिस्ट आंदोलन को क्रांति की समस्याओं के साथ निपटने के मार्ग से भटका दिया गया था।

जिन्होंने उस फूट को अंजाम दिया था, उनसे पूछा जाना चाहिये कि उन्होंने ऐसा करके क्या हासिल किया। इस निर्णायक प्रश्न के बारे में स्पष्टता पेश करके, वे क्रांति के पीछे हटने के इस दौर में कम्युनिस्टों की एकता का निर्माण करने में योगदान दे सकते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (माकपा) के नेतृत्व को सबसे ज्यादा स्पष्टीकरण देना होगा, जो इन वर्तमान हालतों में भी इस सवाल का जवाब देने से बचने की कोशिश कर रहा है और घमंडी तथा संर्कीणतावादी ढंग से व्यवहार कर रहा है। उनसे मांग की जानी चाहिये कि वे, वर्तमान हालतों का विश्लेषण करके और अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोणों व आम कार्यदिशा पर प्रकाश डालकर, फूट के परिणामों को समझायें और इस तरह से लोगों

की राजनीतिक एकता बनाने में योगदान दें। उन्हें ऊपर से एकता बनाने के घिसे-पिटे दावपेंचों को त्याग देना चाहिये, जैसे कि तीसरे मोर्चे के चुनाव कार्यक्रम में किया गया है तथा बीते समय में वे हमेशा करते आये हैं। उन्हें अपना यह घिसा-पिटा राग अलापना भी बंद कर देना चाहिये जिसके मुताबिक मज़दूर वर्ग को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मज़दूरों द्वारा अपनी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिये परिस्थितियां अभी मौजूद नहीं हैं।

सबसे निर्णायक कार्य सभी मज़दूरों व मध्यम तबकों की राजनीतिक एकता बनाना है – उन सभी की राजनीतिक एकता जो वर्तमान हालतों का विरोध करते हैं, खासकर शासन व्यवस्था के अपराधीकरण का; लोगों को दबाने व हिंसा की रीति को कायम करने में सेना तथा सुरक्षा बलों की भूमिका का; राजकीय आतंकवाद के प्रयोग का; लोगों की सभी आज़ादियों पर किये जा रहे हमलों का विरोध करते हैं, और इससे भी अहम, जो मज़दूरों और सभी मेहनतकश लोगों के आर्थिक कल्याण के पक्ष में हैं। इस या उस असूल के प्रति, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के क्लासिकी ग्रंथों में से इस या उस मुहावरे के प्रति वफादारी की घोषणा करना और लोगों की सारी वस्तुगत व आत्मगत हालतों से समाधान को तलाशने के बगैर, ऐसी घोषणा करना प्रगति में बिल्कुल योगदान नहीं देगा।

साथियों, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी, क्रांति के पीछे हटने को क्रांति का अंत नहीं मानती है। मार्क्सवाद का सिद्धांत आज भी उतना ही उपयुक्त है, जितना कि यह मार्क्स द्वारा खोजे जाने के समय था। क्रांति के पीछे हटने का मतलब यह नहीं है कि इस युग के मुख्य अंतर्विरोध लुप्त हो गये हैं। यह युग, आज भी साम्राज्यवाद तथा श्रमजीवी क्रांति का युग है, जैसे कि लेनिन ने इसे परिभाषित किया था। फिर भी अभ्यास के मार्ग को रोशन करने के लिये, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धांत को विकसित करने की ज़रूरत है, इसकी पुनः जांच करनी होगी और इसे तरो-ताजा बनाना होगा, क्योंकि इतिहास का बहाव, वस्तुओं व संबंधों में

निरंतर परिवर्तन, नये अनुभवों और नयी खोजों को जन्म देते हैं। हमें नयी परिभाषायें विकसित करनी होंगी जो इस वक्त सामाजिक प्रगति की ज़रूरतों के अनुकूल हों।

हिन्दोस्तान, इस धरती पर सबसे विशाल आबादी वाले देशों में से एक है। इसके पास क्रांतिकारी परंपराओं का एक बड़ा खजाना है, जो कि ज्ञान के उदय के लिये तथा कम्युनिस्ट विचारों के फलने-फूलने के लिये एक उपजाऊ भूमि है। इसके साथ-साथ, जनता पर थोपी गई गुरबत तथा पिछड़ेपन की हालतें, कम्युनिस्टों को इस युग की ज़रूरतों के अनुकूल अपनी एकता की पुनर्स्थापना करने के लिये प्रेरित करती हैं। हिन्दोस्तान के लिये, यह इतिहास का अंत नहीं है बल्कि, आधुनिक मायनों में, इसका प्रारंभ है। हिन्दोस्तान की ठोस हालतों के अंतर्गत कार्य करने के दौरान, कम्युनिस्ट ही इतिहास रचेंगे, वह इतिहास जो समाज की प्रगति का रास्ता खोलेगा। लोगों के लिये किसी भी दूसरे पर आशा रखना फिजूल होगा, क्योंकि मज़दूर वर्ग ही सबसे संपूर्णतया क्रांतिकारी वर्ग है, और कम्युनिज़्म मज़दूर वर्ग के संपूर्ण उद्धार की शर्त है। किसी भी भटकाव से कुशलतापूर्वक दूर रहते हुये, कम्युनिस्टों को वस्तुगत तौर पर उपलब्ध प्रत्येक ताकत को समाज की प्रगति के लिये इस्तेमाल करना होगा, और ऐसा सुनिश्चित करने के लिये, अपने सिद्धांत में से प्रत्येक चीज़ का इस्तेमाल करना होगा।

दुनियाभर के कम्युनिस्ट, अपनी वस्तुगत व आत्मगत हालतों का मूल्यांकन कर रहे हैं और हिन्दोस्तान के कम्युनिस्ट इस कार्य में एक दस्ता हैं। इस मूल्यांकन के बगैर, हिन्दोस्तान और दुनियाभर में आवश्यक गहरे क्रांतिकारी परिवर्तनों को लाना नामुमकिन है। हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट, अंतरराष्ट्रीय मज़दूर वर्ग की मुक्ति के आंदोलन का एक अनिवार्य दस्ता तब बनेंगे जब वे हिन्दोस्तान के अंदर अपना कार्य निभायेंगे और पूरी दुनिया में इसी कार्य का समर्थन करेंगे। हर एक जगह पर इसी संघर्ष की हिमायत करने की संकल्पना ही श्रमजीवी अंतरराष्ट्रीयतावाद का मूल आधार है।

भाग 2

सोशल-डेमोक्रेसी के साथ समझौता करने वालों के खिलाफ़ संघर्ष को अंत तक ले जाना

साथियों,

जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत, इसके द्वारा यूरोपीय सोशल-डेमाक्रेसी के साथ पूरी तरह नाता तोड़ने से हुई थी। इस बंटवारे की शुरुआत दूसरी इंटरनेशनल के अंदर, इस प्रश्न से हुई थी कि अंतर-साम्राज्यवादी युद्ध के प्रति तथा सरमायदारों को युद्ध के लिये कर्जे दिये जाने के प्रति, समाजवादियों को क्या रुख़ अपनाना चाहिये। यह खाई बढ़ती ही गई, और 1917 में महान अक्तूबर क्रांति के समय तक यह स्पष्ट हो गया था कि दूसरी इंटरनेशनल ने मार्क्सवाद के संपूर्ण कार्यक्रम तथा निष्कर्षों को पूरी तरह से तिलांजली दे दी थी।

तीसरी इंटरनेशनल का इतिहास, क्रांति तथा समाजवाद के दुश्मनों की सभी तोड़-मरोड़ों के खिलाफ़, मार्क्सवादी कार्यक्रम और इसके निष्कर्षों की हिफाज़त करने का इतिहास है। यह, एक तरफ सोशल-डेमोक्रेसी के साथ समझौता करने वाले सभी का विरोध करने, और दूसरी तरफ, मार्क्सवाद-लेनिनवाद की शुद्धता की हिफाज़त करने का इतिहास है। उसके बाद, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कई पार्टियों ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद को त्याग दिया और सोशल-डेमोक्रेसी के साथ समझौता किया। यही मज़दूर वर्ग, क्रांति तथा समाजवाद के लक्ष्य को वर्तमान में हुये इस भारी नुकसान का कारण बना है। इसी विचारधारात्मक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक निष्कर्ष की हिफाज़त करना ज़रूरी है। यह हिफाज़त हठधर्मी तौर से नहीं, बल्कि दुनिया में आई बड़ी अचानक तब्दीलियों को ध्यान में रखते हुये की जानी चाहिये।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी ने अपनी स्थापना के वक्त, मार्क्सवाद-लेनिनवाद को अपनी सैद्धांतिक सोच का आधार और हिन्दोस्तान में लोक जनवादी क्रांति को अंजाम देने के लिये मार्गदर्शक माना था। उस वक्त कम्युनिस्ट आंदोलन को मुख्य ख़तरा, राजसत्ताधारी आधुनिक संशोधनवाद के विभिन्न रूपों से, खासकर सोवियत संशोधनवाद से था। इन हालतों में, खासकर सोवियत संघ के सिद्धांत व अभ्यास के प्रश्नों के बारे में, आधुनिक संशोधनवाद और इसके सभी रूपों का विरोध करके, और विश्व के दो-ध्रुवीय बंटवारे की हालतों में क्रांति के कार्यों की परिभाषा देकर, मार्क्सवाद-लेनिनवाद की शुद्धता की हिफाज़त की गई थी।

उस वक्त के बाद विश्व के अंदर बड़ी और अचानक तब्दीलियां हुई हैं। न सिर्फ विश्व का दो-ध्रुवीय बंटवारा ही खत्म हो गया है, बल्कि बहुत सी कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपने नाम तक बदल लिये हैं, और उन्होंने सरेआम तथा बड़ी बेशर्मी के साथ सोशल-डेमोक्रेसी को अपना लिया है, जैसा कि सोस्लिस्ट पार्टी ऑफ अल्बेनिया ने किया है। सोवियत संघ का विनाश, रूसी संघ तथा कंफेडेरेशन ऑफ इंडिपेंडेन्ट स्टेट्स (सी.आई.एस.) के अन्य राज्यों के अंदर समाजवाद के आधार तथा ऊपरी ढांचे को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना, और साम्राज्यवादियों द्वारा बताये गये "मुक्त बाज़ार" तथा बहुपार्टीवादी लोकतंत्र को सरेआम अपनाया जाना, एक सत्य है। इसके साथ ही सोवियत संशोधनवाद का पुराना रूप भी नष्ट कर दिया गया है क्योंकि उस संशोधनवाद ने समाजवाद का विनाश करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था।

इन अचानक तब्दीलियों के बाद की आत्मगत तथा वस्तुगत हालतों की छान-बीन करके, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि विचारधारात्मक संघर्ष का मूलतत्व भी बदल गया है। वह अब 1980 वाला मूलतत्व नहीं रहा, जब हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की स्थापना की गई थी। आज, कम्युनिस्ट आंदोलन के लिये सबसे बड़ा खतरा सोवियत संशोधनवाद या आधुनिक संशोधनवाद के अन्य रूपों से नहीं है जैसा कि पिछले चार

दशकों में था। आधुनिक संशोधनवाद, जिसने बीते समय में कम्युनिस्ट आंदोलन में बंटवारा कर रखा था, वह आज खत्म हो गया है। अब जब तूफान थम गया है, जो लोग अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं और जिन्होंने कम्युनिज़्म के लक्ष्य का सरेआम त्याग नहीं किया है, वे सभी एक ही कम्युनिस्ट आंदोलन का अंग हैं।

इस कम्युनिस्ट आंदोलन को खतरा कहां से है? जब अमरीकी साम्राज्यवाद अपने प्रभुत्व तले एक-ध्रुवीय विश्व बनाने का प्रयास कर रहा है, तथा अन्य ताकतें बहु-ध्रुवीय विश्व बनाने का प्रयास कर रही हैं तथा वैश्विक पूंजीवाद विचारधारात्मक हमले कर रहा है और दावा कर रहा है कि मानव सभ्यता के विकास में पूंजीवाद ही अंतिम पड़ाव है, इन हालातों में, इस एक कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर कुछ ऐसे भी हैं जो सोशल-डेमोक्रेसी के साथ समझौता कर रहे हैं और पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद के बारे में भ्रम पैदा कर रहे हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन को मुख्य खतरा इस तरह की ताकतों से ही है। इसीलिये आज, विचारधारात्मक संघर्ष का मूलतत्व, एक तरफ, सोशल-डेमोक्रेसी के साथ समझौता करने वालों के खिलाफ़, तथा दूसरी तरफ, समकालीन मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा और मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सभी असूलों की हिफ़ाज़त के लिये संघर्ष है।

इस समय विचारधारात्मक संघर्ष के मूलतत्व का एक नकारात्मक बढ़िया उदाहरण, रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपनाये गये कार्यक्रम से मिलता है, जिसने रूस में दिसंबर 1995 में हुये चुनाव में डूमा के अंदर तकरीबन एक-तिहाई सीटें जीती हैं। यह कार्यक्रम सोशल-डेमोक्रेसी के साथ पूरे समझौते का कार्यक्रम है। रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में, हमारे द्वंद्वात्मक दर्शनशास्त्र के क्रांतिकारी तत्व, यानी कि इसके हृदय, इसके परम अंग को ही हटा दिया गया है, जिसके बगैर हमारा दर्शनशास्त्र महज एक बेजान, संकलक खिचड़ी बनकर रह जाता है। इस कार्यक्रम पर एक सरसरी नज़र दिखा देगी कि यह एक पूरा सोशल-डेमोक्रेटिक कार्यक्रम है।

न्यूज़ ऐजेंसियों की रिपोर्टों के मुताबिक, "इस (रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी) की नीति के मुख्य विषय डूमा के चुनाव से पहले, इसके नेताओं द्वारा तथा प्रकाशित किये गये दस्तावेज़ों में रेखांकित किये गये थे ... कम्युनिस्ट, रूस में दो साल पहले अपनाये गये संविधान की नुक्ताचीनी करते हुये, एक नया बुनियादी कानून लाना चाहते हैं जो 'मेहनतकश जनता के लिये सत्ता' को सुनिश्चित करे; तथा वे रूस की सरकार की राष्ट्रपति व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जिसने कि, उनके मुताबिक, एक 'अर्ध-नवाबी व्यवस्था' कायम कर दी है।" उनके द्वारा प्रस्तावित की गई यह तब्दीली सिर्फ बाहरी रूप में है और सारतत्व में नहीं। संविधान, विजयी क्रांतियों द्वारा लिखे जाते हैं और वे एक नये सारतत्व को दर्शाते हैं। रूस के संविधान में "मेहनतकश जनता के लिये सत्ता" लिखा जाये या नहीं, सत्ता सरमायदारों के हाथों में ही रहेगी, जब तक कि मज़दूर वर्ग एक विजयी क्रांति के ज़रिये पूंजीवाद का तख्ता पलट कर खुद सत्ता पर कब्ज़ा नहीं कर लेता। रूस बेशक राष्ट्रपति ढंग की व्यवस्था को त्याग कर किसी अन्य किस्म की व्यवस्था, मान लो कि हिन्दोस्तान में मौजूद व्यवस्था जैसी एक व्यवस्था अपना लेता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि, उस हालत में, सत्ता कार्यकारिणी के हाथों में ही संकेंद्रित रहेगी, यानी कि, राष्ट्रपति और मंत्रीमंडल की बजाय प्रधानमंत्री और मंत्रीमंडल में संकेंद्रित रहेगी।

न्यूज़ एजेंसियां आगे बताती हैं कि "डूमा के चुनावों से काफी समय पहले अपनाया गया एक घोषणापत्र कहता है कि रूस के भविष्य का फैसला अवश्य ही लोगों के हाथों में होना चाहिये, तथा यह एक पुराने लेनिनवादी नारे को पुनर्जीवित करता है : 'जो काम नहीं करता, वह खायेगा भी नहीं'। परन्तु पार्टी यह स्पष्ट कहती है कि वेतन काम पर निर्भर होंगे, न कि विचारधारा पर। 'लोग ईमानदारी के साथ काम करेंगे तथा अपने श्रम की मात्रा और गुणवत्ता के अनुसार कमायेंगे। शिक्षक, डाक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, चित्रकार, लेखक तथा खिलाड़ी फिर से महसूस करेंगे कि समाज को उनकी ज़रूरत है'।" परन्तु, इस कार्यक्रम के अंदर कहीं भी पूंजीवाद का तख्ता पलटने और समाजवादी समाज की पुनः स्थापना

करने का जिक्र नहीं है। जब उत्पादन का उद्देश्य अधिकतम पूंजीवादी मुनाफ़ा बनाना है तो लोग "ईमानदारी के साथ काम तथा अपनी श्रम की मात्रा व गुणवत्ता के मुताबिक कमाई" कैसे कर सकते हैं? यह, "दिन के उचित काम के लिये, दिन के उचित वेतन" के 19वीं सदी वाले पुराने एक सोशल-डेमोक्रेटिक नारे से भिन्न नहीं है।

विदेश नीति में, रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने श्रमजीवी अंतरराष्ट्रीयतावाद को पूरी तरह से त्याग दिया है, और इसके स्थान पर "पितृभूमि की सुरक्षा" को अपना लिया है। उपरोक्त खबर एजेंसियों के ही मुताबिक, यह पार्टी "एक ताकतवर राज्य चाहती है, रूस, यूक्रेन और बेलारूस के बीच उस समझौते को रद्द करना चाहती है, जिस समझौते के ज़रिये सोवियत संघ को भंग किया गया था, और महाशक्ति बतौर रूस की पुनर्स्थापना के बारे में एक जनमत संग्रह करवाना चाहती है। वह रूस की सीमाओं के बाहर फंसे हुये दो करोड़ पचास लाख रूसियों की हालत सुधारने के लिये दृढ़ संकल्प है और वह कहती है कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुवानिया जैसे बाल्टिक राज्यों के साथ संबंध कुछ हद तक इस बात पर निर्भर होंगे कि वे अपने रूसी नागरिकों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। कम्युनिस्ट नहीं चाहते कि नाटो अपनी सीमाओं को और विस्तृत करके वॉर्सा संधि के भूतपूर्व देशों को अपने अंदर शामिल करे।" दूसरे शब्दों में, कनफेडेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अन्य सदस्यों के प्रति रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का रुख़ महारूसी उग्रराष्ट्रवाद से प्रेरित है। इसी तरह से इसका, नाटो के विस्तार के प्रति विरोध भी उग्रराष्ट्रवादी नज़रिये से ही है और यह अपने लिये सैन्य गठबंधनों को बनाने की रूस की इच्छा पर आधारित है।

अपनी आर्थिक नीति में, रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी, पूंजीवादी व्यवस्था को जारी रखेगी और इसमें तब्दीलियों की मांग उठायेगी, इस उम्मीद के साथ कि पुराना सोशल-डेमोक्रेटिक कल्याणकारी राज्य उसकी समस्याओं का समाधान कर देगा : "कम्युनिस्ट पार्टी ने बीते समय के कुछ कट्टरपंथी विचारों का खंडन किया है और अब एक तरह की

मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है"। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में "बीते समय के ये कट्टरपंथी विचार" कौन से हैं? राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक 'कट्टरपंथी' विचार, उत्पादन के साधनों की मालिकी में तथा उत्पादन के उद्देश्यों में, श्रमजीवी अधिनायकत्व को अमल में लाने का विचार है। ऐसा कहने का मतलब है कि नींव पर संबंधों के तत्व को, रूस की विद्रोही श्रमजीवी जनता की सशस्त्र ताकत के प्रयोग से, पूंजीवाद से समाजवाद में बदल देना होगा। यही मुख्य "कट्टरपंथी" विचार है, जिसे रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने त्याग दिया है।

क्रांति के ज़रिये समाजवादी समाज स्थापित करने का यह विचार त्याग देने के उपरान्त रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी, अब एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि हिन्दोस्तान में इस वक्त मौजूद किस्म कि अर्थव्यवस्था की पुष्टि कर रही है, जिसका हिन्दोस्तानी मज़दूर वर्ग को लम्बा अनुभव है। इसे राजकीय इजारेदार पूंजीवादी व्यवस्था कहा जाता है, जो अधिकतर विकसित पूंजीवादी देशों में भी मौजूद है। मज़दूर वर्ग के लक्ष्य के साथ इस संपूर्ण गद्दारी के बाद, रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी बहुत भटकाऊ शोर मचाना शुरू करती है, जैसे कि यह ऐलान करती है कि "रक्षा, ऊर्जा, परिवहन तथा प्रौद्योगिकी जैसे उद्योग राज्य के हाथों में रहने चाहिये, जिसका मतलब सरकार की निजीकरण की नीतियों को बदलने का हो सकता है।" वह कहती है कि "राजकीय संपत्तियों का बेचा जाना, आने वाली पीढ़ियों को उनके अधिकारों से वंचित करता है।" पार्टी ने कहा है कि 'गैरकानूनी तरीकों से निजीकृत की गयी कंपनियों' को वापस लोगों के हवाले कर दिया जाना चाहिये, तथा वे निजीकरण के सौदे जो रूस के हितों की पूर्ति नहीं करते, उन्हें रद्द कर दिया जाना चाहिये। लेकिन इस पार्टी ने यह नहीं बताया कि इसका जायजा कैसे लिया जायेगा कि कौन से सौदे रूस के हित में हैं और कौन से नहीं। कम्युनिस्ट कीमतों में सब्सिडी देना चाहते हैं और गिरते हुए उत्पादन में जान फूंकने के लिये पूंजी निवेश को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ, निवेश के लिये भारी ज़रूरत को देखते हुये और चीन द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने की उसकी कामयाबी की बराबरी

करने के लिये, "पश्चिमी पूंजीनिवेश को प्रोत्साहन" देना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी, एक ऐसा आधुनिक पूंजीवादी समाज बनाना चाहती है जो विकसित हो और एक साम्राज्यवादी शक्ति हो। यह कीमतों में सब्सिडी देना चाहती है ताकि इज़ारेदार पूंजीपति अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के अंदर मुकाबले में स्वयं कोई भी जोखिम उठाये बगैर, अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। यह पार्टी, पूंजीपतियों के फायदे के लिये विदेशी पूंजी तलाश रही है।

इसकी सामाजिक नीति यह है : "पार्टी, यह शिकायत करते हुये कि लाखों रूसी लोगों ने दर्दनाक आर्थिक सुधारों की मार झेली है, अब पारिवारिक भत्तों तथा न्यूनतम वेतन बढ़ाना चाहती है और पेंशन भोगियों, परिवारों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांगों को अधिक मदद देना चाहती है। वह मुफ्त शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा और सस्ते आवासों की गारंटी देना चाहती है। वह रूसी लोगों द्वारा, सोवियत दिनों में जमा की गई बचतों, जिन्हें महंगाई निगल गई है, उसके लिये मुआवज़ा देना चाहती है और बेरोज़गारी खत्म करना चाहती है।" यह सब कुछ वह कैसे हासिल करेगी? क्या यह सब कुछ, पूंजीवाद का तख्तापलट किये बगैर हासिल किये जा सकते हैं? नहीं! ये हासिल नहीं किये जा सकते हैं। सिर्फ सोशल-डेमोक्रेसी के नमूने का एक सामाजिक कल्याणकारी राज्य बनाकर इन्हें हासिल करने का दिखावा किया जा सकता है। ऐसा हिन्दोस्तान के अंदर भी किया जाता है। यहां सरकार नियमित तौर पर, आबादी के इस या उस तबके को सब्सीडी, दोपहर का भोजन और हजारों ही अन्य ऐसी योजनाओं के ज़रिये, खैरात बांटती है। चूंकि पूंजीवाद का तख्तापलट नहीं किया गया है, अतः इसका अर्थ यह है कि मेहनतकश लोगों का शोषण और भी तीव्र कर दिया जाता है, और इज़ारेदार पूंजीपति वर्ग, करों में बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति तथा घाटे वाले बजटों के ज़रिये पूरे समाज से इसकी वसूली करता है और "समाज कल्याण" से भी मुनाफ़े कमाता है। रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने पूंजीवाद का तख्ता पलट करने का रास्ता त्याग दिया है, और अब वह सोशल-डेमोक्रेटिक रास्ते पर चलने के लिये दृढ़ संकल्प है, जिस रास्ते पर हम हिन्दोस्तान के अंदर इंडियन

नेशनल कांग्रेस तथा अन्य को लंबे अर्से से चलते हुये देखते आ रहे हैं। दरअसल, रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का यह दावा कि यह सब कुछ पूंजीवाद का तख्तापलट और पूंजीपति वर्ग का संपत्तिहरण किये बगैर ही हासिल हो सकता है, यह महज़ कपटी और सोशल-डेमोक्रेटों वाला चुनावी प्रचार है।

इस पूरे कार्यक्रम में, ऐसी कोई भी चीज़ बिल्कुल नहीं है, जो रूसी समाज को उस घोर संकट से निकाल सके जिसमें आज ये फंसा हुआ है। एक सामाजिक कल्याणकारी राज्य की यह वर्तमान-से-असंगत धारणा, एक ऐसी युक्ति है जो यह सुनिश्चित करती है कि मज़दूर वर्ग मौजूदा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय हालातों के अंदर से एक कार्यक्रम की न तो खोज-पड़ताल करे और न ही इसका विस्तार करे। एक कल्याणकारी राज्य की यह धारणा सुनिश्चित करती है कि मज़दूर वर्ग हरेक चीज़ को महज एक नीतिगत उद्देश्य बना देने के जाल में फंसा रहे और कभी भी एक ऐसा क्रांतिकारी कार्यक्रम प्रस्तुत न करे, जो उसके हितों कि गारंटी देता हो। अगर रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के इस कार्यक्रम को लागू किया जाता है, तो रूसी संघ एक साम्राज्यवादी राज्य बना रहेगा, तथा अपने स्वार्थी हितों के आधार पर सभी साम्राज्यवादी राज्यों से टक्कर लेता रहेगा। बोरिस येल्तसिन के राज्य का भी यही मुख्य तत्व है। पूंजीवादी येल्तसिन और कम्युनिस्ट ज्युगानोव के बीच कोई भी बुनियादी अंतर नज़र नहीं आता।

जब पूंजीवाद अपने अंतिम पड़ाव, साम्राज्यवाद में विकसित हुआ तो सोशल-डेमोक्रेसी, यूरोपीय सरमायदारी राष्ट्रीय राज्य की हिफ़ाज़त करने के लिये और वैश्विक पैमाने पर इसी राष्ट्रीय राज्य के पूंजीवाद के प्रसार के लिये, आगे आयी। सोशल-डेमोक्रेसी, श्रमजीवी क्रांति लाने और श्रमजीवी अधिनायकत्व स्थापित करने की 20वीं सदी की चुनौती से उस वक्त मुंह मोड़ गई, जब पूंजीवाद अपने अंतिम चरण, साम्राज्यवाद के पड़ाव पर पहुंच गया था। रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी बिल्कुल यही किया है। वह, एक नयी श्रमजीवी क्रांति तथा

श्रमजीवी अधिनायकत्व आयोजित करने की चुनौती से भाग गई है, और एक रूसी सामाजिक कल्याणकारी राज्य की तथा रूसी साम्राज्यवाद की पार्टी बन गई है।

सोशल-डेमोक्रेसी, बर्तानवी उपनिवेशवाद के काल में, हिन्दोस्तान में लाई गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिन्दोस्तान में पहली सोशल-डेमोक्रेटिक पार्टी थी। इसका कार्यक्रम स्वतंत्रता लाने का तो था, परन्तु सामाजिक क्रांति के बगैर। यह हिन्दोस्तानी उप-महाद्वीप पर शासन करने का अधिकार चाहती थी, परन्तु आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था में तब्दीलियां किये बगैर। 1950 के दशक के आखिरी वर्षों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, हिन्दोस्तान के लिये दिया गया "गैर-पूंजीवादी विकास" का नारा भी सोशल-डेमोक्रेसी के प्रति जी-हजूरी व उसकी वकालत था, जो सोशल-डेमोक्रेसी उस समय हिन्दोस्तान में नेहरू के "समाजवादी नमूने के समाज" के रूप में मौजूद थी। उपनिवेशवादियों ने ऐसे वर्गों को पैदा किया जिनके हित में उपनिवेशवादी व्यवस्था की हिफाज़त करना था। उन हालातों में तरह-तरह के समाजवादी पंथ पैदा हुये, जिनमें सोशल-डेमोक्रेसी को हमेशा अपने मित्र मिल गये। यही हालत इस वक्त हिन्दोस्तान में मौजूद है।

सोशल-डेमोक्रेसी की राजनीतिक कार्यदिशा, जो इस वक्त दुनिया के इतने सारे देशों में फैल गई है, का असली उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, यह सुनिश्चित करना है कि सभी देशों के मज़दूर अपने-अपने देशों की हालातों की जांच न करें, अपने दर्शनशास्त्र को विकसित न करें, अपने खुद के आर्थिक व राजनीतिक सिद्धांतों को विस्तृत न करें, अपना राजकीय ढांचा विकसित न करें और अपनी अर्थव्यवस्था व संस्कृति की दिशा स्थापित न करें। खासतौर पर, राष्ट्र के मसले पर, सोशल-डेमोक्रेसी के विचार बहुत ही हानिकारक हैं। इसने राष्ट्र का ध्वज कीचड़ में फेंक दिया है, जबकि हमेशा अपने को राष्ट्र का सबसे बड़ा रक्षक व समर्थक के रूप में पेश करती है, और "राष्ट्रीय एकता तथा क्षेत्रीय अखंडता" के नाम पर अपनी कार्यवाहियों को जायज़ ठहराती है।

सोशल-डेमोक्रेसी सरमायदारों की मनपसंद नीति है। इसे वह एक तरफ, राजकीय क्षेत्र और राष्ट्रीय संसाधनों को अपने कब्ज़े में करने के आधार पर अपने अंदरूनी अंतर्विरोधों का निबटारा करने के लिये, और दूसरी तरफ, श्रमजीवी वर्ग संघर्ष को तथा प्रत्येक देश के भीतर व अंतरराष्ट्रीय तौर पर लोगों के मुक्ति संघर्षों को समझौतावादी रास्ते पर लाने के लिये, इस्तेमाल करती है। यह बीसवीं सदी के दौरान, पूरे विश्व के अंदर सरमायदारों की मनपसंद नीति बनी रही है, बेशक, जब सोशल-डेमोक्रेसी मनचाहे परिणाम लाने में असफल हो जाये, तो सरमायदार फासीवाद का सहारा लेता है।

वैश्विक सरमायदार वर्ग आज उदारीकरण व "मुक्त बाज़ार" अर्थव्यवस्था के रूप में उदारतावाद का पक्का समर्थक होने का दावा करता है। लेकिन उदारतावादी लोकतंत्र एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत था, जो उन्नीसवीं सदी में बंधन-रहित *(laissez faire)* पूंजीवाद के हालातों के लिये अनुकूल था, जब पूंजीवाद अपने इज़ारेदारी-पूर्व पड़ाव पर था। उसके बाद काफी समय बीत चुका है, अब पूंजीवाद अपने अंतिम पड़ाव, साम्राज्यवाद के पड़ाव में पहुंच चुका है, जहां इज़ारेदारियों की आर्थिक ताक़त राज्य की राजनीतिक ताक़त के साथ सम्मिलित है। इज़ारेदार समूहों और साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच वैश्विक प्रभुत्व के लिये टक्कर आज एक आम बात बन चुकी है।

ऐसी कोई संभावना नहीं है कि साम्राज्यवाद के चलते स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का स्थान बढ़ेगा : साम्राज्यवाद पूंजी के और अधिक सकेंद्रण तथा इज़ारेदारियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। साम्राज्यवाद का अर्थ है प्रभुत्व के लिये प्रयास करना। इससे साम्राज्यवादी ताक़तों तथा इज़ारेदार समूहों के बीच, साम्राज्यवाद तथा दुनियाभर में मुक्ति के लिये लड़ रहे लोगों के बीच, पूंजी तथा श्रम के बीच, और, 1917 में महान अक्तूबर क्रांति की विजय के बाद, पूंजीवाद तथा समाजवाद के बीच, अंतर्विरोध बहुत ही तीव्र हो गये हैं। इसकी वजह से पहले ही दो अंतर-साम्राज्यवादी विश्व युद्ध हो चुके हैं, तथा बीसियों

साम्राज्यवादी आक्रमणों व दखलंदाजी के युद्ध हुये हैं, तख्तापलट हुये हैं और फासीवादी तानाशाहियां कायम हुई हैं। वर्तमान हालातों के अंदर, उदारीकरण, इज़ारेदार सरमायदारी की तरफ से बेतहाशा लूट तथा प्रभुत्व जमाने की कोशिशों का ही एक दूसरा नाम है। इज़ारेदार सरमायदारी की मनपंसद नीति अभी भी सोशल-डेमोक्रेसी ही है।

इस वक्त हिन्दोस्तान के अंदर, सोशल-डेमोक्रेसी पुराने तरीकों से कामयाब नहीं हो पा रही है। यह राजकीय आतंकवाद तथा अन्य रूप की हिंसा के बढ़ते प्रयोग में देखा जा सकता है। जिन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था और सिद्धांतों को सरमायदारी ने यूरोपीय राष्ट्रीय राज्य के उत्थान के समय जन्म दिया था, वे आज बीसवीं सदी के अंतिम वर्षों के हालातों में बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हैं। यह व्यवस्था समाज की प्रगति का रास्ता खोलने के बजाय, उसके रास्ते में एक बड़ा रोड़ा बन गयी है।

समय के साथ-साथ यह और स्पष्ट होता जा रहा है कि सरमायदार एक अनावश्यक वर्ग है; समाज के शरीर पर ऐसा परजीवी है जो समाज का खून चूसकर उसको नष्ट कर रहा है। मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था का कार्यक्रम, इजारेदारियों व साम्राज्यवादी ताकतों के बीच, निरंकुश प्रभुत्व व लूट के लिये बेलगाम स्पर्धा का ही दूसरा नाम है। यह मांग की जा रही है कि, सभी प्रतिबंधों को हटा दिया जाये, यहां तक कि राष्ट्रीय राज्य को भी खत्म कर दिया जाये, ताकि इजारेदार कंपनियां अपने मुनाफ़ों को अधिक से अधिक बना सकें तथा साम्राज्यवादी वर्चस्व को और बढ़ावा दिया जाये। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व लोक जनवादी राज्यों के पतन के साथ, वैश्विक बाज़ार विश्व के इजारेदार पूंजीपतियों तथा साम्राज्यवादियों के रहमोकरम पर निर्भर हो गये हैं, जो कि विश्व पर प्रभुत्व जमाने के लिये एक तीखी टक्कर में फंसे हुये हैं। इन हालातों में आतंकवाद तथा हिंसा, साम्राज्यवाद और वैश्विक प्रतिक्रियावाद के मुख्य हथियार बन गये हैं। इनका इस्तेमाल न सिर्फ मेहनतकश जनता के प्रतिरोधों व विद्रोहों को कुचलने के लिये, बल्कि साम्राज्यवादियों के आपसी अंतर्विरोधों को सुलझाने के लिये भी किया जा रहा है।

इससे सोशल-डेमोक्रेसी के ऊपर और ज्यादा दबाव आ रहा है कि वह मज़दूर वर्ग को अपनी व संपूर्ण समाज की मुक्ति हासिल करने के रास्ते से भटकाने का काम करे। सोशल-डेमोक्रेसी अपने आप को तमाम किस्म के चरमपंथों के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करके, यह काम करती है। इस तरह का भ्रम वैश्विक मज़दूर वर्ग तथा कम्युनिस्ट आंदोलन को बेहद नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि संघर्ष, अंतिम विश्लेषण में, दो सरमायदारी धड़ों के बीच, सरमायदारी के तथाकथित दक्षिणपंथी और वामपंथी धड़ों के बीच नहीं है, बल्कि सरमायदारी और श्रमजीवी के बीच, यानी कि शोषकों और शोषितों के बीच है।

सरमायदारों ने क्रांतिकारी शक्तियों को तितर-बितर करने के लिये मतदान और बम के तरीकों को और भी कुशलता से इस्तेमाल करना सीख लिया है। सोशल-डेमोक्रेसी अधिकांश समय मतदान के तरीके का इस्तेमाल करती है, परन्तु साथ ही बौखलाहट की हालत में वह बम के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकती। सरमायदार राजकीय आतंकवाद तथा व्यक्तिगत हिंसक कार्यवाहियों, दोनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी तथा अन्यों की कार्यवाहियों में देखा जा सकता है।

हिन्दोस्तानी हालतों के अंदर, संसदीय संघर्ष और राज्य की सशस्त्र हिंसा, सरमायदारों की हुकूमत तथा नीति को दर्शाती हैं। इनका उद्देश्य है सिद्धांत और राजनीतिक कार्यदिशा के वैचारिक संघर्ष और राजनीतिक कार्यक्रम के, तथा इंकलाब लाने के व्यवहारिक कार्य के, व्यापक सवालों को हल करने से कम्युनिस्टों व इंकलाबी ताक़तों का ध्यान हटाना।

भाग 3

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी और विचारधारात्मक तथा विवादात्मक संघर्ष

साथियों,

हिन्दोस्तान के मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनता की बड़ी आकांक्षायें रही हैं कि हिन्दोस्तान की भूमि पर समाजवाद और कम्युनिज़्म स्थापित होगा और वे मुक्त हो जायेंगे। उनकी यह आशा और उम्मीद अभी तक खत्म नहीं हुई है बावजूद इसके कि विश्व स्तर पर क्रांति पीछे हट रही है, सोवियत संघ का पतन हो गया है और बीते समय में अपने को लोक जनवाद कहलवाने वाले देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ है, और वैश्विक सरमायदारी व प्रतिक्रियावादियों के इस प्रचार के बावजूद कि कम्युनिज़्म खत्म हो चुका है, फिर भी हिन्दोस्तानी मज़दूर वर्ग और मेहनतकश आवाम की चेतना में कम्युनिज़्म के लिये गौरवपूर्ण स्थान बना हुआ है। आम जनता के बीच बहुत से ऐसे लोग मिल जायेंगे जो अपने को कम्युनिस्ट कहते हैं, चाहे वे किसी कम्युनिस्ट पार्टी में संगठित न हों। यहां तक कि सम्पत्तिवान वर्गों में भी कुछ लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार के समाजवाद के समर्थक हैं।

हिन्दोस्तानी मज़दूर वर्ग और मेहनतकश आवाम के लिये दुख की बात यह है कि उन्हें अभी भी मुक्ति नहीं मिल सकी है। यह इसलिये हुआ है कि संपत्तिवान वर्गों ने उन्हें पूंजीवाद तथा सामंती अवशेषों के साथ बांध रखा है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल-डेमोक्रेसी ने कम्युनिस्ट और मज़दूर आंदोलन को कमजोर किया है। सच्चाई तो यह है कि यूरोपीय सोशल-डेमोक्रेसी हिन्दोस्तान में अपने को समाजवाद व कम्युनिज़्म के रंगों में पेश करती है। उपनिवेशवादियों और साम्राज्यवादियों द्वारा पैदा किये गये संपत्तिवान वर्गों की आकांक्षाओं ने मज़दूर वर्ग के मुक्ति आंदोलन के स्वस्थ

शरीर में अपने जहरीले पंजे घोंप दिये हैं, और ये आकांक्षायें मांग करती हैं कि असली समाजवाद और कम्युनिज़्म सोशल-डेमोक्रेसी के सामने घुटने टेक दे। सोशल-डेमोक्रेसी के साथ समझौता करने वालों के द्वारा मज़दूरों को अपना लक्ष्य हासिल करने से रोका जा रहा है। इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि मेहनतकश लोगों को उस विचारधारा और सिद्धांत से वंचित रखा गया है, जो उन्हीं की परिस्थितियों की उपज है और जिसके साथ वे हमदर्दी प्रकट करते हैं और जिसे वे वर्ग संघर्ष चलाने के लिये एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

इन परिस्थितियों में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष चलाना होगा और मज़दूर वर्ग के लक्ष्य की हिफाज़त करनी होगी। हमें इस काम के ज़रिये, सभी कम्युनिस्टों को इस दृष्टिकोण पर लाना होगा कि किसी भी कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट संगठन को कांग्रेस (इ) या किसी अन्य सोशल-डेमोक्रेटिक संगठन के बारे में कोई भ्रम नहीं रखना चाहिये। हमें, समाज को संकट से निकालने के कार्यक्रम की हिफाज़त के लिये, बहुत ही जुझारू विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष भी चलाना चाहिये।

हिन्दोस्तान एक कृषि प्रधान देश है, यहां लघु संपत्ति का बोलबाला है। इस धरती पर संपत्ति के मालिक वर्ग – औद्योगिक घराने और पूंजीपति जमींदार – पैदा किये गये हैं। अभी भी उपनिवेशवादी विशेषाधिकार और सामंती संपत्ति मौजूद हैं। हमारे जैसे कृषि-औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देश में 70 प्रतिशत से अधिक आबादी अभी भी गांवों में रह रही है। उत्पादन के पूंजीवादी संबंधों का शहरों और गांवों, दोनों में बोलबाला है। छोटी संपत्ति अभी भी भूमि की मालिकी का मुख्य रूप है, जो जीविका के लिये निजी संपत्ति के साथ मिला-जुला हुआ है। फिर भी, उन्हीं वर्गों की संपत्ति में बढ़ोतरी हो रही जिन्हें बर्तानवी उपनिवेशवादियों ने पैदा किया था।

इन हालातों में, उस स्थान पर अधिकार जमाने की आवश्यकता है जिस पर समाजवाद और कम्युनिज़्म विकसित होगा। विचारों के क्षेत्र में, एक

जोरदार विचारधारात्मक संघर्ष चलाकर कम्युनिज़्म के लिये स्थान ग्रहण करने की काफी संभावना है। हिन्दोस्तान में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कम्युनिस्टों की एकता की पुनः स्थापना करने के क्षेत्र में, एक जोरदार विवादात्मक संघर्ष चलाकर काफी आगे बढ़ा जा सकता है। आधुनिक समय में जिस प्रकार की पार्टी की ज़रूरत है, उसके बारे में विस्तारपूर्वक समझाकर और उसके पक्ष में तर्क देकर, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिये काफी संभावनायें हैं। इस काम से ही हिन्दोस्तान की धरती पर समाजवाद और कम्युनिज़्म का विकास होगा। यह विकास तब होगा जब हिन्दोस्तान के मज़दूर वर्ग तथा मेहनतकशों की मुक्ति का सिद्धांत निश्चित रूप धारण करना शुरू कर देता है और समाज को संकट से निकालने के कार्यक्रम के इर्द-गिर्द लोगों की राजनीतिक एकता स्थापित होने लगती है। कुल मिलाकर, गहराई तक जाने वाले क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिये उपलब्ध स्थान पर कम्युनिज़्म को अधिकार जमाने की आवश्यकता है।

1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के स्थापना प्रस्ताव में, सोशल-डेमोक्रेसी से स्पष्ट तौर पर नाता नहीं तोड़ा गया था। बल्कि इसके साथ समझौता करने का एक रूझान मौजूद था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रति भाकपा के रवैये में दिखता था। उस वक्त, हिन्दोस्तान में सोशल-डेमोक्रेसी की मुख्य अभिव्यक्ति इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जैसा कि आज भी है। मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि 1925 में, हिन्दोस्तानी मज़दूर वर्ग के संगठित हिरावल दस्ते की स्थापना के वक्त क्या हुआ था। निर्णायक बात यह है कि इस वक्त भी यह एक समस्या बनी हुई है। इसके अलावा, इसका महत्व इस तथ्य में है कि 1920 के दशक में एशिया के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य सारतत्व उपनिवेशवाद-विरोधी था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज मुख्य सारतत्व उपनिवेशवादी विरासत से छुटकारा पाना है, जो कि पूंजीवाद के खिलाफ़ संघर्ष के रूप में दिखता है। 1925 में विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष हिन्दोस्तान की तत्कालीन हालातों के अनुकूल शुरू नहीं हुये। बल्कि, जो संघर्ष किसी और जगह छिड़ा

हुआ था, उसी को ही बनावटी तरीके से, हिन्दोस्तान के अंदर भी थोपा जाने लगा। उस समय उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष पूरे जोरों पर था। विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष लड़े जाने के लिये, तथा अपने तर्कपूर्ण निष्कर्ष तक लड़े जाने के लिये चीख रहा था। यह समाजवाद और कम्युनिज़्म की विजय के लिये एक पुकार थी। इसके विपरीत, दरअसल विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष शुरू ही नहीं हुआ, और एक भ्रम खड़ा कर दिया गया कि बर्तानवी उपनिवेशवाद द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था के अंदर पैदा किये संपत्तिवान वर्ग एक उपनिवेशवाद-विरोधी क्रांति ले आयेंगे, जो समाजवाद और कम्युनिज़्म की विजय के संघर्ष से जुदा और अलग होगी।

स्वतंत्रता आंदोलन की परिकल्पना पुराने यूरोपीय नमूने के आधार पर और अमरीका की आजादी के युद्ध के एक और रूप के तौर पर की गई थी। इसकी परिकल्पना, हिन्दोस्तानी उपमहाद्वीप के मज़दूर वर्ग और मेहनतकशों के उद्धार के आंदोलन से पैदा हुई, एक सामाजिक क्रांति के तौर पर कभी की ही नहीं गई थी। हिन्दोस्तानी सरमायदारों ने बड़ी चतुराई से, उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष को, समाजवाद और कम्युनिज़्म के संघर्ष के खिलाफ़ इस्तेमाल किया था। उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष को, समाजवाद और कम्युनिज़्म के संघर्ष में तब्दील करने के बजाय, कम्युनिस्ट और मज़दूर आंदोलन में अड़चने खड़ी करने के लिये उसका इस्तेमाल किया गया। आज भी ऐसा ही किया जा रहा है। "सांप्रदायिक ख़तरे" के खिलाफ़ संघर्ष के नाम पर, मज़दूर वर्ग के लक्ष्य को हमेशा के लिये टाल दिया गया है।

कम्युनिस्ट और मज़दूर आंदोलन के 70 साल के पूरे इतिहास ने दिखा दिया है कि विचारधारात्मक और विवादात्मक कम्युनिस्ट काम के बिना, मज़दूर वर्ग की स्वतंत्र भूमिका को विकसित करना संभव नहीं है। जुझारू विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष के बिना, ठोस मायनों में, यह भी पहचान असंभव है कि आंदोलन के दुश्मन कौन हैं और आंदोलन की दिशा किस तरफ है। साथ ही, यह स्पष्ट करना भी संभव नहीं है कि आज भी कृषि का सवाल, जनवादी क्रांति का मुख्य सारतत्व है।

हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट, पिछले 70 सालों के सबकों को नकार नहीं सकते। महान अक्तूबर क्रांति का रास्ता अभी भी सही है। मज़दूर वर्ग की संख्या बढ़ रही है। क्योंकि पूंजीवाद बड़ी तेज़ी के साथ, खासकर गांवों में, विकसित हो रहा है, लाखों-लाखों लोगों को छोटी आयु में कब्रों की ओर या शहरों की ओर, या प्रवासी बनाकर विदेशों की ओर धकेल रहा है। यदि समूचे विचारधारात्मक और विवादात्मक काम को क्रांति के मुख्य कार्यों के संदर्भ में स्थापित नहीं किया जाता, तो इस सच्चाई से ध्यान हट जायेगा कि पूंजीवाद ही पूरी समस्या की जड़ है। इससे उन सभी वर्गों और तबकों को लामबंध करने के काम से भी ध्यान हट जायेगा, जो वर्तमान हालतों से पीड़ित हैं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में प्रचलित और उसे बंद गली तक पहुंचाने वाली विचारधारा और सिद्धांत को स्थापित करना महत्वपूर्ण नहीं है, जो सिद्धांत और विचारधारा सिर्फ 1947 में ही नहीं, बल्कि फिर से 1964 में, 1975 में और आज भी हावी है। *हिन्दोस्तान किस दिशा में?* के सवाल के बारे में, कम्युनिस्ट और मज़दूर आंदोलन की दिशा निर्धारित करने में उस विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष का महत्वपूर्ण स्थान है, जो वर्तमान परिस्थितियों में इस आंदोलन और इसकी कार्यदिशा की हिफाज़त करे, और इतनी सारी पार्टियों और गुटों में कम्युनिस्टों का बंटवारा किये जाने का विरोध करे।

जैसे कि हमने पहले भी कहा है, विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष का मुख्य सारतत्व, सोशल-डेमोक्रेसी के साथ समझौता करने वाले सभी के खिलाफ़ और समकालीन मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा की हिफाज़त के लिये है। इस काम में सफलता नहीं मिलेगी, अगर हम विचारधारा और विवाद के क्षेत्र को वर्ग संघर्ष से बाहर रखते हैं; सिर्फ चर्चा करने और समझ बनाने का मुद्दा ही बनाये रखते हैं। सोशल-डेमोक्रेसी यही चाहती और करती है। बल्कि, इस काम में सफलता सही अर्थों में, इस काम के आधार पर उन सब से अलग होने से ही हासिल की जा सकेगी, जो सोशल-डेमोक्रेसी के साथ समझौता

करते हैं और मार्क्सवाद-लेनिनवाद को प्रभावहीन करते हैं। समझौता करने वाले, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के क्रांतिकारी निष्कर्षों का खंडन करके ऐसा करते हैं। वे ऐसा करते हैं इस सच्चाई को नकार कर, कि प्रकट हो रहे घटनाक्रम से निपटने के लिये, असलियत में मार्क्सवाद-लेनिनवाद को विकसित किया जाना चाहिये, और कि असल में, शीत युद्ध के खात्मे के बाद के पूरे ऐतिहासिक दौर में मार्क्सवाद-लेनिनवाद विकसित भी हुआ है। विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष एक क्रियाशील शक्ति है जो लगातार दोस्त और दुश्मन को अलग करती रहती है, यह एक ऐसा सीमेंट है जो मज़दूर वर्ग और लोगों को एक साथ जोड़ता है। यह काम, क्रांतिकारी आंदोलन का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट और मज़दूर वर्ग आंदोलन के अनुभव में से ही उत्पन्न होता है।

समाजवाद और कम्युनिज़्म, हिन्दोस्तान में बाहर से लाये गये थे। एक लिहाज से, हिन्दोस्तान के अंदर जिस रूप में सोशल-डेमोक्रेसी प्रकट हुई थी, उससे पूरी तरह से नाता नहीं तोड़ा गया था। कम्युनिज़्म जिस तरह आज हिन्दोस्तान में मौजूद है, यह एक कम्युनिस्ट समाज के निर्माण के लिये मज़दूर वर्ग और मेहनतकश लोगों का आंदोलन होने की बजाय, महज एक नीतिगत उद्देश्य जैसा लगता है। जबकि बर्तानवी उपनिवेशवादियों की तरफ से रोपी गई व्यवस्था – पूंजीवादी व्यवस्था – छलांगे लगाती हुई, मौत और तबाही मचाती हुई, आगे बढ़ती रही है, समाजवाद और कम्युनिज़्म ने उम्मीद के अनुसार उन्नति नहीं की है। मज़दूर वर्ग और मेहनतकश लोगों द्वारा सरमायदारों और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ़ संघर्ष करने और उसका तख्ता पलट करने की हालतें तैयार करना तो दूर की बात है, हिन्दोस्तान में समाजवाद और कम्युनिज़्म तो सोये पड़े हुए हैं। पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयां, आधुनिक समाज की सब तकनीकी और वैज्ञानिक उपब्धियों के बावजूद, एक बेमिसाल सीमा तक पहुंच गई हैं, लेकिन फिर भी कम्युनिस्ट और मज़दूर आंदोलन ने इसका तख्तापलट करने का कोई कार्यक्रम पेश नहीं किया है।

सरमायदार, लोगों के कल्याण को सुनिश्चित बनाने के सवाल को मात्र कुछ नीतिगत उद्देश्यों की घोषणा करने तक सीमित कर देते हैं। यह हिन्दोस्तान के संविधान के नीति निदेशक तत्वों में अभिव्यक्त किया गया है, जो संविधान यूरोपीय सोशल-डेमोक्रेसी की भावना से लिखा गया है। यह उस ढंग से भी प्रकट होता है, जिस ढंग से आज़ादी के बाद के सालों में लोगों के पूरे राजनीतिक जीवन पर शासन किया गया है। उदाहरण के तौर पर यह एक जानी-मानी बात है कि संविधान में अनेकों बढ़िया नीतिगत उद्देश्य हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि हिन्दोस्तानी व्यवस्था दुनिया की सबसे प्रगतिशील तथा जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक है। 45 साल पहले बनाये गये इन उद्देश्यों को देखते हुये, क्या ये निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते थे कि हिन्दोस्तान के अंदर महिलाओं का कोई शोषण नहीं होना चाहिये, जाति पर आधारित कोई दमन नहीं होना चाहिये, बच्चों की मेहनत का शोषण नहीं होना चाहिये, कोई बंधुआ मज़दूरी या ठेका मज़दूरी, किसी तरह की अशिक्षा, इत्यादि नहीं होनी चाहियें? इस तथ्य के बारे में सरमायदार क्या सफाई देते हैं कि हर प्रकार के कानूनों तथा संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, इन समस्याओं में थोड़ी-सी भी कमी नहीं हुई है बल्कि ये और भी बदतर होती जा रही हैं?

गांवों की तबाही तेज़ गति से हो रही है। लाखों-लाखों लोगों को बीमारियों और भुखमरी के कारण कम उम्र में ही मौत की ओर धकेला जा रहा है। लाखों-लाखों लोगों को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर भागने के लिये मजबूर किया जा रहा है। लाखों-लाखों लोगों को ज़हरीले पत्तों, जड़ों और दालों से पेट भरना पड़ता है। अनगिनत लोगों को बंधुआ मज़दूर बनाकर खून चूसने वाले ठेकेदारों और बिचौलियों के चंगुल में फंसा दिया जाता है। बच्चों को छोटी उम्र में ही कठोर तथा खतरनाक काम करने के लिये मजबूर किया जाता है। महिलायें और युवतियां बर्बर मध्ययुगीन दमन का, ब्राह्मणवादी और धर्म और रीति-रिवाजों पर आधारित अन्य भेदभावपूर्ण मर्यादाओं का शिकार हैं। वे पूंजीवाद का भी शिकार हैं। दलित पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन इसलिये सताया जाता है, यातनायें दी जाती हैं और अपमानित किया जाता है, क्योंकि वे

अपना सिर उठाकर यह मांग करने की जुर्रत करते हैं कि उनके साथ इंसान जैसा व्यवहार किया जाये।

ग़रीब और अमीर के बीच की खाई को खत्म करना, हिन्दोस्तानी राज्य का एक मुख्य नीतिगत उद्देश्य है। लेकिन, अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं तथा ग़रीब और ज्यादा ग़रीब। क्या इस बात का ज़वाब नहीं दिया जाना चाहिये कि, अनेकों नीतिगत उद्देश्यों के बावजूद, हालत इतनी तेज़ी से बदतर क्यों बनती जा रही है? क्या कम्युनिस्टों को, उनसे नाता नहीं तोड़ लेना चाहिये, जो सोशल-डेमोक्रेसी के साथ समझौता कर रहे हैं, जिन्होंने कम्युनिज़्म को, मज़दूर वर्ग की मुक्ति की इस शर्त को, महज एक नीतिगत उद्देश्य बनाकर रख दिया है? क्या कम्युनिस्टों को, उपनिवेशवादियों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था को चकनाचूर करने के आधार पर, जनवादी क्रांति को पूरा करने के रास्ते की रूपरेखा नहीं बनानी चाहिये?

कांग्रेस (इ) के ज़रिये, सरमायदार "समाजवादी नमूने के समाज" के हर अवशेष को खत्म कर देने के आधार पर, बहुत से सुनहरे वादे कर रहे हैं। साथ ही ऐसी कम्युनिस्ट पार्टियां भी हैं, जो दावा कर रही हैं कि वे विदेशी पूंजी और उदारीकरण के आधार पर अपने प्रदेश का औद्योगिकीकरण कर सकती हैं। सोशल-डेमोक्रेटिक कांग्रेसी और ऐसे कम्युनिस्टों के बीच सीधा संबंध उनकी नीतियों की समानताओं में देखा जा सकता है। यह कम्युनिस्टों को स्पष्ट जिम्मेदारी सौंपता है कि उन सभी के खिलाफ़ एक निरंतर विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष चलाया जाये, जो सोशल-डेमोक्रेसी के बारे में भ्रम फैलाते हैं और मार्क्सवाद-लेनिनवाद के असूलों को तोड़-मरोड़ रहे हैं।

ऐसे कम्युनिस्ट, "राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता" के नाम पर, "धर्मनिरपेक्ष" और "जनवादी" हिन्दोस्तान के नाम पर कसम खाने में कांग्रेस (इ) का साथ देते हैं, और इनको ही जीवन के मार्गदर्शक असूल और तथ्य मानते हैं, जबकि अन्य सब कुछ को महज एक नीतिगत उद्देश्य

बना दिया गया है। हिन्दोस्तान के मज़दूर वर्ग और मेहनतकशों की हालत लगातार बद से बदतर क्यों होती जा रही है – यह समझाने की बजाय, ये सोशल-डेमोक्रेट और इनके बहकावों में फंसे हुये कम्युनिस्ट, बहुत ही ख़तरनाक विचार फैला रहे हैं कि हालत को गहरे सामाजिक परिवर्तनों के बिना ही सुधारा जा सकता है। पूरी आबादी को, सोशल-डेमोक्रेसी के इस छलावे में फंसाया जाता है कि उनकी समस्याओं के समाधान नजदीक ही, बस पहुंच से कुछ ही दूर हैं। इस छलावे को, नीतिगत उद्देश्यों की एक बहुत ही लच्छेदार और लुभावनी भाषा में पिरोकर पेश किया जाता है। यह छलावा फैलाने में वे कम्युनिस्ट पूरी मदद देते हैं, जो खुद इस भ्रम में हैं और इसका प्रचार करते हैं। भ्रम फैलाने का यह धंधा ही लोगों को राजनीति से दूर रखने का, सरमायदारों के इस या उस तबके के पीछे लोगों में बंटवारे का मुख्य कारण है। यह, पूंजीवादी राज्य में शासन चलाने के लिये कुर्सी की लड़ाई में, लोगों को सरमायदारों के अलग-अलग तबकों के पीछे लामबंध करने वाला मुख्य कारक है।

ये ख़तरनाक भ्रम सिर्फ इस या उस नीतिगत उद्देश्य के बारे में ही नहीं हैं; ये मुख्य तौर पर आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हैं। भ्रम फैलाने वालों ने राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में जकड़कर रखी हुई है और वे राज्य के चरित्र के बारे में ही भ्रम फैलाते हैं। ये भ्रम राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में भी फैलाये जाते हैं, और कहा जाता है कि लोग ही फैसला करते हैं कि दिल्ली और अन्य जगहों पर किस तरह की सरकार होगी – मानो कि राजनीतिक सत्ता लोगों के हाथों में है। ऐसे भ्रम भी फैलाये जाते हैं, जिनके मुताबिक, समाज की सभी समस्यायें, इस या उस सत्तारूढ़ पार्टी की अच्छी या बुरी नीतियों से ही निर्धारित हैं।

हमारे देश का राजनीतिक अखाड़ा ऐसी पार्टियों से भरा पड़ा है, जो सबसे ऊंचे-ऊंचे नीतिगत उद्देश्यों का ढिंढोरा पीटती हैं, सभी के लिये रोज़गार, शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का, भ्रष्टाचार को खत्म करने और राजनीति को धर्मनिरपेक्ष बनाने का और सभी के लिये खुशहाली सहित, और बहुत-सी चीजों का ढिंढोरा पीटती हैं। राजनीतिक

पार्टियों के आधार पर लोगों में बंटवारा, इस आवधारणा पर आधारित है कि सत्ता में चुनी गई पार्टी की नीति ही निर्णायक भूमिका अदा करती है। इस या उस पार्टी की अच्छी और बुरी नीतियों की यह अवधारणा इस सच्चाई के सामने नहीं टिक पाती कि सत्ता तो पूंजीपति वर्ग के हाथों में है, और इस पूंजीवादी लोकतंत्र के तहत राजनीतिक पार्टियों का काम है कि वे इस सत्ता को मज़दूर वर्ग के हाथों में जाने से बचायें। जिन सबको सोशल-डेमोक्रेसी के बारे में और हर प्रकार के सरमायदारी समाजवाद के बारे में भ्रम हैं, उन सभी के खिलाफ़ बिना समझौता किये, विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष चलाते हुये, मज़दूर वर्ग अवश्य ही इस सत्ता को चकनाचूर कर देगा और अपनी खुद की राज सत्ता स्थापित करेगा और अपनी इस सत्ता को समाज की प्रगति का रास्ता खोलने के लिये इस्तेमाल करेगा। राज सत्ता पर मज़दूर वर्ग का कब्ज़ा ऐसी हालतें पैदा करता है, जिनमें समाज पर इसके सभी सदस्यों के दावे पूरे किये जा सकते हैं।

जिस व्यवस्था के अंदर कांग्रेस और भाजपा और साथ ही अलग-अलग कम्युनिस्ट और वामपंथी, हर एक प्रकार का भ्रम फैलाने में आपस में सहयोग और प्रतिस्पर्धा करते हैं इस समस्त व्यवस्था के खिलाफ़ विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष बिना रुकावट के जारी रखना चाहिये। इस व्यवस्था के खिलाफ़ विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष लड़कर, कम्युनिस्ट और मज़दूर आंदोलन के अंदर सभी प्रकार की सरमायदारी विचारधारा को हराया जा सकता है। इस काम के ज़रिये ही कम्युनिज़्म की प्रगति के रास्ते के रोड़े को चकनाचूर किया जा सकता है। कम्युनिस्टों को उस "दोगले" व्यवहार से मुक्त होना चाहिये, जो आज हिन्दोस्तान के अंदर जीवन के हर पहलू में छाया हुआ है – यानी, शब्दों में तथा सिद्धांत में एक बात कहना, परन्तु अभ्यास में इसके बिल्कुल विपरीत काम करना। लगातार किये गये विचारधारात्मक और विवादात्मक काम से ही मज़दूर वर्ग को मार्क्सवाद-लेनिनवाद की विचारधारा से लैस किया जा सकता है। समाजवाद और कम्युनिज़्म एक असली वस्तुगत जुझारू शक्ति कैसे बन सकता है, अगर यह मज़दूरों और मेहनतकश

लोगों से अलग रहता है? समाजवाद और कम्युनिज़्म के बारे में सारी बातें बेमतलब होंगी, अगर सोशल-डेमोक्रेसी के बारे में भ्रमों के खिलाफ़, इस पूरे "दोगले" व्यवहार के खिलाफ़ और मार्क्सवाद-लेनिनवाद के असूलों को बेअसर करने वालों के खिलाफ़, निरंतर विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष नहीं किया जाता है।

आज कम्युनिस्टों को, सरमायदारों द्वारा उन्हें गुमराह करने की सभी कोशिशों में फंसने से बचना होगा। सरमायदारों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तथा हिन्दोस्तान में प्रचार किया जा रहा मुख्य भटकाव यह है कि "सभ्य समाज *(सिविल सोसाइटी)*" लोगों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान कर सकता है। यह कहा जाता है कि, सरकारों पर "राजनीतिक इच्छाशक्ति" दर्शाने का दबाव डालकर, लोग अपना काम करवा सकते हैं। यह दावा बेतुका है क्योंकि सभ्य समाज की स्थापना मज़दूर वर्ग आंदोलन का उद्देश्य नहीं है। इससे मज़दूर वर्ग तथा मेहनतकश लोगों की मुक्ति नहीं हो सकती है। सभ्य समाज की स्थापना पूंजीपति वर्ग के सत्ता में आने के लिये, सामंती रियायतों को दबाने के लिये, पूंजीपतियों के प्रभुत्व की स्थापना के लिये और आधुनिक उपनिवेशवादी कब्ज़ों तथा साम्राज्यवादी लूट के लिये एक बुनियादी शर्त थी। यह, वैश्विक पैमाने पर नव-उपनिवेशवाद का आधार है। सभ्य समाज के अंदर "राजनीतिक इच्छाशक्ति" का उद्देश्य है सरमायदारों की मदद करना ताकि वे कुछ ऐसी असंगतियों से छुटकारा पा सकें, जो उत्पादन और पूंजी के भूमंडलीकरण की सेवा के लिये, समाज और राष्ट्र के बीच तालमेल लाने की उसकी वर्तमान ज़रूरत के अनुकूल नहीं हैं।

अगर बिना पक्षपात के विश्लेषण किया जाये तो सभ्य समाज, मज़दूर वर्ग और मेहनतकश लोगों की गुलामी की एक शर्त है, यह उनकी मुक्ति की शर्त नहीं है। सभ्य समाज हिन्दोस्तान के अंदर पहले ही मौजूद है। सभ्य समाज का मतलब है : उन संस्थाओं को वैधानिक गारंटी देना, जिनके ज़रिये सरमायदार वर्ग अपनी पूंजी का अंबार लगाता है और अपने राज को मजबूत बनाता है। ऐसी संस्थायें, अलग-अलग देशों में व अलग-अलग समयों पर, अलग-अलग रूप धारण कर सकती हैं। सभ्य

समाज के अंदर एक प्रकार की संवैधानिक राजशाही हो सकती है, एक गणराज्य, एक राष्ट्रपति व्यवस्था हो सकती है, और/या प्रधानमंत्री की कमान के तहत एक संसद हो सकती है, एकल राज्य या परिसंघ हो सकता है, एक अनुपाती प्रतिनिधित्व या सबसे अधिक मत जीतने पर आधारित एक चुनाव प्रणाली हो सकती है। इसके अंदर ज्यादा या कम दर्जे तक नागरिक आज़ादियां हो सकती हैं, जैसे कि विचार प्रकट करने, संस्था बनाने, धार्मिक विश्वास और बंदी प्रत्यक्षीकरण *(हीबियास कॉर्पस)* की आज़ादी, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव में वोट डालने का अधिकार, सर्वव्यापी या आंशिक मताधिकार, इत्यादि। साथ ही साथ, इसके अंदर ऐसे भी प्रावधान हैं कि जब सभ्य सत्ता को अंदरूनी या बाहरी खतरा होता है या सरकार इन अधिकारों को "मुनासिब सीमाओं" के अंदर रखने का फैसला करती है तो इन आज़ादियों व संस्थाओं को निलंबित किया जा सकता है। सभ्य समाज, चाहे उसका कोई भी रूप या मूलतत्व हो, हमेशा निजी संपत्ति के सर्वाधिकार और निजी संपत्ति के एकत्रीकरण के ज़रिये "सुख की तलाश" और खुशहाली की धारणा पर आधारित होता है।

हिन्दोस्तान में, भूमि और उत्पादन के अन्य सभी साधनों में निजी संपत्ति की कानूनी वैधता, बर्तानवी उपनिवेशवादी शासन की आधारशिला थी। हिन्दोस्तान का सभ्य समाज एक उपनिवेशवादी विरासत है। यह, हिन्दोस्तान के मेहनतकश लोगों के बेरहम शोषण, और हिन्दोस्तान के लोगों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित करने की शर्त है। अगर इतना भी नहीं समझा जाता है, तो हिन्दोस्तान के कम्युनिस्ट और लोग अपने कंधों पर सवार इस बंदर से, यानी हर एक चीज को महज "सामाजिक नीतिगत उद्देश्य" बना देने के इस तमाशे से, कभी भी छुटकारा नहीं पा सकेंगे, जो कि हिन्दोस्तान की धरती पर समाजवाद और कम्युनिज़्म की प्रगति के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है।

यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि न तो हिन्दोस्तान का संविधान और न ही खुद सत्ता पर कब्ज़ा करने के लिये होड़ लगा रही राजनीतिक पार्टियां, ऐसे तंत्र बनाने और उन्हें लागू करने की आवश्यकता के प्रति कोई ध्यान

देती हैं, जो उनके सीमित लक्ष्यों को हासिल करने के लिये भी ज़रूरी हैं। व्यवस्था पर तो वे कोई सवाल उठायेंगे ही नहीं। व्यवस्था लोगों और समाज के जीवन पर मौत और तबाही बरसाये जा रही है, जबकि तथाकथित बढ़िया कानून और नीतिगत उद्देश्य सिर्फ किताबों तक सीमित रहते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। इस या उस पार्टी का कौन-सा नीतिगत उद्देश्य अच्छा या बुरा है – इसके बारे में निरंतर चर्चा करते रहने का समाज पर और हिन्दोस्तानी लोगों की मानसिकता पर क्या प्रभाव होता है?

इस संदर्भ में, यह दिखाया जा सकता है कि इन भ्रमों के विरुद्ध निरंतर विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष चलाये बिना, कम्युनिज़्म खुद एक नीतिगत उद्देश्य बनकर रह जायेगा। एक ऐसा तत्वहीन और अर्थहीन मुहावरा बनकर रह जायेगा, जिसे समय-समय पर दोहराया जाता है, जैसे कि बहुत-सी कम्युनिस्ट पार्टियां कर रही हैं। विभिन्न पहलुओं में और बहुत से इलाकों में हिन्दोस्तान का कम्युनिस्ट आंदोलन अटका हुआ है। यह भ्रमों की खाई में गिर गया है, जहां से निकलने से यह इनकार कर रहा है। यह भ्रमों के खिलाफ़ एक विचारधारात्मक रवैया अपनाने से पीछे हटने की कोशिश करता है और इन भ्रमों को पैदा करने वालों के विरुद्ध विवादात्मक संघर्ष नहीं लड़ता है। यह उस पुराने विचार में फंसा हुआ है कि सरमायदारी पार्टियों के साथ स्पर्धा करते हुये सरमायदारी राज्य का शासन चलाने के लिये, उसे उसी कार्यक्रम के इर्द-गिर्द संगठित करना चाहिये, जो उसे सबसे "उत्तम" लगता है। नतीजे के तौर पर कम्युनिस्ट आंदोलन टुकड़े-टुकड़े हो गया है, जिसके अंदर बहुत से गुट आपस में इस विषय पर लड़ रहे हैं कि सरमायदारी राज्य का शासन चलाने का सबसे "उत्तम" कार्यक्रम और नीतियां किसके पास हैं। सबसे "उत्तम" कार्यक्रम के इर्द-गिर्द गुट संगठित करने का यह रवैया बिल्कुल यूरोपीय व्यापारी, उद्योगपति और जमींदार वाला दृष्टिकोण है, जो अपना घोषणापत्र, सख्ती से सिर्फ अपने खुदगर्ज़ हितों की पूर्ती के आधार पर प्रस्तुत करता है। इनमें से बहुत से घोषणापत्र, सार रूप में, खुलेआम वर्तमान व्यवस्था की हिफाज़त करते हैं। ऐसा ही हाल उनका है जो अपना "तीसरा मोर्चा" बना रहे हैं।

कम्युनिस्टों को निश्चित ही, सरमायदार वर्ग के सभी गुटों के खिलाफ़, इस या उस नीतिगत उद्देश्य वाली सभी राजनीतिक पार्टियों और गुटों के खिलाफ़, एक निरंतर विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष विकसित करना होगा। उनको निश्चित ही सामाजिक विज्ञान का इस्तेमाल करना होगा और अपने तर्कों को, हिन्दोस्तान के मज़दूर वर्ग तथा मेहनतकश लोगों की आकांक्षाओं के अनुकूल पेश करना होगा। उन्हें ऐसे तर्कों के इर्द-गिर्द इस या उस गुट को संगठित नहीं करना चाहिये। बल्कि इसके विपरीत, उन्हें यह संघर्ष इस तरह से चलाना चाहिये कि मज़दूर वर्ग को क्रांति और समाजवाद की जीत के लिये संगठित किया जा सके। उनको चर्चा और बहस, मज़दूर वर्ग का स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से चलानी होगी। जब तक विचारधारात्मक और विवादात्मक लड़ाइयां, ठोस रूप में यह पहचान करके नहीं चलाई जातीं कि सभी कम्युनिस्टों का फौरी कार्य वर्तमान व्यवस्था के बारे में सभी भ्रमों के खिलाफ़ लड़ाई करना है, तब तक हिन्दोस्तान की धरती पर समाजवाद और कम्युनिज़्म बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पायेगा। जो कम्युनिस्ट इस व्यवस्था के बारे में और सोशल-डेमोक्रेसी के बारे में सभी भ्रमों के खिलाफ़ दृढ़ता से विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष नहीं चलाते, वे कम्युनिस्ट और मज़दूर आंदोलन के साथ गद्दारी तथा उसका विघटन करने का रास्ता पकड़ लेंगे।

हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक कठोर और बिना किसी समझौते के, विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष चलाना आवश्यक है, इसलिये नहीं कि ज्ञान में कोई समस्या है या फिर सिर्फ प्रकाश डालने के लिये ही नहीं। बल्कि इसलिये कि वस्तुगत हालतें इसकी मांग कर रही हैं। पूंजीवादी विकास की वस्तुगत हालतों में यह आवश्यक है कि विचारों का एक शस्त्रागार बनाया जाये और इसे मज़दूर वर्ग के लिये उपलब्ध कराया जाये। विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष इस शस्त्रागार

को बनायेगा। मज़दूर, इस शस्त्रागार को अपने सभी, प्रत्यक्ष और छुपे हुये, दुश्मनों के खिलाफ़ इस्तेमाल कर सकेंगे। विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष चलाते समय, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी, क्रांति के उद्देश्यों को सबसे ऊपर रखती है, यानी फौरी तौर पर समाज को संकट से बाहर निकालना और रणनीतिक तौर पर समाजवाद तथा कम्युनिज़्म की जीत के लिये हालात तैयार करना।

भाग चार

हिन्दोस्तानी सिद्धांत की आवश्यकता

साथियों,

हिन्दोस्तान के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन की जीत के लिये, सिद्धांत का सवाल शुरुआती-बिंदू, पहला कदम, सबसे फौरी सवाल और लंबे समय के कार्य के रूप में सामने आता है। इसकी सबसे ठोस अभिव्यक्ति हिन्दोस्तानी सिद्धांत की आवश्कता के रूप में होती है, एक ऐसे सिद्धांत की आवश्यकता जो हिन्दोस्तान की हालतों में से उभर कर आया हो और यहां कम्युनिज़्म के विकास के लिये अनुकूल हो। यह काम पुराने ज़मीर के साथ, एक तरफ सोशल-डेमोक्रेसी के साथ समझौता करने वालों के ज़मीर के साथ, और दूसरी तरफ बर्तानवी उपनिवेशवादियों और पूंजीपति वर्ग तथा सामंती तत्वों के ज़मीर के साथ, हिसाब चुका कर ही आरंभ करना होगा।

सोशल-डेमोक्रेसी के साथ समझौता करने वालों के सिद्धांत के अनुसार, ऐसी व्यवस्था का होना स्वाभाविक है जो सीधे तौर पर यूरोप से आयातित हो, जो उपनिवेशवादियों द्वारा ही पैदा किये गये वर्गों के लिये उपयुक्त हो, जिन वर्गों के लिये ऐसी व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना और इसे मज़बूत करना उनके हित में हो। यह गंभीरता से जांचना भी महत्वपूर्ण होगा कि हठवादी रूप से प्रस्तुत किया गया मार्क्सवाद-लेनिनवाद बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों, पूंजीपतियों और सामंती जमींदारों जैसे वर्गों के लिये काफी स्वीकार्य है। उनके द्वारा इस हठवादी मार्क्सवाद-लेनिनवाद के पोषण का और क्या कारण हो सकता है, इसके अलावा कि वे इसके ज़रिये अपनी व्यवस्था की हिफाज़त कर सकते हैं?

साथियों, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के सामने हल करने के लिये इस समय की सबसे बड़ी समस्या, हिन्दोस्तानी सिद्धांत की समस्या है। यह काम पार्टी के प्रथम महाअधिवेशन, पार्टी की स्थापना

की दसवीं सालगिरह के समय शुरू हुआ था। अगर हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को मज़दूर वर्ग के हिरावल दस्ते की भूमिका निभानी है, तो उसे हिन्दोस्तान की हालतों से कम्युनिज़्म के सिद्धांत का विकास करना होगा। हिन्दोस्तान के पुराने ज़मीर के साथ हिसाब चुका कर इस सिद्धांत का विकास करना होगा। इस सिद्धांत को हिन्दोस्तानी रूप देना होगा। इस सिद्धांत में यूरोकेन्द्रवाद या इसे गैर वैज्ञानिक बनाने वाले किसी भी अन्य प्रभाव का नामोनिशान नहीं होना चाहिये। यह सिद्धांत हिन्दोस्तानी क्रांति के अभ्यास के लिये उपयुक्त होना चाहिये और दुनिया की किसी भी हालत में, आम तौर पर, लागू करने योग्य होना चाहिये। इस हिन्दोस्तानी सिद्धांत के विकास के ज़रिये ही *हिन्दोस्तान किस दिशा में?* के सवाल का उत्तर पूरी तरह दिया जा सकेगा और क्रांतिकारी आंदोलन तेज़ी से आगे बढ़ सकेगा।

हिन्दोस्तान 2500 से अधिक वर्षों से, छोटे उत्पादन और व्यक्तिगत तथा सामुदायिक संपत्ति का देश रहा है। हिन्दोस्तान में इस अनुभव पर आधारित, अनेक दर्शनशास्त्र और सिद्धांत हैं। परन्तु हालातों में अनेक परिवर्तन आये हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन, यानी भौतिक उत्पादन की सामाजिक प्रक्रिया शहरों और गांवों, दोनों में प्रचलित हो रही है। पर इसके बावजूद, अभी भी बहुत सारा ऐसा स्थान है जिसमें सामुदायिक मालिकी और उस पर आधारित विचार प्रचलित हैं, जिसे पूंजीवाद द्वारा नहीं भरा जा सकता है। इसके बारे में मार्क्सवादी-लेनिनवादी क्या करेंगे? क्या वे पहले इन प्राचीन, सामुदायिक, सामंती-पितृसत्तावादी संबंधों, उत्पादन के एशियाई नमूने को पूंजीवादी संबंधों में तब्दील करेंगे; या, क्या वे सीधा समाजवाद की ओर बढ़ेंगे? सीधा समाजवाद की ओर बढ़ना बेहतर होगा। इसके लिये, एक हिन्दोस्तानी क्रांतिकारी सिद्धांत की आवश्यकता है जो हिन्दोस्तान के संपूर्ण जीवन को क्रांतिकारी बनाने, सीधा समाजवाद की ओर जाने, के अभ्यास का मार्ग रोशन कर सके। इसके लिये यह ज़रूरी होगा कि तमाम दर्शनशास्त्रों और विचारधाराओं, उनके अनेक रूपों व आकारों, को अभ्यास की निर्णायक कसौटी पर परखा जाये और इस एक क्रांतिकारी सिद्धांत का विकास किया जाये।

इस सिद्धांत को मज़दूर वर्ग के मुक्ति आंदोलन के साथ निकट संबंध रखना होगा, क्योंकि यह आंदोलन ही हर गतिविधि की धुरी है। सबसे उन्नत दर्शनशास्त्र और सिद्धांत, मार्क्सवाद-लेनिनवाद और समकालीन मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा के साथ तुलना और भेद करके ही हिन्दोस्तानी क्रांतिकारी सिद्धांत को आधुनिक बनाया जा सकता है। हिन्दोस्तानी दर्शनशास्त्र और सिद्धांत को सबसे अधिक आधुनिक होना होगा। उसे खुद को उन सभी विचारधाराओं से बेरहमी के साथ अलग करना होगा, जो उसे शक्तिहीन बना देती हैं और उसे सिर्फ कोई आध्यात्मिक चरित्र प्रदान करती हैं।

आम तौर पर, सोच, धारणायें, विचार, व्याख्याएं, सभी तुलनात्मक होती हैं। इसीलिये किसी व्यक्ति के विचार उतने ही सही या गलत हो सकते हैं, जितने कि किसी और व्यक्ति के। दूसरी ओर, सिद्धांत अपरिवर्तनशील है, जब तक उसे गलत साबित नहीं किया जाता है। अगर विचारधारा किसी देश की धरती से उभर कर नहीं आती है, अगर सिद्धांत के आधार पर क्या सही है और क्या गलत, यह स्थापित करने के लिये निरंतर संघर्ष नहीं किया जाता है, तो मज़दूर वर्ग का कोई वास्तव में जागरुक, वास्तव में स्वतंत्र और वास्तव में क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हो सकता है। मज़दूर वर्ग की मुक्ति के आंदोलन में जीत हासिल करने के लिये विचारधारात्मक संघर्ष और सिद्धांत, दोनों पर लगातार ध्यान देना निर्णायक होगा।

दर्शन के हिन्दोस्तानी दर्शनशास्त्र का मूल आधार यह है कि सभी वस्तुएं और घटनाक्रम खुद ही खुलकर सामने आते हैं। संपूर्ण विश्वमंडल माया के अलावा कुछ और नहीं है। माया के अस्तित्व की विधि आवागमन है। हिन्दोस्तानी सिद्धांत के विकास की शुरुआत के लिये, हिन्दोस्तानी दृष्टिकोण का इस प्रकार का भौतिकवादी विवरण बहुत उत्तम है। इस सिद्धांत को विकसित करने के लिये, हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों को वर्तमान से आरंभ करना होगा, हिन्दोस्तान के हालातों में जो भी प्रचलित है उसकी तीखी आलोचना करनी होगी, खास तौर पर उस पुराने ज़मीर की, जिसे हिन्दोस्तान के शासक वर्ग इतना बढ़ावा देते हैं।

दर्शन के दर्शनशास्त्र की प्रवाहहीनता, इसका हिन्दोस्तानी विचारधारा की प्रवाहहीनता और हमारे देश में आर्थिक व राजनीतिक सिद्धांतों की प्रवाहहीनता के साथ अटूट संबंध है। दर्शनधारी, हिन्दोस्तानी, अमरीकी और बर्तानवी विश्वविद्यालयों के आरामदायक कमरों में बैठ कर हिन्दोस्तानी दर्शनशास्त्र के बारे में ऊंची-ऊंची सोच प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि उसका हिन्दोस्तान के वर्तमान हालातों के साथ कोई लेना-देना या सम्बंध न हो, इतिहास के वर्तमान समय में हिन्दोस्तानी लोगों की प्रगति के रास्ते को रोशन करने में उसकी कोई भूमिका न हो। दर्शन का एक आदर्शवादी और धार्मिक विवरण दिया जाता है, ताकि वह हिन्दोस्तानी लोगों को लिये निर्जीव और व्यर्थ हो जाये। बहरहाल, हिन्दोस्तानी लोग आज की समस्याओं को हल करने के लिये एक दर्शनशास्त्र और दृष्टिकोण से वंचित हैं और सरमायदारों व साम्राज्यवाद द्वारा बिछाये जाल में बेबस तड़प रहे हैं।

मिसाल के तौर पर, दर्शन को सिर्फ धर्म के क्षेत्र में सीमित रखा जाता है, जिसमें भगवान अपने भक्तों के सामने, उनके दैनिक दर्शन के दौरान प्रकट होते हैं। कई प्रकार के दर्शनशास्त्र जानबूझकर माया का एक आदर्शवादी विवरण देते हैं और उसे एक भ्रम जैसा करार देते हैं – जबकि माया संपूर्ण विश्वमंडल है जिसके अंदर पदार्थ और तरह-तरह की विचारधाराओं के रूप में उस पदार्थ की झलक है। आवागमन – विचारधारा समेत वस्तुओं और घटनाक्रम के उत्पन्न होने और खत्म होने की प्रक्रिया – को अपने अत्यंत क्रांतिकारी और भौतिक चरित्र से वंचित किया जाता है। वास्तव में, आवागमन यह दर्शाता है कि वस्तुयें और घटनाक्रम किस तरह सामने आते हैं, जन्म लेते हैं और मिट जाते हैं। इसके बजाय, ये दर्शनधारी इन अवधारणाओं की आदर्शवादी, चक्रीय और भाग्यवादी व्याख्या देते हैं।

इस प्रकार की व्याख्याएं हिन्दोस्तानी लोगों को समाज में मौजूद समस्याओं को हल करने में मदद नहीं करतीं। मानव और प्रकृति के बीच तथा मानवों के बीच सही संबंध को निर्धारित करने में लोगों को मदद देने, जैसा कि प्राचीन समय दर्शन किया करता था, इसके बजाय इस प्रकार की व्याख्याएं मानवों को वर्तमान समाज और प्रकृति की विनाशकारी

ताकतों का बेबस शिकार बना देती हैं। यह हिन्दोस्तान की त्रासदी है कि हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट दर्शन की इन फरेबी व्याख्याओं का मुकाबला नहीं करते हैं। यह समझा जा सकता है कि बर्तानवी-अमरीकियों द्वारा, खास तौर पर उपनिवेशवादी शासन के दिनों से, दर्शन को जानबूझकर नीचा दिखाया गया है और वर्तमान समय में कोई प्रासंगिकता न रखने वाली, अतीत की पांडित्य की चीज तक उसे सीमित रखा गया है। परन्तु हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों को क्यों इसका शिकार बनना चाहिये?

हिन्दोस्तानी दर्शनशास्त्र का विकास न करके, पांडित्य के क्षेत्र और विश्वविद्यालयों और धार्मिक संस्थानों की चार दीवारों से उसे बाहर न निकाल कर, खुद को तथा लोगों को हिन्दोस्तानी समाज की समस्याओं को हल करने में मदद करने वाली विचारधारा से लैस न करके, हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों ने सरमायदार वर्ग को अपनी हुकूमत बरकरार रखने में सहायता दी है। सरमायदार और उनकी राजनीतिक पार्टियां, हिन्दोस्तानी दर्शनशास्त्र को दिखावटी मान्यता देते हुये, खुद हिन्दोस्तानी परंपराओं और रंगों को धारण करके, आपस में लड़ती रहती हैं। इस सब के दौरान कम्युनिस्ट किनारे पर रह जाते हैं और हिन्दोस्तानी लोगों के "पिछड़ेपन" या "अगुवापन" के बारे में वाद-विवाद करते रहते हैं। कुछ कम्युनिस्ट यह वाद-विवाद भी चलाते हैं कि क्या उन्हें हिन्दोस्तानी इतिहास या धर्मों के कुछ पुराने चिन्हों को अपना लेना चाहिये, जैसे कि मानो दर्शनशास्त्र या सिद्धांत का सवाल एक वस्त्र को बदलकर दूसरा वस्त्र धारण करने के मामले जैसा है। यह समाज में सिद्धांत के महत्व का मजाक बनाता है। ऐसे समय पर जब पूरी जागरुकता के साथ इतिहास की रचना करने की तथा अराजकता और स्वतः स्फूर्त उथल-पुथल के पूर्व-इतिहास को खत्म करने की आवश्यकता है, इस समय सिद्धांत के महत्व को इस तरह नकारा जाता है। हिन्दोस्तान के कम्युनिस्टों को सिद्धांत को उच्चतम पड़ाव तक पहुंचाना होगा और ऐसा स्वरूप देना होगा, जो कि सिर्फ हिन्दोस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में, समाज की प्रगति का रास्ता खोलने में एक योगदान बतौर, विश्वस्तर पर माना जायेगा।

हिन्दोस्तान में समाजवाद और कम्युनिज़्म के संघर्ष के 70 वर्षों से गुजर कर, सभी हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों को यह समझना होगा कि जिन सिद्धांतों का विरोध किया जाना चाहिये, उनका खंडन सिर्फ इसलिये नहीं करना है कि वे विदेशी हैं। उन सिद्धांतों का खण्डन इसलिये करना है क्योंकि वे हिन्दोस्तानी समाज को गुलामी और बंधन में रखने के साधन हैं। अगर समाज को 21वीं सदी के लिये तैयार होना है, तो उसे यूरोपीय सोशल-डेमोक्रेसी और सरमायदारी समाजवाद की खिचड़ी के संपूर्ण बोझ को पीछे छोड़ना होगा। यही मुख्य बात है। हमें यह समझना होगा कि किसी भी देश के यथार्थ हालातों के अंदर, ऐतिहासिक तौर पर विकसित सिद्धांत और दर्शनशास्त्र के बिना, उस देश में समाजवाद और कम्युनिज़्म का निर्माण करना मुमकिन नहीं है। यह समझने से हम बर्तानवी उपनिवेशवाद की उस विरासत को हमेशा के लिये खत्म कर देंगे, जिसके अनुसार हिन्दोस्तानी दर्शनशास्त्र और विचारधारा सिर्फ यूरोपीय दर्शनशास्त्र के ज़रिये ही अभिव्यक्त हो सकती हैं।

अफ़लतून और अरस्तू (प्लेटो और एरिस्टोटल) से जन्मी यूरोपीय दर्शनशास्त्र की परंपरा को ज्ञान और विवेक के युग के दौरान परिपूर्ण बनाया गया तथा आधुनिक यूरोपीय राष्ट्रीय राज्य को जन्म देने वाले क्रांतिकारी संघर्षों के दौरान और अधिक ठोस आकार दिया गया था। परन्तु इसके बावजूद, इस अति प्रभावशाली विकास के बाद *अतर्कवाद* का दौर चला। *अतर्कवाद* कार्ल मार्क्स द्वारा सामाजिक विज्ञान के क्रांतिकारीकरण और श्रमजीवी क्रांति के डर के प्रति यूरोपीय सरमायदारों की प्रतिक्रिया थी।

इसी *अतर्कवाद* को यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने अपने उपनिवेशों पर थोप दिया। उपनिवेशों के आज़ाद हो जाने के बाद भी ऐसा किया जाता रहा। इस उपनिवेशवादी दर्शनशास्त्र की पूर्वधारणाओं की नज़र से हिन्दोस्तान को देखना कुछ विदेशी विद्वानों की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है और "श्वेत पुरुष का बोझ" की धारणा को उचित ठहराने के लिये भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। "श्वेत पुरुष का बोझ" वह मिशनरी उत्साह का दूसरा नाम है, जिसके ज़रिये उपनिवेशवादियों ने "बंजर" हिन्दोस्तानी

आत्माओं पर अपना अधिकार जमाने व उनमें सभ्यता भरने की कोशिश की थी। खून-खराबा और कब्ज़ाकारी जंग के ज़रिये, उन्होंने हिन्दोस्तान को सभ्य समाज और यूरोपीय उपनिवेशवादी दर्शनशास्त्र के नियंत्रण में लाया। इस प्रकार से थोपा गया सभ्य समाज और यूरोपीय दर्शनशास्त्र मज़दूर वर्ग की मुक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दे सकते हैं।

लोगों के उपनिवेशवादी विनाश से जो खाली स्थान पैदा हुआ, उसे उपनिवेशवादियों ने *अतर्कवाद* से भरने की कोशिश की। उपनिवेशवादियों ने हिन्दोस्तानी समाज और दर्शनशास्त्र को नकारा। आज अगर हिन्दोस्तानी समाज और दर्शनशास्त्र को विकसित करके आगे ले जाना है, तो उपनिवेशवादियों की उस कृति को नकारना होगा। उनके *अतर्कवाद* को नकारने से तर्कवाद के लिये रास्ता खुलेगा।

फ्रेडरिक ऐंगेल्स ने बहुत समय पहले, बड़ी तीक्ष्णता के साथ समझाया था कि "... हर युग का दर्शनशास्त्र यह मान कर चलता है कि उसके पूर्व युगों से खास विचार-वस्तु मिली है और उसी से अपनी शुरुआत करता है..."[4] क्या हम हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट यह कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें "खास विचार-वस्तु" बतौर कुछ भी नहीं दिया?

जैसे कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक ऐंगेल्स ने अपने समय के प्रचलित विचारों, यानी अपने पुराने ज़मीर के साथ हिसाब चुकाया था, ऐसे ही हमें भी हिन्दोस्तान में प्रचलित ज़मीर, यानी कि हमारे पुराने ज़मीर के साथ हिसाब चुकाना होगा। हम ऐसा करना शुरू भी नहीं कर सकेंगे अगर हम अपने पुराने ज़मीर के अस्तित्व को ही नकारते रहें, अगर हम हिन्दोस्तानी दर्शनशास्त्र को नकारते रहें, अगर हम बीते युग से प्राप्त "विचार-वस्तु" को नकारते रहें। अगर हम अपने भूतपूर्व ज़मीर के साथ

[4] मार्क्स एवं ऐंगेल्स, 'संकलित पत्राचार', फोरेन लेंग्वेज पब्लिशिंग हाउस, मॉस्को, रूसी संस्करण, ऐंगेल्स से सी. श्मिट को पत्र, 27 अक्तूबर, 1890, पृष्ठ 506

हिसाब नहीं चुका लेते, तो दर्शनशास्त्र का क्षेत्र हिन्दोस्तानी सरमायदारों और साम्राज्यवाद के हाथों में रह जायेगा। हिन्दोस्तानी दर्शनशास्त्र और सिद्धांत का विकास रुक जायेगा।

हम हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट दर्शन के हिन्दोस्तानी दर्शनशास्त्र से वह सब कुछ लेते हैं जो भौतिकवादी और क्रांतिकारी है, यानी हम इस धारणा को अपनाते हैं कि वस्तुयें और घटनाक्रम खुद खुलकर हमारे सामने आते हैं। वस्तुयें और घटनाक्रम अपने हठधर्मी रूप में खुलकर सामने नहीं आते हैं, जैसा कि हिन्दोस्तानी सरमायदार हमें यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। माया के अस्तित्व की विधि, यानी कि आवागमन, हठधर्मी रूप में की गयी इन अभिव्यक्तियों को समाप्त कर देती है। माया के आने और जाने, जन्म लेने और समाप्त होने के चरित्र आवागमन, से प्राप्त होता है। वस्तुयें और घटनाक्रम अपने विकास के स्तर के अनुसार खुलकर सामने आते हैं – जैसे-जैसे हालतें बदलती हैं, वैसे-वैसे जो खुलकर सामने आता है उसमें भी तब्दीलियां होती रहती हैं। इस बात को मान लेना हिन्दोस्तानी दर्शनशास्त्र और सिद्धांत को स्थापित करने का शुरुआती बिंदु होगा। यह अंतिम बिंदु नहीं है, जिस प्रकार द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद अंतिम बिंदु नहीं है। ऐसा सोचना बेवकूफी होगी कि अब तक जो बड़े-बड़े आविष्कार किये गये हैं, वे मानव जाति की ज़रूरतों की उच्चतम और अंतिम व्याख्या हैं, जो हमेशा के लिये और दुनिया के सभी लोगों के लिये उपयुक्त होंगे। इस प्रकार का छिछला विचार सिर्फ उन्हीं को अच्छा लगता है जो वर्तमान हालतों से संतुष्ट हैं और जिन्हें यथास्थिति से फायदा हो रहा है।

जिस तरह सरमायदार वर्ग ने विदेशी उपनिवेशवादी विरासत, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था और अन्य संस्थानों को मजबूत करके, पूरे देश को विदेशी पूंजी पर निर्भर बना रखा है, वैसे ही उसने यूरोपीय दर्शनशास्त्र पर अपनी निर्भरता को बनाये रखा है। "विचार-वस्तु" की दृष्टि से भी वह भिखारी है। हिन्दोस्तानी लोगों के खिलाफ़ यह उसका

सबसे बड़ा अपराध है। सरमायदारों के स्कूलों में विदेशी "विचार-वस्तु" भरी हुई है, यहां तक कि "राष्ट्रीय भाषा" जिसमें सरमायदार कामकाज करते हैं, वह भी विदेशी भाषा है।

ऐंगेल्स के अनुसार, "मार्क्स वस्तुओं और संबंधों में सांझे मूलतत्व का सारांश करते हैं और उसकी आम तर्कसंगत अभिव्यक्ति निकालते हैं। अतः उनके इस अमूर्तकरण (यानी कि विशेष गतिविधियों से आम निष्कर्ष निकालना) में, विचारों के रूप में, वह सारतत्व प्रतिबिंबित होता है जो पहले से ही चीजों में निहित है।"[5] अगर दर्शनशास्त्र विदेशी है तो "वस्तुओं और संबंधों में सांझा मूलतत्व" भी विदेशी होगा। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार के दर्शनशास्त्र में हिन्दोस्तानी समाज के अंदर "चीजों में पहले से ही निहित सारतत्व" प्रतिबिंबित नहीं होगा। सरमायदार वर्ग, बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों पूंजीपतियों और जमींदारों का जन्म बर्तानवी उपनिवेशवादी व्यवस्था से हुआ है। बर्तानवी उपनिवेशवादियों ने, अन्य चीजों के अलावा, सरमायदार वर्ग को शोषण पर आधारित संपत्ति के संबंध प्रदान किये और उन संबंधों को जायज़ ठहराने वाली विचार-वस्तु भी प्रदान की। हिन्दोस्तान के भूतकाल की सभी उपलब्धियों को नष्ट करके बर्तानवियों ने हिन्दोस्तानियों के सामने दो रास्ते पेश किये – या तो बर्तानवियों द्वारा उत्पन्न किये गये वर्गों की विचार-वस्तु को अपना लें या फिर बीती उपलब्धियों के विनाश से पैदा हुई शून्यता में खो जायें। क्रांतिकारी कम्युनिस्टों को इन दोनों रास्तों को ठुकराना होगा और एक ऐसा सजीव सिद्धांत पैदा करना होगा, जो बर्तानवियों द्वारा दी गयी विचार-वस्तु तथा उनके द्वारा पैदा किये गये खाली स्थान को खत्म कर देगा।

हिन्दोस्तानी शासक वर्गों द्वारा प्रस्तुत की गयी बर्तानवी विचार-वस्तु हिन्दोस्तानी दर्शनशास्त्र और सिद्धांत के विकास को नकारती है। इसे जनसंहार (या कम से कम, सांस्कृतिक जनसंहार) कहा जा सकता है, परन्तु हिन्दोस्तान के सरमायदार इस पर बहुत गर्व करते हैं; सरमायदार

[5] उपरोक्त, ऐंगेल्स से के. काउट्स्की को पत्र, 20 सितम्बर 1884, पृष्ठ 454

जो प्रचार करते हैं वह हिन्दोस्तानी मज़दूर वर्ग और लोगों के हितों के खिलाफ़ है। बीते समय से प्राप्त खास विचार-वस्तु और मज़दूर वर्ग आंदोलन के आम अनुभव के सारांश पर खुद को आधारित करते हुये, हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों को एक ऐसे सिद्धांत की रचना करनी होगी, जो उनके लिये अपना आध्यात्मिक अस्त्र होगा, जिस सिद्धांत का भौतिक अस्त्र मज़दूर वर्ग खुद ही होगा।

कार्ल मार्क्स ने बताया था कि श्रमजीवी वर्ग क्रांति का दिल है और दर्शनशास्त्र उसका दिमाग। अगर भौतिक अस्त्र और दिल, श्रमजीवी वर्ग, हिन्दोस्तानी है, तो बर्तानवी दिमाग कैसे उसका मार्गदर्शन कर सकता है? इसके अलावा, उस दिल का क्या फायदा जिसका मार्गदर्शन करने वाला कोई दिमाग न हो? यह कहना कि यूरोपीय सोशल-डेमोक्रेसी या अलग-अलग प्रकार के सरमायदारी समाजवाद हमारा मार्गदर्शन करने वाला दिमाग बन सकते हैं, इसका मतलब होगा अपने सिर को रेत में गाढ़ देना और मज़दूर वर्ग व लोगों के हितों के खिलाफ़ काम करने की सड़ी-गली परंपरा को जारी रखना। हिन्दोस्तान के कम्युनिस्टों को मज़दूर वर्ग को अपना दिमाग दिलाना होगा, मज़दूर वर्ग के उद्धार के संघर्ष का मार्गदर्शन करने के लिये उसे हिन्दोस्तानी सिद्धांत और दर्शनशास्त्र से लैस करना होगा। मज़दूर वर्ग या तो अपने दर्शनशास्त्र पर अपना अधिकार जमाये या फिर सरमायदार वर्ग को यूरोपीय दर्शनशास्त्र के भजन गाने, मज़दूर वर्ग को निहत्था करने तथा समाज को हमेशा के लिये गुलामी में रखने की पूरी छूट दे। हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों को उस यूरोकेन्द्रवादी दबाव के खिलाफ़ अडिगता से संघर्ष करना होगा, जिसके अनुसार यूरोपीय और अमरीकी पाठ्य और अन्य संस्थानों से पैदा होने वाली विचार-वस्तु ही एकमात्र मूल्यवान है और सबसे अगुवा भी।

पूर्ववाद का तथाकथित सिद्धांत यह इनकार करता है कि हिन्दोस्तानी दर्शनशास्त्र जैसी कोई चीज भी है। पूर्ववाद का सिद्धांत हिन्दोस्तानी दर्शनशास्त्र को आध्यात्मिकता तक सीमित कर देता है, और भौतिकवाद के मूलतत्व का विरोध करता है, उस निष्कर्ष का विरोध करता है कि

प्रत्येक समाज खुद को "खास विचार-वस्तु" प्रदान करता है। हिन्दोस्तानी दर्शनशास्त्र को देशी और विदेशी पंडितों की जिज्ञासा का शिकार बनाये रखने की बजाय, हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों को, क्रांतिकारी आंदोलन के विकास के अभिन्न भाग बतौर, हिन्दोस्तानी सिद्धांत और दर्शनशास्त्र का विकास करना होगा।

अंतरराष्ट्रीय तौर पर, संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट और मज़दूर आंदोलन के आम अनुभव का मूल्यांकन करते हुये, यह कहा जा सकता है कि कम्युनिस्टों की दार्शनिक चेतना मार्क्सवाद-लेनिनवाद से आगे विकसित होकर समकालीन मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा बन गयी है। परन्तु समकालीन मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा लेनिनवाद का खण्डन नहीं है, जिस तरह लेनिनवाद भी मार्क्सवाद का खण्डन नहीं था। दोनों मिलकर, हठधर्म नहीं बल्कि कार्य के मार्गदर्शक हैं। हिन्दोस्तानी क्रांति का मार्गदर्शन करने वाले दर्शनशास्त्र और सिद्धांत का विकास, हिन्दोस्तान और दुनिया के वर्तमान मज़दूर वर्ग आंदोलन के साथ नज़दीकी के संबंध बनाकर होगा। फिर भी, तरह-तरह की सोशल-डेमोक्रेटिक और मौकापरस्त धाराओं का हठवाद, इस काम को नष्ट करने के लिये बहुत दबाव डाल रहा है।

इस क्रांतिकारी सिद्धांत का मुख्य दुश्मन आज भी दक्षिणपंथी मौकापरस्ती है, वे सोशल-डेमोक्रेटिक विचार जो मज़दूर वर्ग के वर्ग संघर्ष को सरमायदारों की ज़रूरतों के अधीन करने की कोशिश करते हैं। आज दक्षिणपंथी मौकापरस्ती, उदारीकरण और निजीकरण की विश्व सरमायदार की ज़रूरतों के अनुसार खुद को ढाल रही है। बीते 50 वर्षों से वह ऐसा ही कर रही है और तब तक ऐसा करती रहेगी जब तक दुनिया का श्रमजीवी वर्ग पूरी तरह निहत्था नहीं हो जाता, या जब तक दुनिया का श्रमजीवी वर्ग अपने सरमायदारी झूठे ज़मीर का मुकाबला नहीं करता है और हिन्दोस्तानी सिद्धांत व दर्शनशास्त्र का नवनिर्माण और आधुनिकीकरण नहीं किया जाता है, तथा उसे सामयिक नहीं बनाया जाता है। इस क्रांतिकारी नवनिर्माण और विकास के साथ, वर्तमान अवधि का ढोंग व मसखरापन समाप्त होगा।

समाजवाद और कम्युनिज़्म के खिलाफ़ साज़िश सिर्फ मार्क्सवाद को एक उदारतावादी विचारधारा बतौर, उसके क्रांतिकारी वर्ग सारतत्व से वंचित विचारधारा बतौर प्रस्तुत करना ही नहीं है, बल्कि मार्क्सवाद को धर्मशास्त्रवादी भावना बतौर सामाजिक विचारधारा में अंतिम सत्य, महज़ एक मार्क्सवादी रूढ़ीवाद के रूप में प्रस्तुत करना भी है। यह साजिश मार्क्सवाद को लेनिनवाद का विरोधी बताता है और लेनिनवाद को समकालीन मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा के विरोध में प्रस्तुत करता है।

यह महत्वपूर्ण है कि बीते छः वर्षों में काफी सारी पार्टियों ने, जो पहले खुद को कम्युनिस्ट कहलाती थीं, अपना नाम बदल लिया है और अब खुद को "अच्छी", उदारवादी सोशल-डेमोक्रेटिक पार्टियां बतौर पेश कर रही हैं। सरमायदारी शैली के अनुसार ये पार्टियां ऐसा दिखावा कर रही हैं कि उनमें कोई वर्ग-विशेष सारतत्व नहीं है, कोई राष्ट्रीय सारतत्व नहीं है, परन्तु वास्तव में उनमें कोई क्रांतिकारी वर्ग-विशेष सारतत्व नहीं है। साथ ही साथ, कुछ ऐसी भी पाटियां हैं जिन्होंने अपने नाम तो नहीं बदले पर उपरोक्त पार्टियों की तरह उन्होंने भी "अच्छे", शांतिपूर्ण, उदारतावादी कम्युनिस्टों का रूप धारण कर लिया है, जिनके साथ साम्राज्यवाद, सरमायदारों और दुनिया के प्रतिक्रियावादियों का "मिलकर चलना" मुमकिन है। मिसाल के तौर पर, अप्रैल 1995 में माकपा के महाअधिवेशन में रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.आर.एफ.) के नेता ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया, जिसके अनुसार दुनिया की 21 मुख्य कम्युनिस्ट पार्टियों ने श्रमजीवी अधिनायकत्व की धारणा को त्याग दिया है। दूसरे शब्दों में, उनके अनुसार कम्युनिज़्म मज़दूर वर्ग के संपूर्ण उद्धार की शर्त नहीं है बल्कि मात्र एक नीतिगत उद्देश्य है। मज़दूर वर्ग के संपूर्ण उद्धार की शर्त बतौर कम्युनिज़्म की स्थापना सिर्फ श्रमजीवी क्रांति और श्रमजीवी अधिनायकत्व के ज़रिये ही हो सकती है। नीतिगत उद्देश्य बतौर कम्युनिज़्म श्रमजीवी क्रांति और श्रमजीवी अधिनायकत्व के खिलाफ़ है। नीतिगत उद्देश्य बतौर कम्युनिज़्म सरमायदारों के अधिनायकत्व को मानव सभ्यता की अंतिम कृति मानकर, उसे अपरिवर्तनशील और चिरकालीन मानकर, उसे स्वीकार कर लेता है।

इस संदर्भ में, देखा जाये तो सभी प्रकार के अधिनायकत्वों का विरोध करने का जो रवैया पेश किया जाता है, वह सिर्फ एक धोखा है, वह मज़दूर वर्ग की मुक्ति के संघर्ष के साथ विश्वासघात और दगाबाज़ी है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब सी.पी.आर.एफ. ने डूमा में सबसे अधिक सीटों पर कब्ज़ा कर लिया, तो समाचार सूत्रों के अनुसार, क्लिंटन प्रशासन ने "रूस में कम्युनिस्टों की चुनावी जीत का अवमूल्यन कर दिया और ऐलान कर दिया कि पार्टी की नयी नस्ल के लोग 'पहले के सर्वसत्तावादी बोल्शेविक नहीं हैं'।"

समकालीन मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा हिन्दोस्तानी सिद्धांत की रचना के लिये मार्गदर्शक है। लेनिन का निष्कर्ष कि "... सही क्रांतिकारी सिद्धांत ... एक हठधर्म नहीं है बल्कि एक सच्चे माइने में जनसामूहिक और क्रांतिकारी आंदोलन की व्यवहारिक कार्यवाई के साथ निकट संबंध बनाकर ही अपना अंतिम आकार धारण करता है", इसका मतलब यह है कि वास्तविक क्रांतिकारी और वैज्ञानिक सिद्धांत वर्तमान से शुरू हो कर व वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हुये ही विकसित हो सकता है। हिन्दोस्तानी सिद्धांत की रचना करने का हमारा काम शुरू हो चुका है। इस समय हिन्दोस्तानी क्रांतिकारी आंदोलन सरमायदारों के प्रभाव में है। क्रांतिकारी सिद्धांत से मार्गदर्शित होना तो दूर, इस समय मज़दूर वर्ग अपने वर्ग के दुश्मनों के हितों से मार्गदर्शित है। सरमायदार अनेक गुटों में बंटे हुये हैं। ये गुट आपस में लड़ रहे हैं और अपनी-अपनी छावनियों की विभाजन रेखाओं के अनुसार मज़दूर वर्ग और मेहनतकशों को बांट रहे हैं और इस प्रकार, क्रांतिकारी आंदोलन में तबाही मचा रहे हैं। सरमायदारों में बंटवारे से वस्तुगत तौर पर, मज़दूर वर्ग को आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। परन्तु क्रांतिकारी हिन्दोस्तानी सिद्धांत की गैर-मौजूदगी में, मज़दूर वर्ग ही बंट जाता है और उसका मुक्ति आंदोलन कुछ समय के लिये लकवाग्रस्त हो जाता है।

बीसियों कम्युनिस्ट पार्टियां और दल मौजूद हैं, कुछ बड़ी और अनेक छोटी, जो मज़दूर वर्ग आंदोलन में बहुत सारे सिद्धांतों को फैलाती हैं।

इनमें कुछ सिद्धांत मज़दूर वर्ग के हितों के विपरीत हैं जबकि कुछ और सिद्धांत अभ्यास से इतने कटे हुये हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा वैचारिक गड़बड़ी फैलाने के सिवाय कुछ और नहीं करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों और दलों के अलावा, कांग्रेस (इ) भी है जो सोशल-डेमोक्रेटिक पार्टी है। कई समाजवादी पार्टियां भी मज़दूर वर्ग आंदोलन पर अपना प्रभाव डालती हैं और कुछ सीधे तौर पर प्रतिक्रियावादी पार्टियां भी मौजूद हैं। सरमायदार इस इंतजाम से बहुत संतुष्ट है। परन्तु इसके बावजूद मज़दूर समय-समय पर विद्रोह करने में सफल होते हैं।

सरमायदारों के अलग-अलग तबके पूरे देश में, नियमित तौर पर, धर्म, इलाका, भाषा, आदिवासी संबंध और जाति के आधार पर भावनायें भड़काते रहते हैं। अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ हिसाब चुकाने और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिशों के तहत, सरमायदार ऐसा करने को अपनी आदत से मजबूर हैं, परन्तु इसके फलस्वरूप लोग इन आधारों पर बंट जाते हैं और उन पर भयानक त्रासदियां थोपी जाती हैं। पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों में जनसंहार, कर्नाटक में तमिलों का कत्लेआम, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों का जनसंहार, बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद पूरे हिन्दोस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम – ये इस प्रकार के खून-खराबे के कुछ गिने-चुने, अतिजघन्य उदाहरण हैं। 1947 में हिन्दोस्तान के बंटवारे के साथ जो प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें सरमायदारों के आपसी झगड़ों की वजह से लाखों-लाखों लोगों का कत्ल किया गया और उन्हें शरणार्थी बना दिया गया, वह प्रक्रिया आज तक जारी है, हमारी जनता पर नयी-नयी व ज्यादा दर्दनाक चोंटें पहुंचाती रहती है और जनसमुदाय को सरमायदारों के पक्ष में बांटती रहती है।

कम्युनिस्ट आंदोलन इस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने और क्रांतिकारी रास्ते पर मज़दूर वर्ग और मेहनतकशों की राजनीतिक एकता बनाने के बजाय, खुद ही सरमायदारों की श्रेणियों की विभाजन रेखाओं के अनुसार बंट गया है। सरमायदारों के इन झगड़ों में, इस या उस पक्ष में फंसने की कम्युनिस्ट आंदोलन में प्रवृत्ति रही है। यहां तक

कि कम्युनिस्ट आंदोलन इस या उस सरमायदारी मोर्चे की हिमायत भी करने लगता है। सैद्धांतिक और संगठनात्मक काम के ज़रिये क्रांतिकारी आंदोलन को विकसित करने पर ध्यान देने की बजाय, कम्युनिस्ट आंदोलन गलत रास्ते पर भटक गया है और पूंजीवादी व्यवस्था के हित में, सरमायदारों के इस या उस तबके की वाहवाही करने लगा है। इसकी वजह से हिन्दोस्तानी क्रांतिकारी आंदोलन एक अंधी गली में जाकर फंस गया है। हिन्दोस्तान की धरती पर कम्युनिज़्म के विकास के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक बतौर, हिन्दोस्तानी क्रांतिकारी सिद्धांत की रचना के काम के ज़रिये ही मज़दूर वर्ग का क्रांतिकारी मुक्ति आंदोलन वर्तमान दर्दनाक हालत से खुद को निकालेगा और अपना लक्ष्य हासिल करेगा।

भाग पांच

हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों की एकता की पुनः स्थापना

साथियों,

इस समय "हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों की एकता की पुनः स्थापना" सबसे ज्वलंत सवालों में से एक है। "हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों की एकता की पुनः स्थापना" – ये शब्द 1964 और उससे पहले से कम्युनिस्ट आंदोलन में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले शब्द रहे हैं। पर इसके बावजूद, हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों से एकता दूर रही है। इस समय यह ज़रूरी है कि सभी हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट स्पष्ट और ठोस रूप से इन शब्दों का मतलब समझें, हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों की एकता की पुनः स्थापना में हिन्दोस्तानी क्रांतिकारी सिद्धांत की रचना की भूमिका को समझें तथा मज़दूर वर्ग के क्रांतिकारी मुक्ति आंदोलन में हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों की एकता बनाने के काम के महत्व को समझें।

1920 के दशक से ही, जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट बड़े या छोटे टुकड़ों में बंटे रहे हैं। वे कम्युनिज़्म के लिये स्थान, जो आज भी मौजूद है, उसको भरने में नाकामयाब रहे हैं। कुछ पार्टियां यह दावा करती हैं कि उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, परन्तु इससे वह स्थान नहीं भरेगा जिसका ख़ालीपन मज़दूर वर्ग आंदोलन और जन आंदोलन इस समय महसूस करते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति का ठोस मूल्यांकन करने और उसके आधार पर इस फूट को समाप्त करने की हालतें पैदा करने की जगह पर बाहरी लोगों द्वारा कहे गये रटे-रटाये नारों व तारीफों से बात नहीं बनेगी।

हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों में फूट, सिद्धांत और विचारधारा के क्षेत्र में उनके बचकानापन का तथा तरह-तरह की सरमायदारी विचारधारा के सामने

उनके घुटने टेकने का लक्षण है। उनका बचकानापन और सरमायदारी विचारधारा के सामने घुटने टेकना, ये मज़दूर वर्ग के स्वतंत्र व सचेत आंदोलन की गति को रोकने वाले मुख्य आत्मगत कारक हैं। यह जन आंदोलन में, खास तौर पर राजकीय आतंकवाद के खिलाफ़ व मानव अधिकारों की हिफाज़त में संघर्ष के अंदर तोड़-फोड़ का भी कारण है। इसी प्रकार, यह ज्ञानोदय के आंदोलन को भी भारी चोट पहुंचाता है। वस्तुगत तौर पर, यह बड़े पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों की हुकूमत को बरकरार रखने के लिये एक बहुत बड़ा सामाजिक सहारा है।

आज का ज्वलंत सवाल सिर्फ यह निर्धारित करना नहीं है कि इस फूट के लिये कौन और क्या कारक जिम्मेदार हैं। मुख्य मुद्दा है इस हालत को बदलना। कम्युनिस्टों की एकता में बहुत बड़ा योगदान देने वाला एक कारक हिन्दोस्तानी सिद्धांत की रचना है। एक और कारक है इस दौर के लिये कम्युनिस्ट आंदोलन की आम कार्य दिशा का विस्तार करना। इसी आम कार्यदिशा के इर्द-गिर्द हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों की एकता को व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है।

एकता के नारे को लेकर सारी दुनिया में तरह-तरह की राजनीतिक ताकतों ने बहुत शोर मचा रखा है और बहुत गलत समझ फैला रखी है। यह एकता का नारा क्या है? इसे बार-बार क्यों उठाया जा रहा है? हिन्दोस्तान में और सारी दुनिया में मज़दूर वर्ग और व्यापक जनसमुदाय क्यों इतनी अडिगता के साथ कम्युनिस्टों की एकता की मांग कर रहे हैं? हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी इस सवाल किस नज़रिये से देखती है?

कम्युनिस्टों की एकता का सवाल क्रांति के पीछे हटने के इस दौर में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, जब अमरीकी साम्राज्यवाद अपनी हुकुमशाही के तहत एक-ध्रुवीय दुनिया की मांग कर रहा है। इसी दौर में रूसी साम्राज्यवाद एक बहु-ध्रुवीय दुनिया की मांग कर रहा है। इस मामले में जर्मनी की अपनी आकांक्षायें हैं और अन्य ताकतों के बारे में भी ऐसा ही कहा जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि आज दुनिया की स्थिति

कुछ ऐसी है कि जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व थी, जब दुनिया को फिर से बांटने का संघर्ष पूरी गंभीरता के साथ शुरू किया गया था। इस समय अमरीकी साम्राज्यवाद एक-ध्रुवीय दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा है। वह अपने पास उपलब्ध सभी शांतिपूर्ण तरीकों के ज़रिये या अगर ज़रूरी हो तो जंग के ज़रिये, अपनी कोशिशों के खिलाफ़ सभी विरोधों को चकनाचूर करने के लिये काम कर रहा है। अमरीकी साम्राज्यवाद ने अपनी "लुभावन और दंड" की नीति और "जिसकी लाठी उसकी भैंस" की नीति को घोषित कर दिया है।

सोशल-डेमोक्रेसी, जो प्रथम विश्वयुद्ध से पहले के दौर में मज़दूर वर्ग का हिरावल दस्ता था, उसने साम्राज्यवाद को अपने इरादे हासिल करने में मदद की। मज़दूर वर्ग और समाज को उस भयानक संकट और जनसंहार के स्थिति से निकालने में अगुवाई देना सोशल-डेमोक्रेसी का काम था। परन्तु इसके बजाय, भयानक अंतर-साम्राज्यवादी प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान सोशल-डेमोक्रेसी ने, "पितृभूमि की रक्षा" के लिये अपने सरमायदारों के साथ हाथ मिला लिया था।

किसी भी कम्युनिस्ट को इस बात को कम करके नहीं आंकना चाहिये कि इस समय, जब दुनिया के सामने एक और सबतरफा संकट है, ऐसे समय पर माकपा, भाकपा और अन्य कम्युनिस्टों ने, अपने मार्गदर्शक सिद्धांत बतौर हिन्दोस्तान की "राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखण्डता" के कार्यक्रम को अपना कर, अपने आप को पितृभूमि की रक्षा के लिये वचनबद्ध कर दिया है। इस सामाजिक उग्रराष्ट्रवादी दृष्टिकोण से खुद को जोड़ कर, वे वर्तमान जटिल परिस्थिति के अंदर, पितृभूमि की रक्षा करने में अपने आप को सरमायदारों के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वे समाज को वर्तमान संकट से निकालने में मज़दूर वर्ग को अगुवाई देने के बजाय, सरमायदारी-जमींदारी समाज की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने एक नये संघ, जो स्वतंत्र और समानतापूर्ण हो, जो अपने सभी घटक राष्ट्रों और आदिवासी लोगों को मान्यता देता हो, बतौर नये हिन्दोस्तानी समाज का निर्माण करने से इनकार कर दिया है।

इन हालतों में कम्युनिस्टों को "राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखण्डता" की कार्यदिशा से नाता तोड़ना होगा। साथ ही साथ, उन्हें वर्तमान संकट से समाज को निकालने के लिये मज़दूर वर्ग को अगुवाई देने के उद्देश्य से, जोशपूर्ण चर्चा और वाद-विवाद, आंदोलनों और संघर्षों का माहौल पैदा करना होगा।

इस समय हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों के सामने एक अत्यंत जटिल और गंभीर समस्या है। आज हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट की स्पष्ट परिभाषा देने की ज़रूरत है, जिसके लिये कम्युनिस्टों और सोशल-डेमोक्रेटों, संशोधनवादियों व मौकापरस्तों के बीच अंतर को स्पष्ट करने की ज़रूरत है। परन्तु यह भेद गुटवादी आधार पर नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों को एक पार्टी में एकजुट करने के लिये काम करना होगा। उसे चर्चा और वाद-विवाद का माहौल तैयार करने के लिये आवश्यक प्रयास करना होगा। उसे बिना अपवाद के, सभी विचारधारात्मक और राजनीतिक ताकतों, सभी कम्युनिस्टों का विश्लेषण करना होगा और यह स्पष्ट करना होगा कि वर्तमान परिस्थिति में उन्हें कौन-सा स्थान लेना चाहिये और क्या भूमिका निभानी चाहिये। पार्टी को "एकता और संघर्ष" का माहौल पैदा करना होगा और इस काम से ध्यान हटाने के लिये हो रहे व्यक्तिगत हमलों तथा सभी कोशिशों के खिलाफ़ संघर्ष करना होगा। उसे उन सभी ताकतों से अपने आप को अलग करना होगा जो चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं और दूसरों को बदनाम करने का अभियान चलाते हैं।

कम्युनिस्ट एकता मज़दूर वर्ग का अधिकार है। क्रांतिकारी हिन्दोस्तानी सिद्धांत की रचना, आम कार्यदिशा की विस्तारपूर्वक प्रस्तुति और मज़दूर वर्ग व जनसमुदाय के विचारधारात्मक और राजनीतिक स्तर को ऊंचा उठाने का जोशीला काम हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों की एकता की पुनः स्थापना में बहुत बड़ा योगदान देगा।

इस समय हिन्दोस्तान में कई ऐसी राजनीतिक ताकतें हैं जो "राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखण्डता" के नारे को एक परम सिद्धांत जैसा मानते हैं। साथ ही, ऐसी भी ताकतें हैं जो समाज को संकट से निकालने के फौरी कार्य को सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं। हिन्दोस्तानी समाज इस समय इन दोनों परस्पर विरोधी मोर्चों के बीच में बंटा हुआ है, जिसमें एक मोर्चा औद्योगिक घरानों और बड़े जमींदारों के हितों को प्रकट करता है तथा दूसरा मोर्चा मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनसमुदाय के हितों को प्रकट करता है। इन दोनों नज़रियों से दो परस्पर विरोधी राजनीतियां पैदा हो रही हैं, और इनमें से एक राजनीति दूसरे को उखाड़ फेंकेगी।

हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरमायदार "राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखण्डता" के नारे के आधार पर हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों व हिन्दोस्तानी मज़दूर वर्ग में फूट की स्थिति को बरकरार न रख सके। उन्हें अपनी एकता की स्थापना करके फासीवाद और जंग की तबाही से बचना होगा। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को कम्युनिस्ट आंदोलन में फूट की स्थिति को बरकरार रखने की सरमायदारों की कोशिशों को नाकामयाब करने के लिये, समाज को संकट से निकालने के उद्देश्य से, सभी हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों और अन्य राजनीतिक ताक़तों के साथ काम करने में खुद को समर्पित करना होगा।

सभी वस्तुएं और घटनाक्रम, जो विकास और गति की स्थिति में हैं, उनकी हालतें, विशेषताएं, आपसी विरोधतायें, "एकता" और "संघर्ष" के ज़रिये प्रकट होती हैं। हिन्दोस्तान एक वर्गों में विभाजित समाज है जो विकास और गति की स्थिति में है। "राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखण्डता" का अनुमोदन करने वाले, समाज को संकट से निकालने का उद्देश्य रखने वालों के विपरीत हैं। हिन्दोस्तान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो वर्गों का विभाजन मौजूद है, वह इन दोनों आपसी विरोधताओं के रूप में प्रकट होता है। "राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखण्डता" का अनुमोदन करने वाले मात्रात्मक परिवर्तन चाहते हैं, यथास्थिति को और

मजबूत करना चाहते हैं। समाज को संकट से निकालने की कोशिश करने वाले इसके बिल्कुल विपरीत हैं, वे ताकतें हैं जो गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहती हैं, यथास्थिति को पूरी तरह चकनाचूर करना चाहती हैं।

हिन्दोस्तान में सभी विचारधारात्मक और राजनीतिक ताकतों को इस ऐतिहासिक विभाजन के प्रति उनके रवैये के आधार पर परखना होगा क्योंकि यह रवैया हिन्दोस्तानी समाज के भविष्य को निर्धारित करेगा। इस ऐतिहासिक विभाजन के ज़रिये प्रतिक्रियावादी ताकतों को अलग करना होगा। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को ऐसा करने के लिये कार्यनीति बनानी होगी। प्रतिक्रियावादी ताकतें ज्यादातर इस या उस नीति के आधार पर, इस या उस "वाद" के आधार पर, मज़दूर वर्ग और समाज में फूट पैदा करने का काम करती हैं और इस तरह पूंजीवादी यथास्थिति को बरकरार रखने के अपने उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करती हैं। इस ऐतिहासिक विभाजन के अनुसार, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी और सभी कम्युनिस्टों के जोशपूर्ण विचारधारात्मक और राजनीतिक काम के ज़रिये, इस फूट को नाकामयाब और खत्म करना होगा।

वी. आई. लेनिन के अनुसार, "विकास आपसी विरोधताओं का 'संघर्ष' है। विकास (उद्भव) की दो मौलिक (या दो संभव? या दो ऐतिहासिक तौर पर देखी जाने वाली?) अवधारणायें हैं : पहली, घटने और बढ़ने और दोहराये जाने के रूप में विकास, और दूसरी, आपसी विरोधताओं की एकता (एक तत्व के दो आपसी विरोधताओं में बंटने और उनके पारस्परिक संबंध) बतौर विकास"।[6] हिन्दोस्तान की हालतों में लेनिन के इस सिद्धांत को लागू करते हुये हम यह देख सकते हैं कि हिन्दोस्तान का विकास इस बात से निर्धारित है कि इस ऐतिहासिक विभाजन में कौन जीत कर आगे निकलता है। अगर "राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखण्डता" का अनुमोदन करने वाले जीतते हैं तो समाज

---

[6] वी. आई. लेनिन, "द्वंद्ववाद के सवाल पर", फिलोसोफिकल नोटबुक संग्रहीत रचनायें, प्रोग्रेस पब्लिशर्स, अंग्रेजी संस्करण, ग्रंथ 38, पृष्ठ 358

का पतन होगा और संकट ज्यादा गहरा व विस्तृत होगा। अगर समाज को संकट से बाहर निकालने के लिये संघर्ष करने वाली ताकतें जीतती हैं तो विकास होगा और समाज की प्रगति का रास्ता खुलेगा। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी और सभी कम्युनिस्ट ताकतों को यह दूसरा परिणाम सुनिश्चित करने के लिये व्यवहारिक कार्यनीतियों को विकसित करना होगा।

लेनिन आगे यह समझाते हैं कि "गति की प्रथम अवधारणा में स्वतः गति, उसकी प्रेरक शक्ति, उसका स्रोत, उसका उद्देश्य अस्पष्ट रहता है (या इस स्रोत को बाहरी बनाया जाता है – मसलन भगवान, कर्ता, इत्यादि)। दूसरी अवधारणा में 'स्वतः' गति के स्रोत के ज्ञान पर मुख्य ध्यान दिया जाता है"।[7] हिन्दोस्तान की हालतों में इसे लागू करते हुए, "राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखण्डता" के समर्थक अपनी "प्रेरक शक्ति", अपने "स्रोत" और "उद्देश्य" को अस्पष्ट रखते हैं जबकि हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के काम को इस समय हिन्दोस्तान और सारी दुनिया में मौजूद यथार्थ हालतों के आधार पर तथा समकालीन मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा के सिद्धांत के अनुसार, पूरी तरह समझाया और उचित ठहराया जा सकता है। अगर हम संघर्ष को सिर्फ "वे गलत हैं" दोहराने तक सीमित रखते हैं और पूरी तरह उनकी आलोचना करके यह नहीं समझाते हैं कि उनके विचारों और अभ्यासों से किस तरह हिन्दोस्तानी समाज को और नुकसान होगा, तो हम ठीक उन्हीं की तरह आचरण करेंगे, "स्वतः गति, उसकी प्रेरक शक्ति, उसका स्रोत और उसका उद्देश्य" को अस्पष्ट रखेंगे। इससे किसी गुणात्मक विकास में योगदान नहीं होगा। वास्तव में इससे यथास्थिति को बनाये रखने में योगदान होगा।

लेनिन साफ-साफ समझाते हैं कि "प्रथम अवधारणा जीवनहीन, फीकी और सूखी होती है।" इसीलिये हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी

[7] उपरोक्त

हठवादी और गुटवादी आधार पर संघर्ष करने के खिलाफ़ है। जबकि, "दूसरी अवधारणा सजीव है। सिर्फ दूसरी अवधारणा ही हर मौजूद वस्तु की 'स्वतः गति' की कुंजी पेश करती है : सिर्फ दूसरी अवधारणा ही 'छलांगों', 'निरंतरता-भंग', 'अपने विपरीत में परिवर्तित होना', पुराने के नाश और नये के जन्म की कुंजी पेश करती है।" इसीलिये हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी वर्ग के दुश्मन को हराने के उद्देश्य से, अहम विषयों पर चर्चा, वाद-विवाद और आंदोलनों को वस्तुगत आधार पर स्थापित कर रही है। ऐसा करने से कम्युनिस्ट आंदोलन के विकास में "छलांगों" और "निरंतरता-भंग" में योगदान दिया जायेगा।

ऐसा किया जा सकता है क्योंकि "आपसी विरोधताओं की एकता (संयोग, पहचान, समान क्रिया) सशर्त, अस्थायी, तुलनात्मक है। आपसी विरोधताओं का संघर्ष परम है, जैसे कि विकास और गति परम हैं।" "पारस्परिक विरोधतायें" अपने विकास के दौरान ही अपने सच्चे रंग प्रकट करती हैं, हालांकि उनकी मौजूदगी का आधार शुरू में ही देखा जा सकता है, जैसे कि हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी ने इस समय दो विरोधताओं की मौजूदगी को पहचान लिया है। कम्युनिस्टों की एकता बनाने के उद्देश्य पर डटे रह कर और समाज को संकट से निकालने के इरादे से काम करने वालों को एकजुट करके उचित कार्यनीति बनाकर, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी न सिर्फ हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों की एकता को पुनः स्थापित कर सकेगी, बल्कि उन ताक़तों को अलग कर के हरा भी सकेगी, जो पूंजीवादी यथास्थिति को बरकरार रखने के लिये "राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखण्डता" के नारे का इस्तेमाल कर रही हैं।

"हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों की एकता की पुनः स्थापना", इन शब्दों में हल करने के लिये प्रथम समस्या यह विस्तार करना, समझाना और पहचानना है कि "राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखण्डता" का नारा एक पुराना नारा है, ऐसा नारा जो हिन्दोस्तान में कम्युनिस्ट और मज़दूर आंदोलन की प्रगति के लिये तबाहकारी है। इस नारे के प्रतिक्रियावादी स्वभाव को

पहचान कर, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को उसे हराने के लिये उचित कार्यनीति, काम के तरीकों और नारों की रचना करनी होगी। इस सुनियोजित, क्रमबद्ध और सचेत रूप से किये गये, पुराने के विनाश से नये का जन्म होगा। इस योजना को लागू करने के दौरान, कम्युनिस्टों की एकता की पुनः स्थापना होगी।

क्या पुराना है और किस चीज पर काबू पाना है, इस सवाल के निपटारे के बाद हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को साफ़ तौर पर निर्धारित करना होगा कि पुरानी चीज पर काबू पाना किसके हित में होगा। क्या यह मज़दूर वर्ग, हिन्दोस्तान के मेहनतकशों और मध्यम श्रेणी के हित में होगा? क्या यह उन ताकतों के हित में होगा जो कश्मीर और पूर्वोत्तर में अपनी राष्ट्रीय मुक्ति के लिये संघर्ष कर रही हैं? पुरानी चीज पर काबू पाने के इस एक संघर्ष में इन सभी ताकतों की एकता बनाने, सभी संघर्षरत ताकतों के सम्मिलन का एक बिंदु निर्धारित करने की योजना को साकार रूप देना होगा। दूसरे शब्दों में, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की यह जिम्मेदारी है कि पुरानी चीज को अधिक से अधिक हद तक अलग करके, समाज की प्रगति को रोकने वाले तत्वों पर वार करके, इन सभी संघर्षरत ताक़तों को एकजुट किया जाये।

यह स्पष्ट है कि शरुआती तौर पर, उन सभी को जो खुद को हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट कहते हैं, और सभी राजनीतिक ताक़तों को, चाहे उनकी विचारधारा कुछ भी हो, समाज को संकट से निकालने के लिये काम करने वालों का हमसफर मानना होगा। वे विरोधताओं की एकता हैं और शुरू में वे आपसी विरोधताओं के संघर्ष की अवस्था में नहीं हैं। आपसी विरोधतायें शोषक और शोषित हैं, अत्याचारी और उत्पीड़ित हैं; संक्षेप में, सरमायदार और श्रमजीवी हैं।

वे ताक़तें जो आपसी विरोधताओं की एकता की अवस्था में, यानी एक सशर्त, अस्थायी, परिवर्तनशील, तुलनात्मक संबंध में हैं, उन्हें तभी पहचाना जा सकता है अगर उनके संयोग, पहचान, समान क्रिया पर

पूरी तरह रोशनी डाली जाये, उसे समझाया जाये और उस पर विस्तार किया जाये। दूसरे शब्दों में, सचेत रूप से नियोजित विभिन्न आंदोलनों और संघर्षों के दौरान, पूर्ण चर्चा और वाद-विवाद का माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ, वे ताक़तें जो आपसी विरोधताओं की एकता की अवस्था में हैं, उन्हें तब तक नहीं पहचाना जा सकता है जब तक आपसी विरोधताओं के साथ उनकी तुलना और भेद न किया जाये। यानी कि, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी उन सबको नज़रअंदाज नहीं कर सकती, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती, जो कम्युनिस्ट आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने पर तुले हुये हैं, जो सोशल-डेमोक्रेसी के साथ समझौता कर रहे हैं और उसके बारे में भ्रम पैदा कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, एकता की विषय-वस्तु को तब तक समझा नहीं जा सकता है जब तक हरेक मौजूद वस्तु की आत्मगति का परीक्षण नहीं किया जाता। इन वस्तुओं में वे सब शामिल हैं जो सशर्त, अस्थायी, परिवर्तनशील, तुलनात्मक हैं और जो अपने विकास के दौरान अवश्य ही कट्टर आपसी विरोधताओं में बंट जायेंगी।

हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों की एकता की पुनः स्थापना चाहने का मतलब है एक ऐसी अवस्था को स्थापित करना जो सशर्त, अस्थायी, परिवर्तनशील, तुलनात्मक है और जो अवश्य ही अपने विकास के दौरान आपसी विरोधी चीजों में बंट जायेंगी। जैसे-जैसे यह कार्यक्रम लागू किया जायेगा, वैसे-वैसे वे तत्व सामने आयेंगे जो इस संघर्ष को अंत तक नहीं ले जाना चाहेंगे। ये तत्व पूंजीवादी यथास्थिति को बनाये रखते हुये, समाज को संकट से बाहर निकालने की एक योजना पेश कर सकते हैं, हालांकि यह एक भ्रम होगा। अंत में संघर्ष अवश्य ही समाजवादी और समाजवाद-विरोधी ताक़तों के बीच में होगा।

1964 में हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट आंदोलन में जो बंटवारा हुआ था, उससे आपसी विरोधता पैदा नहीं हुई। वह बंटवारा आंदोलन के विकास का नहीं, बल्कि उसके पतन का प्रतिबिंब था। वह बंटवारा हठधर्मी और गुटवादी असूलों के आधार पर था। वह सिर्फ घटने या बढ़ने के तौर

पर, उसी चीज को दोहराने के तौर पर एक विकास था। वह कम्युनिस्ट आंदोलन के लिये तबाहकारी था, क्योंकि इस समय उन कम्युनिस्टों की संख्या कम नहीं है जो "राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखण्डता" के नारे का बड़े उत्साह से समर्थन करते हैं। यह एक सोशल-डेमोक्रेटिक कार्यक्रम है, "पितृभूमि की रक्षा" के यूरोपीय सोशल-डेमोक्रेटिक नारे का नया रूप है, अंतर-साम्राज्यवादी जंग का उग्रराष्ट्रवादी ऐलान है और, और कुछ नहीं तो, ये पूंजीवादी यथास्थिति की सेवा में एक नारा है।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी कम्युनिस्टों की फूट और बंटवारे को तथा कम्युनिस्टों के पतन को इस नज़रिये से देखती है कि सभी ताक़तों को एक कार्यक्रम के इर्द-गिर्द एकजुट करना है। वह मानती है कि इस पतन का कारण सोशल-डेमोक्रेसी के साथ कुछ कम्युनिस्टों का समझौता करना है। यह समझौता उन संपत्तिवान वर्गों के दबाव में आकर किया जा रहा है, जो पूंजीवाद के विस्तार से बहुत उत्साहित हो गये हैं और उसमें अपना भविष्य पाते हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन में बंटवारे और पतन के कारणों में से एक कारण, आत्मगत कारण, चेतना से जुड़ा कारण, यह पहचानने से इनकार करना था कि 1962-64 के दौर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की समस्याओं की वजह उस हालत के लिये ज़रूरी काम में जुटकर मज़दूर वर्ग के स्वतंत्र कार्यक्रम का बुलावा देने में उसकी नाकामयाबी थी। भाकपा का रवैया कांग्रेस पार्टी के रवैये के दबाव के तले था, खासतौर पर चीन-हिन्दोस्तान जंग के विषय पर, जिसमें उसने "पितृभूमि की रक्षा" के लिये श्रमजीवी अंतरराष्ट्रीयतावाद का त्याग कर अपने आप को बदनाम किया था।

30 से अधिक वर्ष बाद, माकपा, जो 1964 में भाकपा से अलग हो गयी थी, आज वह "राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखण्डता" का सबसे बड़ी हिमायती है। यह दुख की बात है कि भाकपा आज तक अपने काम को कांग्रेस पार्टी के उद्देश्यों के साथ तालमेल में तय और समायोजित करती है। ऐसा रवैया प्रतिक्रियावादी है, आगे बढ़ने की दिशा में पहल लेने वाला नहीं है। यह रवैया हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति की यथार्थ

हालतों का विश्लेषण करने की नाकामयाबी से, यानी कि तत्कालीन और रणनैतिक तौर पर क्रांति के पड़ाव को निश्चित रूप से निर्धारित करने में नाकामयाबी से पैदा होने वाली मुश्किलों पर आधारित है।

जब 1962-64 के दौरान भाकपा में मतभेद पैदा हुये तो वे सारतत्व से संबंधित मतभेद थे। उन्हें मार्क्सवादी-लेनिनवादी परंपरा के अनुसार पार्टी के अंदरूनी तरीकों से हल किया जा सकता था। परन्तु, ठेठ सोशल-डेमोक्रेटिक तरीके से, संघर्ष हटकर इस विषय पर आ गया कि संघर्ष का एक या दूसरा तरीका मंजूर है या नहीं, सरमायदारों का एक या दूसरा तबका "प्रगतिशील" है या नहीं। संघर्ष के तरीकों में अंतर के आधार पर मानसिक वर्गीकरण करके कट्टर आपसी विरोधताओं को पैदा करना बहुत आसान था, और ऐसा करते हुये सारतत्व में अंतर पर पर्दा डाल दिया गया। ऐसा होना कोई संयोग नहीं था क्योंकि जो नेता भाकपा के नेतृत्व पर विश्वासघात का आरोप लगा रहे थे, उनका सारतत्व भी मौलिक तौर पर भाकपा के नेताओं जैसा ही था। माकपा एक गुट मात्र था और आज तक ऐसा ही रहा है। सभी कम्युनिस्टों और जनवादी ताक़तों के लिये एक ही सांझा कार्यक्रम पेश करने का मौका चूक गया। उसकी जगह पर, राजनीतिक ताक़तों में फूट और बंटवारा फैल गया तथा मज़दूर वर्ग ने काफी लंबे अर्से के लिये अपनी अगुवा भूमिका खो दी।

अगर हम क्रांतिकारी द्वंद्ववाद के नज़रिये से हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट आंदोलन को परखते हैं तो हम यह देखते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), जिसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कट्टर आपसी विरोधता होना था, उस रूप में उभर कर नहीं आयी। उसके पास वह नया सारतत्व नहीं था और उस नये सारतत्व के अनुकूल नये ढांचे नहीं थे। खुद को मार्क्सवादी-लेनिनवादी और माओवादी कहलाने वाले अनेक दलों ने भी नये सारतत्व को विकसित करने का प्रयास नहीं किया। संसदीय संघर्ष बनाम क्रांतिकारी हिंसा जैसे संघर्ष के विरोधी तरीकों से इस नये सारतत्व की रचना नहीं होती है। संघर्ष के तरीकों को सारतत्व के अधीन होना चाहिये। नये बाहरी रूप ठीक इसीलिये निर्णायक बन जाते हैं क्योंकि नये सारतत्व

को शामिल करने की फ़ौरी ज़रूरत पैदा होती है। बाहरी रूप और सारतत्व के बीच में द्वंद्वात्मक संबंध है। पुराने ढांचे के साथ टिके रहने पर नये सारतत्व के विकास में रुकावट आ सकती है।

वस्तुगत तौर पर, अपने सारतत्व और संघर्ष के तौर-तरीकों में, माकपा ठीक भाकपा जैसी ही थी। भाकपा के साथ उसकी एकता, जिसे उसकी कट्टर आपसी विरोधता होनी थी, सशर्त, अस्थायी, परिवर्तनशील, तुलनात्मक नहीं थी, बल्कि अपरिवर्तनशील थी। अगर माकपा नयी होती तो उसकी एकता सशर्त, अस्थायी, परिवर्तनशील, तुलनात्मक होती और कम्युनिस्ट ताक़तों में फूट नहीं पड़ती। दायें व "बायें" से आने वाले सोशल-डेमोक्रेटिक और संशोधनवादी तत्वों के बीच में फूट पड़ जाती। परन्तु यह ढोंग करके कि वह नयी थी, माकपा ने जबरदस्ती बंटवारा करवाया, जिससे विकास नहीं हुआ, कट्टर आपसी विरोधतायें पैदा नहीं हुईं, बल्कि और पतन हुआ।

हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों की एकता की पुनः स्थापना के रास्ते में रुकावट यह कट्टर आपसी विरोधता है, भाकपा, माकपा तथा कुछ अन्य ताक़तों का यह पुराना सारतत्व है, जिन्होंने "राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखण्डता" के कांग्रेस (इ) के नारे को समर्थन दिया है। पुराने बाहरी रूपों से इस रुकावट को और मदद मिलती है। पुराने बाहरी रूपों में एक है जोरदार चर्चाओं और वादविवाद की जगह पर, दुनिया के एक कोने से दूसरे तक अफ़वाहें फैलाना और गपशप चलाना। इनके द्वारा मज़दूर वर्ग के लक्ष्य को त्याग देने के सिद्धांत और अभ्यास बतौर "जनवादी धर्मनिरपेक्ष मोर्चा" के कार्यक्रम को बढ़ावा देने, कम्युनिस्टों के बीच में और अधिक फूट व बंटवारा पैदा करने तथा सोशल-डेमोक्रेसी के इस या उस तबके के साथ समझौता करके उसके तलवे चाटने की बेहद बेईमानी से इस रुकावट को मदद मिलती है।

हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों की एकता की पुनः स्थापना पुराने सारतत्व और बाहरी रूपों से नहीं होगी। इस या उस पार्टी या दल के मानसिक

वर्गीकरण के आधार पर, उम्मीदों पर खरा न उतरने का दोषी ठहराने से या "असली" कम्युनिस्ट पार्टी कहलाने योग्य न होने का दोषी ठहराने से यह एकता नहीं बनेगी। इसके विपरीत, पुराने सारतत्व और तरीकों को ठुकरा कर तथा समाज को संकट से बाहर निकालने के लिये चर्चा, वादविवाद और आंदोलन चला कर, कट्टर आपसी विरोधताओं को स्पष्ट किया जा सकेगा। हर राजनीतिक ताक़त का वस्तुगत तौर पर विश्लेषण करके, समाज की समस्याओं के समाधान में सहायता करने वाले सभी बातों व कार्यों के आधार पर एकता बनाकर, ऐसा करना होगा।

समाज को संकट से बाहर निकालने की योजना ही नयी और सबसे आधुनिक है, और इसे एक चीज के विभाजन से पैदा होने वाली आपसी विरोधताओं और उनके बीच के संबंध के विकास में देखा जा सकता है। यह लोकतांत्रिक नव-निर्माण, पूंजीवादी व्यवस्था के तख्तापलट के ज़रिये उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष को पूरा करने की योजना है। पुराने को ठुकराने के इस काम, पुराने सारतत्व और पुराने तौर-तरीकों को पूरी तरह से त्यागने के इस संघर्ष से एक नया विकास होगा, पुराने से नये तक एक "छलांग" होगी, पुराने आंदोलन के प्रतिगमन को "तोड़ा" जायेगा और एक उच्चतर स्तर की कट्टर आपसी विरोधताओं की एकता पैदा होगी।

भाग छः

राजनीतिक एकता पर

राजनीतिक एकता बनाने की कोशिश करते हुये, कम्युनिस्टों को इस सवाल को मनमाने या सरसरे ढंग से नहीं देखना चाहिये। कम्युनिस्टों को इस सवाल को समाज के भविष्य के साथ तथा समाज को संकट से बाहर निकालने की ज़रूरत के साथ जोड़ना होगा और इस आधार पर सभी राजनीतिक ताक़तों की एकता बनाना होगा। इस एकता को मुख्यतः बुनियाद से, परन्तु साथ-साथ ऊपर से भी बनाना होगा।

कम्युनिस्टों को पूंजीवादी विकास के सवाल को उठाना होगा, यह दिखाने के लिये कि यह पूंजीवादी विकास ही समाज को एक संकट से दूसरे की ओर घसीट रहा है। पूंजीवाद के खिलाफ़ सभी ताक़तों को लामबंध करना होगा। ऐसा कोई भ्रम नहीं हो सकता है कि पूंजीवाद कृषि क्रांति को मदद देगा या उपनिवेशवाद और सामंतवाद के अवशेषों को खत्म करेगा या केन्द्रीय राज्य, जो उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी है, पर अंकुश लगायेगा। ऐसा कोई भ्रम नहीं हो सकता है कि पूंजीवाद महिलाओं के दमन को खत्म करेगा या आदिवासियों के हित में काम करेगा, जातिवाद और साम्प्रदायिकता को खत्म करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा या सभी राष्ट्रीयताओं के मुक्त और समानतापूर्ण संघ की हालतें पैदा करेगा।

अपने राजनीतिक काम में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी किसी भी राजनीतिक पार्टी या दल की उपेक्षा नहीं कर सकती है। कम्युनिस्टों को प्रथम मोर्चे (कांग्रेस इ), दूसरे मोर्चे (भाजपा), तीसरे मोर्चे (भाकपा, माकपा तथा अन्य) और सभी अन्य राजनीतिक ताक़तों पर ध्यान रखना होगा। इन तीनों मोर्चों की कड़ी आलोचना करनी होगी, क्योंकि ये केवल संसदीय गठन हैं जिन्होंने सभी समस्याओं को "नीतिगत उद्देश्यों" तक सीमित कर रखा है। हिन्दोस्तान का मज़दूर

वर्ग, बाकी दुनिया के मज़दूरों की तरह, कम्युनिस्टों से यह जानने का इंतजार कर रहा है कि वर्तमान हालतों के अनुकूल कार्यक्रम, समाज की समस्याओं को हल करने वाला कार्यक्रम विस्तृत रूप में क्या होगा। इस कार्यक्रम को मज़दूर वर्ग और आम जनसमुदाय के अनुभव से निकलना होगा। मज़दूर आत्मगत पक्ष, चेतना और दृष्टि की मांग कर रहे हैं। ऐसी दृष्टि सिर्फ तीनों मोर्चों की आलोचना पर आधारित नहीं हो सकती, हालांकि इस आलोचना को नियमित काम का हिस्सा होना पड़ेगा।

मज़दूर वर्ग को ऐसी चेतना की ज़रूरत है जो मुक्ति के आंदोलन के लक्ष्य के अनुकूल, यथार्थ हालतों के ठोस विश्लेषण पर आधारित होगी। मज़दूर वर्ग को आत्मगत पक्ष, चेतना और संगठन की हालत तथा इन्हें वर्तमान ज़रूरतों के अनुरूप लाने के लिये आवश्यक काम की जानकारी होनी चाहिये। इस कार्यक्रम, इस दृष्टि, इस चेतना को तैयार करके, कम्युनिस्ट क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष में भाग लेने के दौरान, अपने और जनसमुदाय के संगठनों को मज़बूत करेंगे। मज़दूर वर्ग और आम जनसमुदाय को, समाज को संकट से बाहर निकालने के संघर्ष को वास्तव में नेतृत्व देकर, कम्युनिस्टों के विचारों की ओर आकर्षित करना होगा। अगर आज कम्युनिज़्म मानसिक श्रेणियां और काल्पनिक हव्वा बनाने में व्यस्त रहे, अगर वह आत्मवाद और संकीर्णतावाद की दलदल में फंसा रहे, अगर वह मांग करे कि कार्य में किसी भी प्रकार की एकता बनाने से पहले, सभी उसकी बात मानें और बिना किसी शर्त के उसके कार्यक्रम को अपनायें, तो आज कोई कम्युनिज़्म को मान्यता नहीं देगा।

इस दौर के लिये, हिन्दोस्तानी सिद्धांत को विकसित करने के सर्वव्यापी काम और चल रहे विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष के काम तय करके, और कम्युनिस्टों की एकता की पुनः स्थापना के काम की योजना को निर्धारित करके, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को सभी संघर्षरत ताक़तों की राजनीतिक एकता बनाने की कोशिश करनी होगी और उन संघर्षों की ओर बहकाये जाने से इनकार करना होगा, जो इस

राजनीतिक एकता के लिये ख़तरनाक हैं, खास तौर पर जो अलग-अलग कार्यक्रमों या विचारधारात्मक रवैयों के आधार पर लोगों को बांटते हैं।

हम कम्युनिस्टों को लोगों को यह समझाना होगा कि जहां तक वर्गों का सवाल है, समाज में दो कार्यक्रम नहीं हो सकते। जब सरमायदार सत्ता में है और व्यवस्था पूंजीवादी है, जैसा कि इस समय है, तो एक ही कार्यक्रम हो सकता है। जब मज़दूर वर्ग सत्ता में होगा और व्यवस्था समाजवादी होगी, तब भी एक कार्यक्रम ही होगा। इन कार्यक्रमों में समाज में वास्तविक तौर पर प्रचलित विचारों और राजनीतिक कार्यदिशाओं की झलक होती है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, अपने खुदगर्ज़ कारणों के लिये, अपने कार्यक्रमों के वर्ग चरित्र को छिपाने की कोशिश करती हैं। वे लोगों को बुद्धू बनाने की कोशिश करती हैं, यह दिखावा करती हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था अलग-अलग कार्यक्रमों के बीच स्पर्धा पर निर्भर है, और कि लोगों को "सबसे अच्छा" कार्यक्रम चुनने की आज़ादी है। वास्तव में संघर्ष पूंजीवाद और समाजवाद के बीच है। आज की परिस्थिति में ये दो व्यवस्थाएं ही संभव हैं। परन्तु पूंजीवाद का समय खत्म हो चुका है और क्रांति के ज़रिये इसकी जगह समाजवाद को लाने की ज़रूरत है। समाज के विकास में अगले चरण बतौर समाजवाद ही एकमात्र विकल्प हो सकता है।

नरसिम्हा राव की कांग्रेस (इ) का यह दावा है कि उसका नीतिगत उद्देश्य है हिन्दोस्तानी अर्थव्यवस्था में नई जान डालना, ग्रामीण और शहरी गरीबों की हालतों को सुधारना। राव यह दावा करता है कि उदारीकरण और निजीकरण से औद्योगिक सवंर्धन होगा और बेरोज़गारों को नौकरियां मिलेंगी। यह दिखावा किया जाता है कि कांग्रेस (इ) का कार्यक्रम सभी वर्गों के हित में है, खास तौर पर मज़दूर वर्ग और किसानों और मध्यम श्रेणी के लिये। राव यह तर्क पेश करता है कि "गरीबी उन्मूलन" के लिये पैसा लगाने से दौलत नहीं पैदा होती है और राजकोष दिवालिया हो जाता है, अतः उन हालतों को पैदा करने पर जोर देना होगा जिनमें लोगों को नौकरी मिलेगी। यह दावा किया जाता है कि उदारीकरण और निजीकरण से ऐसी हालत पैदा होगी। बहरहाल, राव

को "गरीबी उन्मूलन" के लिये पैसा बांटने से कोई ऐतराज़ नहीं है, अगर उससे वोट बैंक सुनिश्चित हो सके और इन कार्यक्रमों से मुख्य तौर पर लाभ प्राप्त करने वाले निहित स्वार्थों का भला होता रहे।

यह पूरा वाद-विवाद कि क्या राज्य को "गरीबी उन्मूलन" पर पैसा खर्च करना चाहिये या नहीं, क्या इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा या नहीं, या फिर क्या राज्य को "बाज़ार की शक्तियों" को खुली छूट देनी चाहिये और "गुप्त हाथ" से "गरीबी उन्मूलन" हो जायेगा, यह हिन्दोस्तान और दुनिया में एक पुराना वाद-विवाद है। जीवन का अनुभव और हमारा सिद्धांत हमें सिखाता है कि यह भटकाववादी वाद-विवाद है। मुद्दा यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती और न ही करती है। पूंजीवादी व्यवस्था सामंती, उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी प्रभाव को खत्म करने में मदद नहीं देती है। राजकीय इजारेदार पूंजीवाद के चलते, एक तरफ अमीरों के और अमीर होने तथा दूसरी तरफ गरीबों के और गरीब होने की प्रवृत्ति होती है। जब तक यह प्रवृत्ति कायम रहती है तब तक, चाहे "गरीबी उन्मूलन" पर पैसा खर्च किया जाये, यानी निहित स्वार्थ वाले खास ठेकेदारों और बिचौलियों की जेबों को भरने के लिये पैसा खर्च किया जाये या बड़े पूंजीपतियों की सीधी मदद करने के लिये (जिसमें राज्य सारा घाटा अपने ऊपर ले लेता है), पैसा खर्च किया जाये, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता।

इस तरह, कांग्रेस (इ) के कार्यक्रम, जिसके अंदर भी खास तबकों के अपने-अपने हित हैं, के वर्ग चरित्र को छिपाने की कोशिश की जा रही है। उनके कार्यक्रम का वर्ग चरित्र पूंजीवादी व्यवस्था की तथा सामंतवाद और संपूर्ण उपनिवेशवादी विरासत के अवशेषों तथा साम्राज्यवाद की हिफाज़त करना है। वे इस बात को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका वास्तविक कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने का कार्यक्रम है कि राजकोष को हिन्दोस्तानी सरमायदारों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित के लिये लूटा जाये। वे यह छिपाना चाहते हैं कि उनका कार्यक्रम हिन्दोस्तान के मेहनतकशों का शोषण करने का कार्यक्रम है, जो उससे मुनाफ़ा कमाने

वालों के धन का स्रोत है। वे यह छिपाना चाहते हैं कि उनका कार्यक्रम इस शोषण के शिकार बने हुए लोगों के दुख-दर्द को खूब बढ़ाने का कार्यक्रम है। इस संदर्भ में सरमायदारों के जिन तबकों ने कांग्रेस पार्टी पर पैसा लगाया है, उनके हित पूरे हो रहे हैं। कांग्रेस (इ) का कार्यक्रम हिन्दोस्तान के बड़े सरमायदारों की मांग के अनुकूल है। हिन्दोस्तान के बड़े सरमायदार वर्तमान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति का फायदा उठाकर, अंतरराष्ट्रीय मैदान पर एक बड़ा खिलाड़ी बनकर आगे आना चाहते हैं।

जबकि कांग्रेस (इ), भाकपा, माकपा और अन्य पार्टियां यह प्रचार करती रहती हैं कि हिन्दोस्तान के लिये मुख्य ख़तरा भाजपा के "दक्षिणपंथी साम्प्रदायिक अजेंडा" से है, तो दूसरी ओर, भाजपा केंद्र पर सत्ता में आने के लिये गंभीरता से कोशिश करने का दावा कर रही है। भाजपा को जनता के सामने कांग्रेस पार्टी के उत्तराधिकारी बतौर पेश किया जा रहा है। भाजपा अपने लिये एक राष्ट्रवादी पार्टी, जो अकुशलता और भ्रष्टाचार का विरोध करती है, बतौर स्थान बनाने की कोशिश कर रही है। वह कांग्रेस (इ) के कार्यक्रम को विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों अंधाधुंध बेच डालने का कार्यक्रम बताकर, उसकी आलोचना कर रही है।

इसके साथ-साथ, भाजपा स्पष्ट रूप से यह कहने में सावधानी बरत रही है कि वह भी उदारीकरण और निजीकरण की हिमायत करती है। भाजपा ने ऐलान किया है कि वह उपभोग की सामग्रियों और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के खिलाफ़ है, परन्तु वह बिजली, भारी उद्योग, सड़क निर्माण और दूरसंचार, इत्यादि जैसे ढांचागत क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश का समर्थन करती है। भाजपा भ्रष्टाचार, वंशवाद और अपराधीकरण के लिये कांग्रेस (इ) की निंदा करती है और वादा करती है कि उसकी सरकार इससे भिन्न होगी। भाजपा ने अपने "गरीबी उन्मूलन" कार्यक्रमों की भी घोषणा की है, जिन्हें वह सत्ता में आने पर लागू करेगी। भाजपा के नेता आडवानी ने ऐलान किया है कि अगर उसकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह उपभोग की सामग्रियों और खाद्य क्षेत्र में हिन्दोस्तान में पहले से ही घुसी हुई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से किसी को भी बाहर नहीं निकालेगी।

जबकि भाजपा अपने आप को सत्ता के योग्य प्रतियोगी बतौर जोर-शोर से पेश कर रही है, तो यह स्पष्ट है कि पूंजीवाद, सामंतवाद और संपूर्ण उपनिवेशवादी विरासत के अवशेषों तथा साम्राज्यवाद के प्रति भाजपा का रवैया, साम्प्रदायिक अजेंडा समेत भाजपा का कार्यक्रम कांग्रेस (इ) के कार्यक्रम से ठोस तौर पर भिन्न नहीं है।

उपभोग की सामग्रियों और खाद्य उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश का विरोध करने की बात करके, भाजपा मध्यम श्रेणी के एक तबके के हितों की रक्षा करने का दावा कर रही है, ग्रामीण और शहरी सरमायदारों के उस तबके को खुश करने की कोशिश कर रही है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बेरोकटोक प्रवेश से अपने हितों पर ख़तरा महसूस कर रहे हैं। भाजपा उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिये यह भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है कि कुछ नीतिगत कदमों के ज़रिये मध्यम श्रेणी के ध्रुवीकरण – उनमें से बहुसंख्या का मज़दूर वर्ग में शामिल हो जाना और कुछ गिने-चुने हिस्से का अमीरों में शामिल होना – को टाला जा सकता है। भाजपा बड़े सरमायदारों के उन तबकों के हितों की रक्षा करने का आश्वासन दे रही है, जो आर्थिक सुधारों की गति से नाखुश हैं और अपनी सुविधा व अपने सबसे अहम हितों के अनुसार इन आर्थिक सुधारों को लागू करना चाहते हैं।

भाजपा यह छुपाने की कोशिश कर रही है कि पूंजीवाद के चलते, एक ही कार्यक्रम हो सकता है। वह सरमायदार और शोषित वर्गों के बीच की खाई को छिपाने की भी कोशिश कर रही है, जो सत्तारूढ़ पार्टी के लिये शासन करने में मुश्किलें पैदा कर रही है। वह खुद को राष्ट्रहित, विदेशी हितों, अमीर और गरीब, सभी के अभिभावक बतौर पेश करके, ऐसा करने की कोशिश कर रही है। भाजपा के सत्ता पर आने से मध्यम श्रेणी की तबाही नहीं रुकेगी। सरमायदारों के अलग-अलग तबकों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न पार्टियों की आपस की लड़ाइयों के रूप में, सरमायदार वर्ग के अलग-अलग तबकों के बीच की लड़ाइयां चलती रहेंगी। भ्रष्टाचार, वंशवाद, साम्प्रदायिकता और अपराधीकरण, वे तौर-तरीके हैं जिनके द्वारा ये

अलग-अलग प्रतिस्पर्धी तबके इस व्यवस्था के अंदर, अपने-अपने हितों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। भाजपा की जीत होने से ये गतिविधियां खत्म नहीं होंगी बल्कि और बिगड़ जायेंगी, जैसा कि कांग्रेस (इ) के फिर से जीतने से भी होगा।

जनता दल और सामाजवादी पार्टी, बसपा, इत्यादि जैसे अन्य राजनीतिक संगठनों के बारे में भी यही कहा जा सकता है। इस बात पर ध्यान दिया जाये कि इनमें से कोई भी पार्टी उदारीकरण और निजीकरण के खिलाफ़ नहीं है। विदेशी पूंजी को आकर्षित करने में वे एक से बढ़ कर एक हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सभी संसदीय संस्थानों को देश में विदेशी पूंजी लाने के साधनों में तब्दील कर दिया गया है। ये पार्टियां, जहां भी सत्ता में हैं, विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की भरसक कोशिश कर रही हैं और यह साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि अगर वे केन्द्र में सत्ता पर आतीं तो इस मामले में नरसिम्हा राव से बेहतर काम करतीं।

इस परिस्थिति के अंदर, ये सभी पार्टियां ऐसा दिखावा करती हैं जैसे कि उनके कार्यक्रम राव व उसकी पार्टी तथा भाजपा के कार्यक्रमों से अलग हैं, कि उनके कार्यक्रमों से किसी-न-किसी तरह हिन्दोस्तान के गरीबों का भला होगा। जनता दल, सपा और बसपा यह भ्रम फैलाती हैं कि अगर उनकी पार्टियां केन्द्र में सत्ता में आतीं तो दबी-कुचली जातियों का सशक्तिकरण होता। जैसा कि वस्तुगत गतिविधियों ने दिखाया है, इनकी नीतियों ने न तो जातिवादी दमन के आधार को खत्म किया है और न ही उस शोषण को, जिसकी वजह से बहुसंख्यक आबादी का जीवन बहुत दुखद हो गया है। इन पार्टियों का अस्तित्व शोषक वर्गों के बीच तीखे होते जा रहे अंतरविरोधों और राजनीतिक मामलों में चल रही पूर्ण अराजकता को दर्शाता है। परन्तु इसके बावजूद, ये पार्टियां लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश करती हैं कि लोगों के सामने एक "विकल्प" है। इन पार्टियों के कार्यक्रमों से न तो देश की आर्थिक हालतें बदलेंगी, न ही निचली जातियों की आर्थिक खुशहाली में उन्नति होगी, न ही जातिवादी दमन खत्म होगा और न ही लोग सत्ता में आयेंगे।

माकपा ने भी अपने 15वें महाधिवेशन में, खुद को दूसरी राजनीतिक पार्टियों के साथ स्पर्धा करने वाले एक और दल बतौर पेश किया, जो संसद में अपने तीसरे मोर्चे के लिये बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। यह स्पर्धा की भावना माकपा के नेताओं के विश्वासघातक रास्ते पर पर्दा डालती है और मज़दूर वर्ग व मेहनतकशों से उनके असली इरादों को छिपाती है। माकपा बड़ी धूर्तता के साथ, सत्ता के लिये अपनी लालच को मज़दूर वर्ग व मेहनतकश जनसमुदाय के हितों की हिफाज़त बतौर प्रस्तुत करती है। वह इस बात को भी छिपाने की कोशिश करती है कि वह मध्यम श्रेणी की एक पार्टी है जो सरमायदारों के कुछ तबकों के हितों की भी हिफाज़त करती है। वह मध्यम श्रेणी को पसंद आती है क्योंकि वह कसम खाती है कि मध्यम श्रेणी को तबाही से बचाया जा सकता है। वह मज़दूर वर्ग को यह समझाती है कि उन्हें सत्ता में आने के लिये कुछ देर और इंतजार करना होगा क्योंकि इस समय उसके हालात मौजूद नहीं हैं। अतः अंतिम विश्लेषण बतौर, माकपा सरमायदारों व विदेशी हितों के रक्षक बतौर आगे आती है।

मज़दूर वर्ग सरमायदारी सरकारों, सरमायदारी अधिनायकत्व और उनके सभ्य समाज पर नियंत्रण करने के लिये, सरमायदारों के साथ स्पर्धा नहीं कर रहा है। इसके विपरीत, कम्युनिस्टों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मज़दूर वर्ग एक ऐसे नये समाज की रचना करने में नेता बतौर आगे आये, जिस समाज में कोई संकट, झगड़ा, खून-खराबा और जंग नहीं होगा। सरमायदारी राज्य का विनाश और जनवादी व समाजवादी नये समाज का निर्माण आज का कार्यक्रम है। इसे हकीकत में बदलने के लिये कम्युनिस्टों को यह स्पष्ट करना होगा कि मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनसमुदाय के हित, समाज को संकट से बाहर निकालने के फौरी कार्यक्रम के ज़रिये ही पूरे हो सकते हैं। कृषि क्रांति और जनवादी नव-निर्माण की ज़रूरत है ताकि लोग यह देख सकें कि उनके हित में कुछ ठोस कदम लिया जा रहा है। उपनिवेशवाद-विरोधी क्रांति को अंत तक ले जाने की ज़रूरत है।

सवाल यह नहीं है कि क्या कम्युनिस्ट अपने कार्यक्रम के साथ चुनावों में भाग लेते हैं या नहीं। चुनाव वर्ग संघर्ष का, सरमायदारों और मज़दूर वर्ग के बीच हो रही टक्कर का एक अहम मैदान है। कम्युनिस्टों को क्रांति और समाजवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिये, सभी मोर्चों पर यह संघर्ष करना होगा। परन्तु इसके बावजूद, कम्युनिस्ट खुद अपने तथा दूसरी संसदीय पार्टियों और नेताओं के बीच अंतर को स्पष्ट करके सामने रखते हैं। कम्युनिस्ट अपनी पार्टियों को चुनावी मशीन नहीं बना देते हैं, या यह नहीं मानते हैं कि चुनावों में उनकी जीत, विभिन्न गुटवादी हितों को लाभ पहुंचाने का मौका है, जैसा कि सोशल-डेमोक्रेसी करती है। कम्युनिस्टों के लिये, चुनावी संघर्ष वर्ग संघर्ष का एक मैदान है। इसी तरह, कम्युनिस्ट सरकारों, विधान सभाओं और संसदों को भी वर्ग संघर्ष के मैदान बतौर इस्तेमाल करते हैं। अपने संपूर्ण क्रांतिकारी काम में, अपनी पार्टियों के काम में, कम्युनिस्ट कभी यह नहीं भूलते कि उनका अंतिम लक्ष्य क्रांति और समाजवाद की जीत है, और वे इसी लक्ष्य को आगे रखते हुये सभी संघर्षों को लड़ते हैं। कम्युनिस्ट सशस्त्र संघर्ष और अन्य प्रकार के संघर्षों के मैदान को भी इसी नज़रिये से देखते हैं।

राजनीतिक एकता बनाने की कोशिश में समस्या यह है कि कांग्रेस (इ), भाजपा और दूसरी पार्टियों के कार्यक्रम लोगों को बांटने के लिये बनाये गये हैं। दूसरी समस्या मज़दूर वर्ग के कार्यक्रम को तुच्छ बना देने में है, जो कि "धर्मनिरपेक्ष और जनवादी समाज के लिये तीसरा मोर्चा" के नारे में देखा जा सकता है। ऐसा नारा यथास्थिति को मजबूत करने का स्पष्ट बुलावा है और दूसरे कार्यक्रमों का भी यही इरादा है। इस नारे का मुख्य सारतत्व कांग्रेस (इ) और भाजपा के कार्यक्रमों के जैसा ही है, क्योंकि इसका आधार वर्तमान व्यवस्था को शोषक वर्गों के हित में और बेहतर तरीके से चलाना है। इसमें उठाया गया अजेंडा सरमायदारों का ही अजेंडा है। माकपा खुलेआम ऐलान करती है कि मज़दूर वर्ग के कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का अभी सही समय नहीं आया है।

ये सभी कार्यक्रम जिस प्रकार का समाज बनाने का वादा करते हैं, वह वास्तव में उसी प्रकार का समाज है जो पहले से ही मौजूद है। ऐसे समाज में समय-समय पर आतंकवाद की व्यक्तिगत हरकतें, राजकीय आतंकवाद और साम्प्रदायिक हिंसा भड़क उठती हैं, क्योंकि यह समाज "धर्मनिरपेक्ष" और "लोकतांत्रिक" है और "राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखण्डता" की धारणा पर आधारित है। यह धर्मनिरपेक्ष सिर्फ इसलिये है कि धर्मनिरपेक्षता-विरोधी ताक़तों को बर्दाश्त करता है और लोकतांत्रिक सिर्फ इसलिये है कि लोकतंत्र-विरोधी ताक़तों को बर्दाश्त करता है। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र ऐसे समाज में महज नीतिगत उद्देश्य ही हैं क्योंकि इस समाज का आधार पूंजीवादी और सामंती है और इसका ऊपरी ढांचा, यानी कि इसके सभी संस्थान, कई महत्वपूर्ण पहलुओं में साम्प्रदायिक, उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी है।

इस मोर्चे को बनाने के लिये बुलावा देकर, माकपा के 15वें महाधिवेशन ने समाज को संकट से निकालने में अगुवाई देने के लिये मज़दूर वर्ग को संगठित करने के काम से अपने हाथ धो लिये। माकपा उन कम्युनिस्टों के बीच में बहुत बेचैनी और निराशा पैदा कर रही है जो अभी भी इस भ्रम में हैं कि माकपा अपने तौर-तरीकों को सुधार लेगी। माकपा न सिर्फ संकट से समाज को बाहर निकालने के कार्यक्रम को उठाने में नाकामयाब रही है, बल्कि उसने कम्युनिस्ट कार्यक्रम को पूरी तरह त्याग देने की दिशा में एक कदम बतौर, उदारीकरण को स्वीकार कर लिया है। जब ऐसा कर लिया जाता है, तो यथास्थिति को बरकरार रखने के इस या उस कार्यक्रम को जायज़ ठहराने के तर्कों की कोई कमी नहीं होती। ऐसे कार्यक्रम को जायज़ ठहराने के लिये यह तर्क पेश किया जाता है कि मज़दूर वर्ग की अगुवाई में एक व्यापक जनमोर्चा बनाने की हालतें तैयार नहीं हैं। यह कैसा तर्क है? यह सरमायदारों को आश्वासन देने वाला तर्क है कि माकपा इस समय मज़दूर वर्ग के उद्देश्य की हिफाज़त करने के लिये दूसरों के साथ मिलकर काम नहीं करेगी और भविष्य में भी उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। यह ख़तरनाक भ्रम पैदा करके कि मज़दूर वर्ग एक दिन सरमायदारी राज्य का शासन करने के

लिये, संसद के ज़रिये सत्ता में आ सकेगा, माकपा अब और भविष्य में भी, राज्य के अंदर वर्तमान प्रबंधों में अपने स्थान को सुरक्षित रखने की उम्मीद करती है। आज का ज्वलंत सवाल यह नहीं है कि व्यवस्था के तख्तापलट के लिये हालतें कब तैयार होंगी। आज का ज्वलंत सवाल यह है कि समाज को संकट से बाहर निकालने में अगुवाई देने के लिये, मज़दूर वर्ग के कार्यक्रम को राजनीतिक ताक़तें कब उठायेंगी।

माकपा ने अपने 15वें महाधिवेशन में जैसा किया, वैसा ही भाकपा ने अपने 16वें महाधिवेशन में दोहराया। भाकपा ने हिन्दोस्तान में कम्युनिज़्म के 70 वर्षों का जिक्र किया, सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और दिसम्बर में अपनी 70वीं सालगिरह के समारोह की घोषणा की। उसने तीसरे मोर्चे के बुलावे को पूरा समर्थन दिया और उसे एक वाम, जनवादी और धर्मनिरपेक्ष मोर्चा बताया (जबकि माकपा ने उसे एक धर्मनिरपेक्ष जनवादी मोर्चा बताया था)। इस रूपरेखा के अंदर, भाकपा ने तीसरे मोर्चे के समर्थन में सभी वामपंथियों की एकता का बुलावा दिया, जिससे भाकपा और माकपा के बारे में भ्रम रखने वाले हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों में और निराशा फैल गयी।

भाकपा और माकपा के किसान, नौजवान और महिला मोर्चों में चुनावी, संसदीय और ट्रेड यूनियन कार्यवाइयों का कुल इरादा लोगों को राजनीति से दूर हटाना तथा मज़दूर वर्ग को विचारधारात्मक, राजनीतिक और संगठनात्मक तौर पर पूरी तरह निहत्था बनाना है। इस हालत में हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट कहां जायेंगे? क्या वे हिन्दोस्तानी उपमहाद्वीप के कोने-कोने में, हिमालय से कन्याकुमारी तक और पूर्व से पश्चिम तक, लोगों को यह घोषित करते हुये भटकते रहेंगे, कि अब उन्हें दक्षिणपंथी साम्प्रदायिक ताक़तों को हराने के लिये एक और सारहीन कार्यक्रम के पक्ष में वोट देना होगा? मान लेते हैं कि दक्षिणपंथी साम्प्रदायिक ताक़तों की हार हो जाती है। मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनसमुदाय का क्या होगा? क्या तीसरा मोर्चा सरकार में आकर, समाज को संकट से बाहर निकालने का बीड़ा उठायेगा? नहीं, ऐसी चीजों पर बात करने का यह

वक्त नहीं है। माकपा के 15वें तथा भाकपा के 16वें महाधिवेशनों से यही स्पष्ट संदेश मिला। दोनों महाधिवेशनों में से किसी में भी यह सवाल नहीं उठाया गया कि हिन्दोस्तान में संकट की मूल वजह क्या है और उसका समाधान क्या है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने हिन्दोस्तानी समाज की समस्याओं पर चर्चा और वाद-विवाद में नकारात्मक योगदान दिया।

मज़दूर वर्ग को बहुत सतर्क रहना होगा कि भाकपा और माकपा कांग्रेस (इ) के साथ गठबंधन सरकार बनाकर और उसे साम्प्रदायिक ताकतों पर धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताक़तों की जीत बताकर, फिर से सरमायदारों को बचाने और जन-विरोध को दबाने की कोशिश कर सकती हैं। वे पोलैंड में सोशल-डेमोक्रेटों के सत्ता में आने पर, पहले से ही शेखी बघार रही हैं। रूसी संसद में उनके भ्रात्रीय कामरेडों की जीत पर भी उनकी खुशी नज़र आ रही है। इस विश्वासघात को चुनौती देने के लिये, आज पूरी दृढ़ता के साथ, विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष करना होगा।

इन परिस्थितियों में, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का यह पक्का विचार है कि हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिये कि यह या वह कम्युनिस्ट पार्टी या दल हालत में परिवर्तन लाने वाला है। उन्हें निराश होकर इस या उस पार्टी को अपने हमलों का निशाना भी नहीं बनाना चाहिये। इसके बजाय, उन्हें इस प्रकार की राजनीति से अपने आप को अलग करना होगा। उन्हें समाज को संकट से बाहर निकालने के कार्यक्रम पर विस्तार करने के काम को उठाना होगा। उन्हें इस आधार पर राजनीतिक एकता बनानी होगी।

हम कम्युनिस्टों को इस समय क्रांति की इस मूल समस्या पर कोई गुटवादी भावना नहीं दर्शानी चाहिये। हमें समाज में राजनीति की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के उद्देश्य से, बिना किसी अपवाद के, सभी राजनीतिक

ताक़तों की कार्यवाइयों का विश्लेषण करने और उन पर टिप्पणी करने का अधिकार खुद को देना होगा। इस आलोचनात्मक पर्दाफाश में हमें गुटवाद या हठवाद की थोड़ी सी भी महक नहीं आने देना चाहिये। हमारा उद्देश्य इस या उस पार्टी, इस या उस कम्युनिस्ट को बदनाम करना, ऐसा नहीं होना चाहिये। हमारा उद्देश्य एक ऐसा सजीव राजनीतिक माहौल पैदा करना है, जिसमें लोग खुद यह परख सकेंगे कि इस या उस मोर्चे ने क्या हासिल किया है और आगे क्या हासिल करेगा। यह काम पूरी हिम्मत के साथ, किसी भी तरफ से बदले के डर के बिना, करना होगा।

अब वक्त आ गया है कि सभी कम्युनिस्ट पार्टियों, सभी कम्युनिस्ट बलों, प्रगतिशील और लोकतांत्रिक ताक़तों, सभी राजनीतिक ताक़तों की आंखों से सरमायदारों द्वारा लगाई गयी पट्टी हटाई जाये, जिसके कारण वे सोचते हैं कि अलग-अलग कार्यक्रमों के आधार पर उनके बीच में जितनी ज्यादा फूट पड़ती है, वे क्रांति की जीत के उतने ही नज़दीक आ रहे हैं। उन्हें मज़दूर वर्ग और मेहनतकशों के राजनीतिक स्तर को ऊपर उठाने के लिये, खुद आगे आना होगा।

सभी कार्यक्रमों को मज़दूर वर्ग और मेहनतकशों के द्वारा अपनी मांगों के अनुसार, तय किये गये कार्यक्रमों के अधीन होना होगा। लोगों को क्रांति के जरिये यह स्थापित करना होगा कि सिर्फ वे ही अजेंडा तय करने के अधिकारी हैं। इस या उस राजनीतिक पार्टी से जुड़ने या उसका समर्थन करने के लिये, इस या उस कार्यक्रम पर वाद-विवाद करना इस काम के लिये विनाशकारी है। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि मज़दूर वर्ग और लोगों की पहलशक्ति पर इस प्रकार के विनाशकारी हमले को हराया जाये। मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनसमुदाय को सचेत बनाना होगा ताकि वे समाज को संकट से बाहर निकालने के लिये खुद अपना अजेंडा तय कर सकें।

भाग सात

लोकतांत्रिक नव-निर्माण और उपनिवेशवाद-विरोधी क्रांति को अंतिम पड़ाव तक ले जाना

एक संपूर्ण उपनिवेशवाद-विरोधी क्रांति का अवश्य ही यह मतलब है कि पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीवादी लोकतंत्र को खत्म करना होगा, जिसने लोगों को अपनी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता से वंचित किया है। एक ऐसी उपनिवेशवाद-विरोधी क्रांति, जो सिर्फ औपचारिक आज़ादी का मामला है और सामाजिक क्रांति नहीं है, यह इस समय से मेल नहीं खाती है।

1947 में हिन्दोस्तानी सरमायदारों को "सत्ता के हस्तांतरण" के समय से, हिन्दोस्तानी उपमहाद्वीप और खास तौर पर बंगाल व पंजाब के बंटवारे के साथ, पूरा अनुभव यह साबित करता है कि इनसे कोई गहन परिवर्तन नहीं हुये हैं। बल्कि सरमायदारों ने सामाजिक क्रांति को पूरी तरह रोक रखा है। यह साबित हो चुका है कि पूंजीवाद ही सामंतवाद के अवशेषों का रक्षक है; कि पूंजीवाद ही साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी हितों की रक्षा कर रहा है; कि पूंजीवाद ही सरमायदारों के पूंजी और उत्पादन के भूमंडलीकरण की प्रेरक शक्ति है। इसके अलावा, पूंजीवाद ने गांवों में तबाही मचाई है, कृषि समस्याओं को और गहरा बनाया है तथा देशभक्त ताक़तों के "जोतने वाले को ज़मीन" के नारे को पांव तले रौंद दिया है।

इस समय हिन्दोस्तानी समाज की बुनियाद पर पूंजीवाद और सामंती अवशेष सड़ रहे हैं, जबकि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवादी प्रभुत्व का ऊपरी ढांचा है। इसकी वजह से, मज़दूर वर्ग और मेहनतकशों का जीवन बहुत ही दुखद हो गया है। 50 प्रतिशत से अधिक हिन्दोस्तानी लोग बेहद गरीबी की हालतों में जीते हैं, कुपोषण, अस्वस्थता, निरक्षरता और हर प्रकार की बीमारी के शिकार हैं। भारत सरकार के "गरीबी उन्मूलन" के

संपूर्ण कार्यक्रम में आंकड़ों के साथ खेलने पर जोर दिया जाता है, यह साबित करने के लिये कि गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले हिन्दोस्तानी लोगों का प्रतिशत घट रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब यह दावा किया जा रहा है कि आबादी के 20 प्रतिशत से कम गरीबी रेखा के नीचे हैं। यह खेल हिन्दोस्तानी राज्य और उसके शासकों की उदासीनता को दर्शाता है, जो प्रतिदिन प्राप्त होने वाली कैलोरियों के आधार पर गरीबी रेखा की परिभाषा देते हैं। इस सच्चाई, कि इंसान सिर्फ न्यूनतम मात्रा के भोजन के आधार पर ही नहीं जी सकता है, को तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है। इंसानों को कुपोषण से बचने के लिये और चीजों, जैसे कि दालों, सब्जियों, दूध और मांस की जरूरत है; पीने के पानी, शौच प्रबंध, स्वास्थ्य सेवा, सही आवास और वस्त्र, और जीने लायक स्वच्छ, स्वस्थ, शांतिपूर्ण और स्थिर माहौल की ज़रूरत है। इंसानों को शिक्षा और संस्कृति तथा अपनी लगातार बढ़ती भौतिक व सांस्कृतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिये काम करने में संतुष्टि की ज़रूरत है।

हिन्दोस्तान में, जहां दालें जनसमुदाय के लिये प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं, दालों का प्रतिव्यक्ति उत्पादन और उपभोग बीते 48 वर्षों में क्रमशः गिरते रहे हैं। नैशनल इस्टिट्यूट आफ न्यूट्रिशन, हैदराबाद की एक रिपोर्ट के अनुसार, हिन्दोस्तान के सिर्फ चार राज्यों, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में दालों का औसतन उपभोग प्रतिदिन 40 ग्राम के निर्धारित स्तर से ऊपर है। दूध का औसतन उपभोग प्रतिदिन 95 मि.ली. है, जो कि निर्धारित सीमा के दो-तिहाई से कम है। नैशनल न्यूट्रिशन मोनिटरिंग बोर्ड (एन.एन.एम.बी.) द्वारा गांवों में पोषण पर किये गये एक अध्ययन में यह दिखाया गया है कि 1975-79 और 1988-90 के बीच में, दालों, कंदों और मूलों, बाजरा और सब्जियों के उपभोग में बहुत गिरावट आयी है। चीनी और अनाज के अलावा अन्य सभी खाद्य पदार्थों के उपभोग के स्तर, 1975-79 और 1988-90 के दौरों में, निर्धारित स्तर से काफी नीचे थे। सिर्फ कैलोरियों से ही अगर गरीबी को नापा जाये तो भी, पंजाब, मध्य प्रदेश और कर्नाटक को छोड़कर, बाकी सभी राज्यों में औसतन उपभोग गरीबी की परिभाषा के अनुसार निर्धारित

न्यूनतम स्तर – प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 2,280 किलो कैलोरी – से कम है। एन.एन.एम.बी. के अध्ययन यह भी दिखाते हैं कि 60 प्रतिशत शिशु निर्धारित स्तर से कम कैलोरियों का उपभोग करते हैं। यह निर्धारित स्तर से कम कैलोरियों का उपभोग वाले वयस्कों से भी ऊंची प्रतिशत है।

इन अध्ययनों से यह नहीं स्पष्ट होता है कि हमारे लोगों को कितनी अमानवीय हालतों में जीना पड़ता है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में, लाखों-लाखों लोगों को जंगली पत्तों, ज़हरीले मूलों और दालों का भोजन करना पड़ता है, जिनका बहुत ख़तरनाक असर होता है। यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि अधिकतम हिन्दोस्तानी लोगों की जान धीरे-धीरे निकलती जा रही है। पूंजीवाद के संवर्धन के साथ-साथ गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है और उनकी गरीबी की तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। ज़िन्दगी के खत्म होने के साथ-साथ, हिन्दोस्तानी समाज में जो भी स्वस्थ चीज है उसे भी मिटा दिया जा रहा है।

शहरों में, जहां 25 प्रतिशत हिन्दोस्तानी लोग जीते हैं, वहां आधी आबादी से अधिक, यानी मेहनतकश आबादी इतनी अमानवीय हालतों में जीती है कि उसका वर्णन करना भी मुश्किल है। उनके लिये कोई शौच व्यवस्था या स्वच्छ पीने का पानी नहीं है। बहुत कम पोषण के साथ, कारखानों और निर्माणस्थलों पर कमरतोड़ मेहनत की वजह से पुरुष और स्त्री जल्दी ही मर जाते हैं तथा बच्चों का बचपन कच्ची उम्र में ही खत्म हो जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि चार करोड़ से अधिक बच्चे किशोर अवस्था के पहले ही, दयनीय वेतनों पर, बहुत ही कठिन और ख़तरनाक काम करके गुजारा करते हैं।

सरकार द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा पर प्रति व्यक्ति खर्च से संबधित सरकारी आंकड़े यह दिखाते हैं कि पूरे देश के अंदर, प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 59 रु. खर्च किया जाता है और सार्वजनिक शिक्षा पर 268 रु.। इन अत्यंत निम्न आंकड़ों से भी असली हालत के बारे में बहुत कम पता चलता है। स्वास्थ्य पर आंकड़ों में यह छिपाया

जाता है कि अधिकतम खर्च गर्भनिरोध कार्यक्रमों पर, यानी बच्चों का जन्म रोकने पर किया जाता है। शिक्षा पर आंकड़ों में यह छिपाया जाता है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर बहुत ही कम खर्च किया जाता है और बड़ी संख्या में "प्रतिभा पलायन" होता है जब शिक्षित लोग विदेशों में 'सब्जबागों' की ओर भागते हैं।

पूंजीवाद ने यह सुनिश्चित किया है कि देश के विभिन्न इलाकों में और शहरों की तुलना में गांवों में, "विकास" बहुत ही एकतरफा रहा है। पूंजीवाद ने यह सुनिश्चित किया है कि सामंती अवशेषों से हमारी जनता आज भी पीड़ित है। देश के अनेक भागों में कृषि संबंध आज भी सामंती हैं, जमींदार सर्वोपरि मालिक है, और उसके लिये काम करने वाले पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का भी स्वामी है। कृषि के अंदर सबसे आधुनिक तौर-तरीकों के साथ-साथ प्राचीन तौर-तरीकों का प्रयोग देखने में आता है। यह अधिकतम मुनाफ़ा कमाने और सामंती संबंधों को बचाये रखने की सरमायदारों की ज़रूरत से प्रेरित है। पूंजीवादी शोषण को और तीव्र करने के लिये, मज़दूरों को वेतन का गुलाम होने के "सम्मान" से भी वंचित करने के लिये और मेहनतकशों को पूरी तरह गुलाम बनाये रखने के लिये, पूंजीवाद इन सामंती संबंधों को बरकरार रखता है। सरमायदारों ने बर्बर जाति प्रथा को बरकरार रखा है, जिस प्रथा को सभी शोषक वर्गों ने, पुरुषों और महिलाओं को बेइज्ज़त और प्रताड़ित करके, उन्हें अपनी हवस के शिकार बनाये रखने के लिये, इस्तेमाल किया है। इस व्यवस्था को बरकरार रखने के लिये, लोगों को आपस में लड़वाने के लिये और अलग-अलग समुदायों को वोट बैंक बनाकर रखने के लिये आरक्षण नीति का इस्तेमाल किया जाता है।

बड़े औद्योगिक घरानों के मुनाफों को अधिक से अधिक बनाये रखने के लिये, उन्हें पूंजी और उत्पादन के भूमंडलीकरण की ज़रूरत के अनुसार अपनी व्यवस्था का संयोजन करना पड़ता है और व्यवस्था को इस ज़रूरत के अधीन रखना पड़ता है। इस संयोजन में सरकार उनकी मदद करती है। अंतरराष्ट्रीय वित्त पूंजी के साथ सहयोग और स्पर्धा करते हुये,

पूंजी और उत्पादन का संकेंद्रण भारी लूट-खसोट के ज़रिये किया जा रहा है, जिसकी वजह से मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनसमुदाय की हालत और भी दर्दनाक होती जा रही है। हिन्दोस्तानी पूंजीवाद बर्तानवी उपनिवेशवादी शासन द्वारा बनाया गया एक साधन है जिसके बिना बर्तानवी शासक हिन्दोस्तान में एक दिन के लिये भी नहीं टिक सकते थे। इस पूंजीवाद में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की सभी विशेषताएं बरकरार रखी गयी हैं। अपने सारतत्व में यह आज भी वैसा ही है जैसा कि 1947 में था, जब बर्तानवी उपनिवेशवादियों ने हिन्दोस्तान छोड़ा था। हिन्दोस्तानी लोगों की, देश के विभिन्न इलाकों की भूमि, श्रम और संसाधनों को, बर्तानवी उपनिवेशवाद द्वारा पैदा किये गये पूंजीपति और जमींदार वर्गों तथा उनका सहयोग करने वाले सामंती तत्वों की निजी जायदाद माना जाता है। इसकी वजह से राष्ट्रीय दमन की समस्या बहुत बढ़ गयी है, क्योंकि 1947 में "सत्ता के हस्तांतरण" के बाद, अर्थव्यवस्था पर विदेशी नियंत्रण बढ़ गया है।

यह आकस्मिक नहीं है कि अधिकतम मुनाफ़े हासिल करने के लिये और खुद एक वैश्विक शक्ति बनने के लिये हिन्दोस्तानी सरमायदार, इजारेदार पूंजीपतियों की भूमंडलीकरण की दिशा के अनुसार, हिन्दोस्तानी अर्थव्यवस्था को विदेशी पूंजी के लिये खोलने और अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने की मांग कर रहे हैं। यह हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था में तबाही मचा रही है, मज़दूरों, किसानों व अन्य मेहनतकशों पर नयी-नयी त्रासदियां लाद रही है। 1990 से, निजीकरण और अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की वजह से, कपड़ा और इंजीनियरिंग उद्योगों में, कोयला और इस्पात उद्योगों व अन्य क्षेत्रों में कई लाखों मज़दूर बेरोज़गार हो गये हैं। जी.ए.टी.टी. संधि और कृषि-व्यवसाय क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये हिन्दोस्तान के द्वार खोल देने से किसानों की रोजी-रोटी को भारी ख़तरा है। पूंजीवाद देशभर के शहरों और गांवों में, छोटी संपत्ति के मालिकों को तबाह कर रहा है। बढ़ते कर्जभार और ब्याजदर के चलते, छोटे और मंझोले व्यवसायों की तबाही की गति और तेज़ हो गयी है। पूंजीवाद ज़मीन का संकेंद्रण बढ़ायेगा, किसानों की तबाही को बढ़ायेगा,

गांव से शहरों को पलायन की समस्या को बढ़ायेगा तथा शहरी हालतों में बेरोजगारी, बेघरपन और अराजकता की समस्याओं को बढ़ायेगा।

दूसरी ओर, इन सुधारों के शुरू किये जाने के बीते पांच सालों में, सबसे बड़े इजारेदार घरानों की दौलत में बेशुमार वृद्धि हुई है। सेंटर फॉर मोनिटरिंग द इंडियन इकोनोमी के अनुसार, 1994-95 में, 743 बड़ी हिन्दोस्तानी कंपनियों (जिनमें 25 सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं) के टैक्स कटौती के बाद मुनाफे में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष में ही इसमें 70 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। दूसरे शब्दों में, सिर्फ दो वर्षों में ही इन इज़ारेदार कंपनियों के मुनाफे ढाई गुना हो गये हैं। आज पूंजी और उत्पादन का संकेद्रण हो रहा है, न कि जनसमुदाय का गरीबी उन्मूलन, और न ही समाज के सभी सदस्यों की ज़रूरतें पूरी करने के लिये समाज में उन्नति लाई जा रही है।

बर्तानवी शासकों द्वारा स्थापित राजनीतिक नियंत्रण की व्यवस्था आज भी पूरी तरह बरकरार है। इसकी वजह से, राष्ट्रीयताओं और आदिवासियों की सत्ता से दूरी बढ़ती जा रही है और केंद्रीय राज्य पर नियंत्रण पाने के लिये सरमायदारों के आपसी झगड़े तीखे हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य एक उपनिवेशवादी तंत्र के सिवाय कुछ और नहीं है। यह राष्ट्रीयताओं और आदिवासियों को गुलाम बनाये रखने तथा इस देश के मज़दूर वर्ग और मेहनतकशों के शोषण को और तीव्र करने के लिये, देशी और विदेशी हितों की हिफाज़त करने का एक तंत्र है।

सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टियां, जो शासक वर्गों व उनके संरक्षकों के प्रतिनिधि हैं, अपने नीतिगत उद्देश्यों के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें करती हैं, कि उनकी नीतियों से मज़दूर वर्ग और मेहनतकशों का ऐसा-ऐसा भला होगा। परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पार्टियां उत्पादन की प्रक्रिया में लोगों के बीच के संबंधों के सार को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं कर रही हैं। ये पार्टियां ऐसे लोकतंत्र का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं कर रही हैं, जिसमें लोग संप्रभु होंगे और समाज

का सब कुछ लोगों के अधीन होगा। ये पार्टियां पूंजीवाद, सामंतवाद के अवशेषों, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को खत्म करने, यानी संपूर्ण उपनिवेशवादी विरासत को खत्म करने, का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं कर रही हैं।

इस पूंजीवादी बुनियाद का राजनीतिक ऊपरी ढांचा, इसके राजनीतिक ढांचे और राजनीतिक प्रक्रिया, यानी वर्तमान राजनीतिक शासन, उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी है। पूर्वोत्तर राज्यों का उपनिवेशीकरण और उस इलाके को हिन्दोस्तानी संघ के साथ बलपूर्वक जोड़ना, इसका एक उदाहरण है। कश्मीर का उपनिवेशीकरण और बलपूर्वक विभाजन व कब्ज़ा इसका एक और उदाहरण है। कई अन्य इलाकों का बलपूर्वक कब्ज़ा और सभी राष्ट्रीयताओं और आदिवासियों की गुलामी हिन्दोस्तानी राज्य के उपनिवेशवादी चरित्र को दर्शाती है।

1947 से आज तक पूंजीवाद का निरंकुश विस्तार होता रहा है। हिन्दोस्तान में बड़े औद्योगिक घरानों, सामंती ताक़तों और उपनिवेशवादी व साम्राज्यवादी हितों का राज चलता रहा है। "समाजवाद का नेहरूवी नमूना" के नाम से जानी जाने वाली, आज़ादी के बाद के दौर की संपूर्ण योजना को सबसे पहले अगुवा उद्योगपतियों के एक दल ने दो ग्रंथों में प्रकाशित किया था। आम तौर पर यह *बॉम्बे प्लान* के नाम से जाना जाता है। इस योजना में प्रस्ताव किया गया था कि हिन्दोस्तानी उद्योग के आधार का निर्माण करने के लिये, हिन्दोस्तानी राज्य को कर-वसूली और घाटे की वित्त व्यवस्था तथा मुद्रास्फीति के ज़रिये संसाधन जुटाना चाहिये। इस योजना में बताया गया कि किन क्षेत्रों को उद्योगपतियों के हाथ में रहने देना चाहिये और किन क्षेत्रों को सरकार के हाथ में, कितने समय के लिये रखना चाहिये। इस योजना में यह मांग की गयी कि लाइसेंसों के ज़रिये, कुछ समय के लिये सरकार हिन्दोस्तान के अंदर और बाहर से स्पर्धा को सीमित करे, ताकि बड़े औद्योगिक घराने तेज़ गति से बढ़ सकें। बड़े औद्योगिक घरानों के आपसी झगड़ों को संतुलित रखने के साधन बतौर लाइसेंसों का आबंटन करने की एक

योजना पेश की गयी, ताकि इन झगड़ों से ये घराने खुद ही न खत्म हो जायें। यह भी कहा गया कि विकास के इस प्रस्तावित रास्ते पर चल कर गरीबी दूर हो जायेगी, इत्यादि और इन सबको नीतिगत उद्देश्यों का दर्जा दिया गया। इस बॉम्बे प्लान को उन सभी पहलुओं में साकार रूप दिया गया जो बड़े औद्योगिक घरानों के लिये मुनाफेदार थे। सिर्फ गरीबी को नहीं मिटाया गया और अर्थव्यवस्था संकट से बाहर नहीं निकली। वर्तमान अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था नहीं है, जो सबकी खुशहाली की गारंटी दे सके।

1980 में इंदिरा गांधी ने जिस आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को शुरू किया था, जिसे राजीव गांधी ने 1985 में आगे बढ़ाया था, और 1991 में नरसिम्हा राव ने जिस उदारीकरण और निजीकरण के कार्यक्रम को लागू किया था, ये सभी कार्यक्रम बड़े औद्योगिक घरानों के आदेशानुसार चलाये गये हैं और विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व वित्त पूंजी के अन्य संस्थानों समेत, अंतरराष्ट्रीय वित्त पूंजी की मांगों के अनुसार लागू किये गये हैं। अगर हम गहराई से देखें तो यह पता चलता है कि हर पड़ाव पर, सरमायदारों ने उसी रास्ते को बढ़ावा दिया है जिससे वे संकट से बच सकते हैं और अपने मुनाफ़े की दर को बढ़ा सकते हैं, चाहे हिन्दोस्तानी लोगों पर इसका कितना भी बुरा असर क्यों न हो।

कड़वी सच्चाई यह है कि बड़े औद्योगिक घरानों का यह शासन सेना, पुलिस और विभिन्न सरकारों के इशारों पर काम करने वाले तरह-तरह के गुंडों के ज़रिये चलाया गया है। ये गुंडे सरकारों से स्वतंत्र रूप से, बड़े पूंजीपतियों, बड़े जमींदारों और राजनीतिक पार्टियों के सीधे आदेशों पर भी काम करते हैं, जैसा कि एक हालिया उदाहरण बतौर, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद करवाये गये हत्याकांडों से देखा जा सकता है।

जब मज़दूर अपने काम और जीवन की हालतों को सुधारने के लिये छोटी से छोटी हड़ताल करते हैं, या जब किसान जमींदारों के वहशी दमन के खिलाफ़ छोटे से छोटा संघर्ष करते हैं, तो हिन्दोस्तानी लोगों

को पुलिस के बेरहम शासन का सामना करना पड़ता है। पुलिस बल मज़दूरों, किसानों, महिलाओं व बच्चों पर बलात्कार और उत्पीड़न समेत, तरह-तरह के अत्याचार करते हैं। वे खुद बहुत धन कमाते हैं और समय के साथ-साथ पूंजीपति, जमींदार और नेता भी बन जाते हैं। कई बार वे पूंजीपतियों व जमींदारों की निजी सेना बतौर काम करते हैं, झुग्गीवासियों और फुटपाथ पर रहने वालों को रोज़ तड़पाते हैं, छोटे दुकानदारों व विक्रेताओं से "हफ्ता" वसूलते हैं, और इसके बदले उन्हें अपनी गंदी बस्तियों में रहने या अपने रोजगार कमाने का "विशेष अधिकार" देते हैं।

नियमित पुलिस बल के अलावा कई अर्धसैनिक बल भी मौजूद हैं, जैसे कि सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ., असम रायफल्स, आई.टी.बी.पी., सी.आई.एस.एफ., इत्यादि जो सेना की तरह ही काम करते हैं। 1947 से अब तक बीते साढ़े चार दशकों में, उनकी संख्या और विविधता में बहुत वृद्धि हुई है, जैसे-जैसे बड़े सरमायदारों की हुकूमत के खिलाफ़ मज़दूरों और किसानों का प्रतिरोध बढ़ता गया है। नगालैंड में 1947 से ही सशस्त्र बलों का शासन लगा हुआ है, और अधिकतम पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसा ही है। कश्मीर, पंजाब और हिन्दोस्तान के कुछ अन्य इलाकों में भी ऐसा ही है। जहां-जहां मेहनतकश जनसमुदाय ने वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ़ बगावत की है, जहां-जहां इस बगावत से औद्योगिक घरानों के शासन को ख़तरा पहुंचा है, वहां-वहां सशस्त्र बलों ने बड़ी बेरहमी से लोगों को दबाया है।

तेलंगाना में 1947 में सामंतवाद-विरोधी संघर्ष के उद्देश्य को आगे बढ़ाने और कृषि सुधारों को बढ़ावा देने के लिये जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसे हिन्दोस्तानी सेना ने कुचल दिया। वह आंदोलन लोकतांत्रिक, सामंतवाद-विरोधी, साम्राज्यवाद-विरोधी क्रांति की जीत के लिये कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की अगुवाई में, किसानों की बगावत थी। 1947 में तेलंगाना के संघर्ष के कुचले जाने के बाद, सैंकड़ों-हजारों लोगों को सिर्फ इस प्रकार की मुठभेड़ों में ही मार डाला गया है, घायल किया गया और जेल में बंद किया गया है। मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनसमुदाय या

राष्ट्रीयताओं के सभी प्रगतिशील विद्रोहों और संघर्षों का कुचला जाना अब एक नियमित तरीका बन गया है, 1947 से आज तक पूरे हिन्दोस्तान में एक आम बात बन गयी है।

बर्तानवी उपनिवेशवाद द्वारा रचित, बड़े पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों के उपनिवेशवादी शासन के एक रूप बतौर हिन्दोस्तानी राजनीतिक शासन की व्याख्या की जा सकती है। उनके हित के लिये, केन्द्रीय राज्य की मशीनरी, खास तौर पर सशस्त्र सेना का इस्तेमाल करके, हिन्दोस्तान के पूरे इलाके पर कब्ज़ा किया गया है और उसे उपनिवेश जैसा बना दिया गया है। यह धारणा पैदा करने के लिये कि संसद और राज्य विधान सभाओं द्वारा शासन किया जाता है, विभिन्न राज्यों और केन्द्र में निर्वाचित सरकारों की स्थापना की जाती है। आज सभी पूर्वोत्तर राज्यों और पंजाब में निर्वाचित सरकारें मौजूद हैं और केन्द्र सरकार कश्मीर में भी निर्वाचित सरकार स्थापित करने की कोशिश कर रही है। परन्तु सशस्त्र सेना के बिना इन सरकारों का कोई बल नहीं है।

सरमायदारों के लिये यह बेहतर होता अगर उन्हें लोगों की बगावत का सामना न करना पड़ता और वे संसद व विधान सभाओं में सौदेबाज़ी करके, अपनी ही श्रेणियों के अंदर अंतर्विरोधों को शांतिपूर्ण ढंग से हल कर सकते तथा अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये कानून पास कर सकते। जब दूसरे तरीके असफल हो जाते हैं तो सरमायदार जनता की बगावत को कुचलने और अंदर से किसी भी प्रकार के विरोध को मिटाने के लिये सशस्त्र ताक़त का सहारा लेते हैं और लेते रहेंगे। दूसरे शब्दों में, नागरिक शासन खुद ही सशस्त्र सेना के प्रयोग के अधीन है, न कि सेना नागरिक शासन के अधीन। नगालैंड और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों ने हाल में अपने-अपने राज्यों से कुछ सी.आर.पी.एफ. बटालियनों को कुछ समय के लिये बाहर निकालने के प्रस्ताव का सख्त विरोध किया और कहा कि सी.आर.पी.एफ. के बिना वे शासन नहीं कर सकते हैं!

बहुपार्टीवादी लोकतंत्र, समय-समय पर करवाये जाने वाले चुनाव, औद्योगिक घरानों और बड़े जमींदारों, यानी सरमायदारों के वहशी शासन को छिपाने के लिये एक पर्दा मात्र हैं। सरमायदारी शासन पूंजीवादी व्यवस्था की, सामंतवाद और उपनिवेशवाद के अवशेषों और साम्राज्यवाद, यानी संपूर्ण उपनिवेशवादी विरासत की हिफाज़त करता है। केन्द्र या राज्यों में सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टियां भी इस शासन को वैधता देकर अपनी भूमिका निभाती हैं। अपराधीकरण, साम्प्रदायिक उन्माद भड़काना और साम्प्रदायिक हिंसा आयोजित करना, व्यक्तिगत आतंकवादी हरकतों और राजकीय आतंकवाद को आयोजित करना, भटकाववादी हरकतों को आयोजित करना – इन हथियारों के सहारे बड़े औद्योगिक घरानों के आपसी अंतर्विरोधों को हल किया जाता है, इस या उस निहित स्वार्थ की पूर्ति को सुनिश्चित किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि जनसमुदाय हमेशा उनके शासन के अधीन रहेगा तथा उनके शासन का दुखद शिकार बना रहेगा।

बर्तानवी उपनिवेशवादी काल में कानून का शासन उपनिवेशवादियों और उनके हिन्दोस्तानी कारिंदों का शासन था, जिसे पुलिस और 1858 में स्थापित बर्तानवी हिन्दोस्तानी सेना के ज़रिये लागू किया जाता था। वह निरंकुश कानून-हीनता का शासन था क्योंकि उसका सारतत्व उपनिवेशवादी लूट था। जब तक लूट ही सारतत्व बना रहेगा, तब तक यह कानून का शासन बदनाम रहेगा। 19वीं सदी के यूरोप में पूंजीवादी विकास ने सामंती विशेषाधिकारों और दमन को खत्म किया और राष्ट्रीय राज्य तथा सरमायदारों के कानून के शासन के उभरने का रास्ता खोला। उसका उद्देश्य था सामंती विशेषाधिकारों को अवैध ठहराना तथा निजी संपत्ति पर आधारित सरमायदारी विशेषाधिकारों को वैधता देना। हिन्दोस्तानी पूंजीवाद सबसे पहले बर्तानवी उपनिवेशवाद के साधन बतौर विकसित हुआ। उसने सामंती विशेषाधिकारों को अवैध नहीं ठहराया बल्कि उसे अपने फायदे के लिये इस्तेमाल किया। यूरोप और उत्तरी अमरीका में पूंजीवाद जैसे-जैसे इजारेदार पूंजीवाद के पड़ाव तक पहुंचा, वैसे-वैसे अपने लोकतांत्रिक और प्रगतिशील चरित्र को खो दिया। वह पूरी तरह प्रतिक्रियावादी बन गया।

हिन्दोस्तानी पूंजीवाद को भी उसी सांचे में ढाला गया, और सामंतवाद को उसके फायदे के लिये इस्तेमाल किया गया। हिन्दोस्तान की धरती पर जो भी स्थापित किया गया वह मिश्रित था। सामंती, उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी हितों को बढ़ावा देने का मुख्य साधन पूंजीवादी विकास था, जो हिन्दोस्तानी औद्योगिक घरानों के लिये सबसे लाभदायक था। न तो उपनिवेशवादी हितों को मिटाया गया और न ही सामंती विशेषाधिकारों या साम्राज्यवादी दखलंदाजी को।

हिन्दोस्तानी लोकतंत्र और कानून का शासन अब काफी समय से एक गहरे संकट में फंसा हुआ है, जिससे बाहर निकलने के लिये, क्रांति के ज़रिये समाज में गहन परिवर्तन लाना होगा। यही आज का अहम मुद्दा है। यह संकट शोषितों और शोषकों के बीच अंतर्विरोध का, वित्त अल्पतंत्र और सरमायदारों के अंदरूनी अंतर्विरोधों का प्रतिबिंब है। इन अंतर्विरोधों को कानून-हीनता और राजनीति के अपराधीकरण के ज़रिये हल किया जा रहा है। यह अपराधीकरण इस हद तक पहुंच चुका है कि आबादी के पूरे के पूरे तबकों के कत्लेआम के साथ-साथ, औद्योगिक घरानों के आकाओं, राजनीतिक पार्टियों एवं सरकारों के प्रमुख नेताओं की हत्या एक आम बात बन गयी है।

हिन्दोस्तानी व्यवस्था का नव-निर्माण करना ज़रूरी है। नयी व्यवस्था बुनियादी तौर पर एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जो मज़दूर वर्ग और मेहनतकशों के जज़बातों और दुनिया के मज़दूर वर्ग और लोगों के जज़बातों के अनुकूल होगी। ऐसी व्यवस्था जनता की खुशहाली को समाज की नींव और अर्थव्यवस्था का लक्ष्य मानेगी। इस लक्ष्य को हासिल करना एक नीतिगत उद्देश्य मात्र नहीं होगा बल्कि देश का मूल कानून होगा।

नयी व्यवस्था न सिर्फ आधुनिक और आधुनिकतम होगी बल्कि यह एक परिसंघीय राज्य को भी स्थापित करेगी, जिसमें सभी राष्ट्रों और जनजातियों को पूर्ण समानता और आज़ादी मिलेगी। उन्हें अलग होने के अधिकार समेत, आत्मनिर्धारण का अधिकार मिलेगा। अलग होने के

अधिकार के बिना, आत्मनिर्धारण का अधिकार एक खोखला शब्द बन कर रह जाता है। नयी व्यवस्था में उपनिवेशवाद द्वारा बांटे गये सभी राष्ट्रों को फिर से एक होने का पूरा मौका दिया जायेगा, अगर वे ऐसा चाहते हों। नयी व्यवस्था उपनिवेशवादी विरासत को पूरी तरह खत्म कर देगी और तब हिन्दोस्तान एक सबसे अधिक प्रगतिशील ताक़त बतौर राष्ट्रमंडल में प्रवेश करेगा।

भाग आठ

क्रांति का पड़ाव

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हिन्दोस्तान में क्रांति के पड़ाव का निर्णय सिर्फ अंदरूनी हालतों के अध्ययन से ही नहीं किया जा सकता है। इसे अंतरराष्ट्रीय हालत के संदर्भ में, मुख्यतः अंदरूनी हालत के अध्ययन के आधार पर स्थापित करना होगा।

सभी देशों की प्रगति के द्वार को बंद करने के लिये, दुनिया के सरमायदारों और प्रतिक्रियावादियों ने हर जगह पूंजीवादी ताकतों को क्रियाशील किया है। दुनिया के सरमायदार और प्रतिक्रियावादी सारी दुनिया को अपने जाल में फंसाने के लिये, *"शॉक थेरेपी* (आघात चिकित्सा)" की मांग कर रहे हैं, जो खुलेआम लूट और तबाही का दूसरा नाम है। अंतरराष्ट्रीय वित्त अल्पतंत्र का अगर जरा-सा भी विरोध किया जाये, तो फौरन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे वैश्विक समूहों, नाटो जैसे सैनिक गठबंधनों और हजारों तरीकों से हमलों व दखलंदाजी के ज़रिये उसे धमकी दी जाती है। "मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था", "बहुपार्टीवादी व्यवस्था", "विचारधारात्मक और राजनीतिक बहुवाद" और तथाकथित मानव अधिकारों के "आदर" की मांग की आड़ में, यह मांग की जा रही है कि किसी भी देश को पूंजीवाद से नहीं बचना चाहिये।

जबकि दुनिया के सरमायदार और प्रतिक्रियावादी यह मांग कर रहे हैं कि सभी को विश्व पूंजीवाद के सामने झुकना होगा, तो वर्तमान अंतरराष्ट्रीय हालत की यह विशेषता है कि पूंजीवाद का सबतरफा संकट गहरा और व्यापक होता जा रहा है तथा दुनिया की अर्थव्यवस्था में नाम मात्र का संवर्धन ही हो रहा है। बेरोजगार "बहाली" इस पूंजीवाद की विश्व-व्यापक विशेषता बन रही है, जैसा कि अमरीका, जरमनी, फ्रांस, इत्यादि में

बहुत स्पष्ट है। पूंजीवाद के गहराते सबतरफा संकट के जवाब में, वित्त अल्पतंत्र पूंजी और उत्पादन के भूमंडलीकरण का रास्ता बता रहे हैं। इस तरीके से वित्त अल्पतंत्र सारी दुनिया पर अपना वर्चस्व जमाने के लिये, अपनी आपसी लड़ाइयां लड़ रहे हैं।

दुनिया के दो-ध्रुवीय बंटवारे के खत्म होने से भी पूंजीवादी संकट और गहराया है। पूर्वी गठबंधन के खत्म हो जाने से, विश्व पूंजीवाद के इस संकट के गहराने और व्यापक होने में बहुत बड़ा योगदान हुआ है, क्योंकि इन देशों की जनता अपने-अपने देशों में नकली समाजवाद के नाश और क्लासिकी पूंजीवाद के उत्थान से पैदा हो रही विनाशकारी हालत के खिलाफ़ आवाज़ उठा रही है। जैसे-जैसे पूंजीवाद दुनिया में अपने लिये नये स्थान खोलता जा रहा है, वैसे-वैसे लोगों पर नयी त्रासदियां बरसती रहती हैं। पूंजीवाद बड़ी तेज़ी से अपने पंख फैलाकर, एक ही झपट में पूरे उपमहाद्वीपों और इलाकों पर कब्ज़ा कर लेता है। वह हरे-भरे चारागाहों पर उतरने वाले टिड्डों के झुंड की तरह है। पूंजीवाद के चलते सब कुछ धूल में मिल जाता है, लाखों-लाखों लोग तबाह हो जाते हैं। हालांकि पूंजीवाद ने अपने शुरुआती काल में उत्पादक ताक़तों के विकास को बढ़ावा दिया था, परन्तु अंतिम पड़ाव में वह लोगों का खून चूसने वाली एक जौंक जैसा बन गया है। वह बड़ी तेज़ी से उत्पादक ताक़तों को निगल रहा है। इसी प्रकार का पूंजीवाद हिन्दोस्तान में मौजूद है और लोगों की सभी समस्याओं की जड़ है।

अपने डंडे तले "नयी विश्व व्यवस्था", एक-ध्रुवीय दुनिया स्थापित करने की अमरीकी साम्राज्यवाद की कोशिश के चलते, पूंजीवाद और साम्राज्यवादी लूट के विस्तार के किसी भी प्रकार के विरोध को कुचलने की उसकी जुर्रत बहुत बढ़ गयी है। अमरीकी साम्राज्यवाद को अभी भी पूरा विश्वास है कि उसके लिये सारे दरवाज़े खुले हुये हैं, या तो हिंसा के ज़रिये, जैसे कि निकोलाई चेचेस्कू की हत्या में, या अंदरूनी तोड़-फोड़ के ज़रिये, जैसा कि मिखाइल गोर्बाचेव ने कर दिखाया है। परन्तु अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देते हुये, अमरीकी साम्राज्यवाद

यह मानने को तैयार नहीं है कि पूंजीवादी हमले के खिलाफ़ उत्पादक ताक़तों की बगावत के पूरे आक्रोश का अभी भी प्रकट होना बाकी है, कि यह आक्रोश बिजली की कड़क की तरह शीघ्र ही आने वाले इंकलाबी तूफानों का संदेश देगा। हालांकि ऐसा लगता है कि अमरीका द्वारा थोपी गयी "खुले द्वार की नीति" की जीत कभी पलट नहीं सकती, परन्तु अंतर-साम्राज्यवादी अंतर्विरोधों के तीखे होने से, तथा इरान, इराक और उन सभी राज्यों जो विदेशी तोड़-फोड़ और अमरीकी साम्राज्यवाद की हुक्मशाही का डटकर सामना कर रहे हैं और उसकी "एक-ध्रुवीय दुनिया" को मानने से इनकार कर रहे हैं, उनके प्रतिरोध से यह नीति नाकामयाब हो रही है। क्यूबा, उत्तरी कोरिया और वियतनाम जैसे देश बहादुरी के साथ अपने प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने पर डटे हुये हैं, अपनी आज़ादी की रक्षा कर रहे हैं और सभी विदेशी धमकियों का मुकाबला कर रहे हैं। इस "खुले द्वार की नीति" के रास्ते में, "एक-ध्रुवीय दुनिया" स्थापित करने की अमरीकी साम्राज्यवाद की हुक्मशाही के खिलाफ़, इस्लामी आंदोलन भी खड़ा है।

इन हालतों में, जबकि साम्राज्यवाद, सरमायदार और दुनिया के प्रतिक्रियावादी यह दिखावा करते हैं कि समाजवाद और कम्युनिज़्म का ख़तरा खत्म हो गया है, पर वास्तव में इन देशों में सबतरफा संकट से स्पष्ट होता है कि इनका आर्थिक आधार पूरी तरह अस्त-व्यस्त है। इन देशों के मज़दूर वर्ग में पूंजीवादी व्यवस्था के ख़तरों के बारे में नयी जागृति पैदा हो रही है। मज़दूर वर्ग और सरमायदारों के बीच अंतर्विरोध, समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में अंतर्विरोध बहुत तीखा हो रहा है। यह अंतर्विरोध शोषितों और शोषकों के बीच संघर्ष में तथा लोकतांत्रिक नव-निर्माण के पक्ष में व उसके खिलाफ़ ताक़तों के बीच संघर्ष में स्पष्ट हो रहा है। इस संघर्ष का सारतत्व समाज की प्रगति का द्वार खोलना है। अब हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों के लिये वक्त आ गया है कि मज़दूर वर्ग, सभी मेहनतकशों और देशभक्त ताकतों को जागृत करें और उनके हथियारों, उनकी विस्फोटक शक्ति को, उस अतिबेरहम पूंजीवाद के खिलाफ़ इस्तेमाल करें, जिसे सरमायदार और प्रतिक्रियावादी हिन्दोस्तानी लोगों पर थोप रहे हैं।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी यह मानती है कि सबसे अहम अंतर्विरोध, सबसे निर्णायक अंतर्विरोध समाजवाद और पूंजीवाद के बीच है। समाजवाद और पूंजीवाद के बीच अंतर्विरोध को हल करने से हर प्रकार के अन्य अंतर्विरोध हल हो जायेंगे। राजनीतिक तौर पर, इस समय यह अंतर्विरोध एक खास रूप में आगे आ रहा है। यह एक तरफ, गहन परिवर्तन, समाज की प्रगति के लिये ज़रूरी नव-निर्माण और आधुनिकीकरण चाहने वालों, तथा दूसरी तरफ, वर्तमान व्यवस्था के बारे में भ्रम फैलाने वालों, पूंजीवाद के सुधरे, सोशल-डेमोक्रेटिक पड़ाव के घिसे-पिटे विचारों को फैलाने वालों के बीच में अंतर्विरोध के रूप में पेश हो रहा है। समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में अंतर्विरोध, सिद्धांत के क्षेत्र में तीखे संघर्ष में, विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष के क्षेत्र में, समाज में हर चीज और खास तौर पर राजनीति के स्तर को नीचे खींचने की सरमायदारों की कोशिश में नज़र आता है। इसका यह मतलब है कि हमारे संघर्ष की तीखी धार के साथ हमें उन सब पर वार करना होगा जो पूंजीवाद और "समाजवाद" के बारे में, यानी निजीकरण और उदारीकरण और सोशल-डेमोक्रेसी के बारे में भ्रम फैला रहे हैं।

समाजवाद और पूंजीवाद के बीच इस संघर्ष के तीखे होने के संदर्भ में हमें दूसरे सारे अंतर्विरोधों को समझना होगा। यह सोचने वाली बात है कि अमरीकी साम्राज्यवाद क्यूबा पर घेराबंदी को बनाये रखने पर तुला हुआ है, इसलिये नहीं कि क्यूबा अमरीका के लिये किसी प्रकार का ख़तरा है, बल्कि इसलिये कि क्यूबा की व्यवस्था उस धारणा का खंडन करती है कि अमरीकी साम्राज्यवाद के द्वारा परिभाषित एक-ध्रुवीय दुनिया में सिर्फ एक प्रकार का लोकतंत्र और एक प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। समाजवाद और पूंजीवाद के बीच के इस अंतर्विरोध को इस बात में भी देखा जा सकता है कि पूंजीवाद अपने खिलाफ़ संघर्ष करने वाले सभी देशों और ताक़तों को पूरी तरह कुचलने की कोशिश कर रहा है। बहुत से देशों को अंतरराष्ट्रीय वित्त पूंजी पर पूरी तरह निर्भरशील बना दिया गया है, जिसके कारण उनकी आर्थिक और वित्तीय गुलामी के खिलाफ़ संघर्ष अनिवार्य है।

इस अंतर्विरोध की पृष्ठभूमि में, हिन्दोस्तान में क्रांति का पड़ाव पूंजीवाद को मिटाने तथा सामंतवाद और उपनिवेशवाद के अवशेषों और साम्राज्यवाद को मिटाने का पड़ाव है। हिन्दोस्तान में पूंजीवाद का बहुत ही तेज़ गति से विकास हो रहा है और सभी अंतर्विरोध, खास तौर पर शोषितों और शोषकों के बीच अंतर्विरोध, बहुत तीखे होते जा रहे हैं। सरमायदार खुद इस अंतर्विरोध का इस्तेमाल कर रहे हैं जब वे यह दिखावा करते हैं कि देश की आर्थिक प्रगति के लिये समाजवाद को खत्म किया जा रहा है।

क्रांति के इस पड़ाव में कई लोकतांत्रिक और साम्राज्यवाद विरोधी कार्य भी करने होंगे। परन्तु देश के मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनसमुदाय इन कार्यों को नहीं समझेंगे अगर पूंजीवाद के विनाश को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। यही वह अत्यंत निर्णायक सवाल है जिसपर इस समय चर्चा की जानी चाहिये और फैसले लिये जाने चाहिये, और जिसके इर्द-गिर्द मज़दूर वर्ग और जन समुदाय की रणनैतिक राजनीतिक एकता बनानी होगी। परन्तु यह क्रांति के पड़ाव को निर्धारित करने की चर्चा का अंत नहीं है। यह मात्र उसकी शुरुआत है।

भाग नौ

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की रणनीति और कार्य योजना

कम्युनिस्ट आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचा है। आगे वह किस दिशा में जायेगा? हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि समाज के भविष्य के लिये उनका क्या प्रस्ताव है। सरमायदारों की राजनीतिक पार्टियां यह दावा कर रही हैं कि उन्हें समाज की समस्याओं का समाधान मिल गया है। उनका समाधान निजीकरण और उदारीकरण तथा पूंजी और उत्पादन का भूमंडलीकरण है। दूसरे शब्दों में, उनकी योजना समाज के सभी अंतर्विरोधों को और तीखा करने में योगदान देगी।

कम्युनिस्ट आंदोलन का रणनैतिक लक्ष्य पूंजीवाद का तख्ता पलट और समाजवादी समाज की स्थापना होना चाहिये। यह कम्युनिस्ट आंदोलन के लिये एक उत्साहजनक नज़रिया है। सभी हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों को इस उत्साहजनक नज़रिये के साथ कम्युनिस्ट आंदोलन की ओर देखना होगा। जबकि यह सभी के लिये बहुत स्पष्ट है कि इस समय हिन्दोस्तान में कम्युनिस्ट आंदोलन बंटा हुआ है, परन्तु यह भारी भूल होगी अगर कम्युनिस्ट इस बंटवारे को सिर्फ बंटवारा ही समझें और इसे आगे बढ़ने का मौका न समझें। इससे भी बड़ी भूल होगी यह सोचना कि कम्युनिस्ट आंदोलन ही एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसमें सच्चे तौर पर लोकतांत्रिक और प्रगतिशील ताकतें मौजूद हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन के बाहर बहुत-सी प्रगतिशील और लोकतांत्रिक ताक़तें हैं और वे सब भी प्रगतिशील ताकतों की राजनीतिक एकता के कार्यक्रम में रुचि रखती हैं। वर्तमान हालतों में कम्युनिस्ट आंदोलन की भूमिका को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना बहुत भारी गलती होगी। समाज को संकट से बाहर निकालने के लिये राजनीतिक एकता बनाने की फौरी ज़रूरत पर हमें जोर देना होगा।

बीते समय में मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनसमुदाय के लक्ष्य को बहुत नुकसान पहुंचा है। इस या उस नुकसान के लिये खास लोग जिम्मेदार रहे हैं। इस समय किसी खास व्यक्ति या संगठन पर उसके बीते स्वभाव के बारे में इलज़ाम लगाने के उद्देश्य से, बीते दिनों में जाकर तलाशने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्तमान स्थिति पर इस या उस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा, मज़दूर वर्ग आंदोलन किस दिशा में बढ़ रहा है और उसे कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ले जाया जाये, इन विषयों पर चर्चा करके लोगों के विचारधारात्मक और राजनीतिक स्तर को ऊंचा उठाना होगा तथा कार्यक्रम को विस्तृत रूप में पेश करना होगा। इस तरह, जैसे-जैसे यह काम विकसित होता है, वैसे-वैसे वर्तमान और बीते समय के सभी अपराधियों का स्वभाव स्पष्ट हो जायेगा; उनका पर्दाफाश हो जायेगा और लोग समझ जायेंगे कि उन्होंने आंदोलन को कितना भारी नुकसान पहुंचाया है।

इस संदर्भ में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को बहुत ही तीखे तरीके से विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष करना होगा ताकि समकालीन मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा और मार्क्सवाद-लेनिनवाद की शुद्धता की रक्षा की जाये तथा सोशल-डेमोक्रेसी के साथ समझौते की हर कोशिश का डटकर विरोध करके, कम्युनिस्ट और मज़दूर आंदोलन की हिफाज़त की जाये। जैसे-जैसे यह संघर्ष विकसित होगा, वैसे-वैसे लोग समझेंगे कि प्रगति के रास्ते को रोकने वालों के साथ कैसे निपटना होगा। लोग अपने अनुभव से सीखेंगे और इन रुकावटों को दूर करते हुये, आंदोलन और मजबूत होगा।

क्रांतिकारी सिद्धांत के इर्द-गिर्द संगठित करने पर हमें मुख्य ज़ोर देना होगा। हमें जीव और जागरुकता, वस्तुगत और आत्मगत के बीच सजीव संबंध को समझाना होगा। इस पर ज़ोर देकर विचारधारात्मक संघर्ष को विकसित किया जाता है, आम कार्यदिशा को स्थापित किया जाता है, संगठनात्मक कार्यों को तय किया जाता है और विवादात्मक संघर्ष किया जाता है। इस अवधि के लिये आम कार्यदिशा के दायरे में कार्य

योजना को लागू करने के आधार पर ही पार्टी के अगुवा निकायों और बुनियादी संगठनों की स्थापना की जा सकती है और उन्हें मज़बूत किया जा सकता है। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का निर्माण, यह खुद ही सबसे महत्वपूर्ण आत्मगत हालत की रचना है। यह मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनसमुदाय के उद्धार के संघर्ष का मुख्य साधन है। यह उपनिवेशवादी विरासत, सभी सामंती अवशेषों और साम्राज्यवाद को नष्ट करने तथा क्रांति के ज़रिये समाज को पूंजीवाद से समाजवाद में तब्दील करने का मुख्य साधन है। मज़दूर वर्ग की अपनी जगरुकता और संगठन सुनिश्चित करना, यह हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की भूमिका है; उसके आगे पार्टी मज़दूर वर्ग का स्थान खुद नहीं ले सकती। हिरावल पार्टी की स्थापना करने की समस्या एक है; मज़दूर वर्ग आंदोलन के खुद अपने क्रांतिकारी कार्यक्रम से लैस होने की समस्या दूसरी है। ये दोनों कार्य आपस में संबंधित हैं। पहला कार्य मज़दूर वर्ग के अगुवा तत्वों का काम है, जबकि दूसरा कार्य मज़दूर वर्ग के व्यापक जनसमुदाय का काम है, जिसकी अगुवाई हिरावल दस्ते को करनी होगी। परन्तु हिरावल दस्ता खुद मज़दूर वर्ग के व्यापक जनसमुदाय का स्थान नहीं ले सकता।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का यह विचार है कि क्रांति के पड़ाव और कार्यक्रम से संबंधित इन मामलों पर चर्चा करने के अलावा, वर्तमान हालतों में क्या करना चाहिये, इस पर विस्तार करने की भी ज़रूरत है। किस प्रकार की व्यवस्था की ज़रूरत है, जो लोगों के हितों की सेवा करेगी? क्रांति के रणनैतिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के संदर्भ में, फौरी समस्याओं के लिये संघर्ष को कैसे करना होगा?

इस विषय को हल करने के लिये कम्युनिस्टों को बड़ी निपुणता के साथ विस्तारपूर्वक पेश करना होगा कि वर्तमान समय पर हिन्दोस्तान में पूंजीवाद के खिलाफ़ संघर्ष को ठीक किस तरीके से करना होगा। अगर हम लोगों के सामने जाकर सिर्फ यह ऐलान करें कि हम पूंजीवाद के खिलाफ़ हैं, तो लोग हमारी बातों को नहीं समझेंगे। इसी तरह, अगर हम कहते हैं कि लोगों को लोकतांत्रिक नव-निर्माण में जुटना

चाहिये तो लोग उसे भी नहीं समझेंगे। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के विचार में, पूंजीवाद के खिलाफ़ जो संघर्ष ज़रूरी है, उसके तरीके का सारतत्व पहले से ही जनसमुदाय के अनुभव में मौजूद होगा। यह सारतत्व अवश्य ही पूंजीवाद-विरोधी, सामंतवाद-विरोधी, उपनिवेशवाद-विरोधी और साम्राज्यवाद-विरोधी होना चाहिये।

गरीबी हटाओ, एक के बाद दूसरी सरकार ने यह नारा दिया है, जिनमें नरसिम्हा राव की सरकार भी शामिल है। परन्तु इन सरकारों द्वारा पेश किये गये इस नीतिगत उद्देश्य से ही गरीबी नहीं हट जायेगी। ये सभी सरकारें दावा करती हैं कि लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिये उनके पास पैसा नहीं है और इस बात को छिपाती हैं कि वर्तमान व्यवस्था के चलते, अमीर और अमीर होते जाते हैं तथा गरीब और गरीब। इस समय ये सरकारें इस हद तक गिर चुकीं हैं कि वे खुले-आम ऐलान कर रही हैं कि लोगों की ज़रूरतें पूरी करना वास्तव में लोगों के लिये अच्छा नहीं होगा और अर्थव्यवस्था के लिये भी अच्छा नहीं होगा। उनकी मांग है कि सभी को अपनी देखभाल खुद करनी होगी। दुनियाभर के सरमायदारों और प्रतिक्रियावादियों के जैसे ही, हिन्दोस्तानी सरमायदार भी चिल्ला रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कार्यक्रमों के लिये पैसे नहीं हैं। जहां तक हिन्दोस्तान की ठोस परिस्थितियों का सामना करने की बात है, सरमायदार जीविका तक सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं और पूंजीवादी व्यवस्था लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती।

आज आधे से भी अधिक लोग सरकारी गरीबी रेखा के नीचे हैं और बड़ी संख्या में लोग जीवन के साधनों से वंचित हैं। परन्तु इस समस्या को हल करने के बजाय, नरसिम्हा राव, दुनिया भर के प्रतिक्रियावादियों के इशारे पर चलकर, "नीचे तक रिसने" (पूंजीपतियों की दौलत बढ़ने से थोड़ा कुछ गरीबों तक नीचे भी पहुंचेगा) का वादा कर रहा है और पूंजीवादी ताक़तों को राजकोष तथा जनसमुदाय को लूटने की और ज्यादा छूट दे रहा है। वास्तविक हालतें और इस बेलगाम लूट व उत्पादक ताक़तों के

विनाश का परिणाम इस नीति के सभी प्रचारकों के मुंह पर एक तमाचा है : गरीबों तक नीचे रिसना तो दूर, अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ती जा रही है।

पूंजीवादी व्यवस्था की इस प्रवृत्ति को सरमायदार क्यों नहीं पलट सकते हैं? पूंजीवादी व्यवस्था लोगों की ज़रूरतों को क्यों पूरा नहीं कर सकती है? क्या सही नीतियों की कमी है? नहीं, पूंजीवाद पूंजीवाद नहीं होता अगर सरकार पूंजीवाद का तख्ता पलट किये बिना ऐसा कर सकती। एक तरफ अमीरी का संकेंद्रण और दूसरी तरफ गरीबी का संकेंद्रण, यह पूंजीवादी व्यवस्था में निहित है। सामंतवाद और उपनिवेशवाद के अवशेषों तथा साम्राज्यवाद की वजह से भी यह गतिविधि और तेज़ हो रही है।

केन्द्र सरकार और सरमायदारों द्वारा लोगों के अधिकारों और रोजी-रोटी पर इस हमले के संदर्भ में, अगर हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी यह प्रस्तावित करे कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये धन जुटाने का तरीका है, तो कैसा होगा? मिसाल के तौर पर, हिन्दोस्तान के संपूर्ण अंदरूनी और विदेश व्यापार को अगर राज्य के हाथ में ले लिया जाये, तो यह धन जुटाया जा सकता है। हिन्दोस्तानी और विदेशी बाज़ारों में वितरण के लिये सामग्रियों को खरीदने और बेचने के आधार पर राज्य पूंजी जुटाने का काम शुरू कर सकता है। कर्ज़ा चुकाने के लिये भुगतान पर कुछ समय के लिये रोक लगा कर भी, फौरी तौर पर बहुत सारा धन जुटाया जा सकता है। समाज से लोगों की जो-जो मांगें हैं, उन्हें पूरा करने के लिये इन तरीकों से जुटाये गये धन का सीधा इस्तेमाल हो सकता है। इंसान होने के नाते लोगों को जो-जो अधिकार मिलने चाहिये, उनके लिये देश में संवैधानिक गारंटी दी जा सकती है और इन तथा अन्य तरीकों से लोगों की ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। अर्थव्यवस्था के सैन्यीकरण को खत्म करना भी धन जुटाने का एक और तरीका हो सकता है। साथ ही साथ, सभी अंदरूनी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को समाज के नियंत्रण में लाने,

अर्थव्यवस्था के सैन्यीकरण को खत्म करने तथा कर्ज़ा चुकाने के लिये भुगतान पर कुछ समय के लिये रोक लगाने के कदमों को मानने से इनकार करने वालों के हाथों से राज्य उत्पादन के मुख्य साधनों को छीनने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

क्या हिन्दोस्तान की सरकार धन जुटाने के इन कदमों को उठायेगी, ताकि लोगों और समाज की खुशहाली की देखभाल न करने का उसके पास कोई बहाना नहीं होगा? नहीं, सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि हिन्दोस्तानी सरकार का उद्देश्य बड़े पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों, जिन्होंने उन्हें सत्ता पर बैठाया है, उनकी सेवा करना है। हिन्दोस्तानी लोगों को खुद ही ये कदम उठाने पड़ेंगे। इन कदमों को उठाकर, लोगों को एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की ओर आगे बढ़ना होगा।

व्यापार का सवाल देश में किन-किन चीजों का उत्पादन किया जाता है, उससे सीधे तौर पर संबंधित है। उत्पादित वस्तुओं का उपभोग कहां होता है और ये कहां जाती हैं, इसके साथ भी व्यापार का संबंध है। देश के लोगों को इस विषय में बहुत रुचि है। लोगों को यह जानने में बहुत रुचि है कि श्रम के उत्पादों तथा श्रमशक्ति, दोनों की कीमतों को कौन तय करता है और किस तर्क के आधार पर ये कीमतें तय की जाती हैं। हिन्दोस्तान के लोगों का यह अनुभव है कि अकाल जैसी हर आपदा की हालतों में भी, खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं होती है लेकिन उसकी कीमत इतनी ऊंची होती है कि वह लोगों की पहुंच से बाहर हो जाता है। आज भी, जब लोग बड़ी संख्या में भुखमरी के शिकार हैं या जल्दी मौत के घाट पहुंचने को मजबूर हैं, तो गोदामों में गेंहू और चावल के सड़ने की कहानियों का कोई अंत नहीं है। हिन्दोस्तान में खाद्य पदार्थों की कमी नहीं है पर फिर भी, देश के बहुत से इलाकों में लोग भूखे मरते हैं और लाखों-लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं।

हमें ऐसी मांगें रखनी होंगी जिनका उद्देश्य है लोगों के आंदोलनों को उन सुधारों की दिशा में मोड़ना जो पूंजीवादी यथास्थिति को तोड़ने में मदद करेंगे, न कि यथास्थिति को मजबूत करेंगे, जैसा कि सोशल-डेमोक्रेटिक मांगों व कार्यों का परिणाम होता है। इन आंदोलनों और मांगों से उन सभी ताक़तों की राजनीतिक एकता बनेगी, जो गहन परिवर्तनों के पक्ष में हैं, और एक वैकल्पिक समाज का नज़रिया पेश करने में मदद देंगी जो उसके सभी सदस्यों की मांगों को पूरा करने के काबिल हो।

इन मांगों को पेश करने के अपने काम के अलावा, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को मज़दूरों और मेहनतकशों, बुद्धिजीवियों और पेशेवरों, महिलाओं और नौजवानों को अगुवाई देनी होगी ताकि वे खुद अपनी मांगें तय कर सकें। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पूंजीवादी व्यवस्था और इस या उस राजनीतिक पार्टी या नेता की अच्छी और बुरी नीतियों के बारे में सोशल-डेमोक्रेटिक भ्रम फैलाने के आधार पर, मज़दूर वर्ग और लोगों का बंटवारा खत्म किया जाये। इस प्रयास में मुख्य काम है उन संगठनात्मक तौर तरीकों को स्थापित करना जिनके ज़रिये लोग अपने बीच आपस में इन विषयों पर चर्चा कर सकेंगे। इस प्रयास के ज़रिये लोग अपने आपस में से उन उम्मीदवारों का चयन भी कर सकेंगे, जो उनकी मांगों के प्रतिनिधि होंगे और उन मांगों को बढ़ावा देंगे। जनसत्ता के केंद्रों के रूप में इन संगठनों को विकसित करना होगा, जिनके ज़रिये लोग खुद अपने जीवन पर नियंत्रण करने लगेंगे।

अगर हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी इस समय काम के स्थानों, शिक्षा संस्थानों और मोहल्लों में लोक सशक्तिकरण समितियों की स्थापना का आह्वान करती है, तो लोग देश के राजनीतिक मामलों में भाग लेना शुरू कर सकते हैं। इस या उस राजनीतिक पार्टी के बीच में बंट जाने के बजाय, लोग शुरू से ही अपनी राजनीतिक एकता स्थापित कर सकेंगे। उचित समय पर और उचित हालतों में ये समितियां जनसत्ता के तंत्र

बन जायेंगी। इन समितियों में वैधानिक और कार्यकारी काम, दोनों ही किये जायेंगे। जिन-जिन स्तरों पर ये समितियां स्थापित होंगी, उन-उन स्तरों पर ये लोगों के अधीन होंगी।

साथियों, आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे विषयों पर बात की है और अनेक व्यापक प्रकार के सवालों को उठाया है। अब यह सवाल उठता है : क्या हम उन सभी पर काम कर सकते हैं? हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की रणनीति क्या होनी चाहिये? हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के पास उपलब्ध सभी ताकतों तथा भविष्य की संभावनाओं का गहरा मूल्यांकन करने के बाद, हमारी रणनीति उस चीज पर पूरा जोर लगाना है, जो हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के निर्माण के लिये इस समय निर्णायक है। हमें इस रिपोर्ट में उठाये गये सभी मुद्दों पर काम को और गहराई तक ले जाना होगा, खास तौर पर क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष को करने के दौरान, अध्ययन और खोज पर आधारित सारतत्व को प्रस्तुत करना होगा।

आज जो विश्लेषण पेश किया गया है, और इससे जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, इन्हें इस विषय पर प्रथम शब्द समझने चाहिए, न कि अंतिम। इस काम के दौरान, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को हिन्दोस्तानी सिद्धांत का विकास करना होगा और बहुत ही तीक्ष्ण विचारधारात्मक व विवादात्मक संघर्ष करना होगा। इसके साथ-साथ, सोशल-डेमोक्रेसी के बारे में किसी भी प्रकार के भ्रम के खिलाफ़, और सरमायादार वर्ग के साथ किसी भी प्रकार के समझौते के खिलाफ़, हठवाद और गुटवाद के खिलाफ़ मुख्य संघर्ष होगा। अभ्यास के तौर पर, सबसे ज्यादा जोर देना होगा हिन्दोस्तानी सिद्धांत को विकसित करने और तीक्ष्ण विचारधारात्मक व विवादात्मक संघर्ष करने पर, जिसकी तेज़धार होगी केंद्रीय समिति के मुखपत्र, पीपल्स वायस का निर्माण करना, मज़दूरों, नौजवानों और महिलाओं के जन संगठनों का निर्माण करना। साथ ही साथ, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को समाज के लोकतान्त्रिक नव-निर्माण के

लिए जो काम शुरू हो चुका है, उसे आगे ले जाने के लिए, सभी प्रगतिशील और लोकतान्त्रिक ताक़तों के साथ, मिल कर करना होगा।

रणनीति और आभ्यासिक कार्य की योजना, दोनों को ही अपने उद्देश्य पर बहुत ध्यान देना होगा। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को यह सुनिश्चित करने पर बहुत ध्यान देना होगा कि इस पूरे काम को ऐसे तरीके से किया जाये ताकि सम्पूर्ण सैद्धान्तिक, विचारधारात्मक और विवादात्मक काम, केंद्रीय समिति के मुखपत्र को मज़बूत करने के काम और जन संगठनों को मज़बूत करने के काम के ज़रिये, पार्टी को मज़बूत किया जाये। इस पूरे काम को सफलतापूर्वक करने के लिए, सोशल-डेमोक्रेसी के बारे में भ्रम फैलाने वालों तथा सोशल-डेमोक्रेसी के साथ समझौता करने वालों पर हमें निशाना साधना होगा।

साथियों, सारी दुनिया में बहुत ही गंभीर, सब-तरफा संकट फैला हुआ है, जिसमें प्रतिगामी ताकतें हमलावर हैं। इन हालतों में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का यह दायित्व है कि वह अगुआ भूमिका अदा करे यह सुनिश्चित करने के लिए कि मज़दूर वर्ग समाज को संकट से बाहर निकालने के संघर्ष में नेतृत्व देने को तैयार है। मैं फिर से दोहराता हूँ, साथियों, वर्तमान हालतें या तो क्रांति की ओर ले जायेंगी, या फिर युद्ध की ओर। हमारे सामने एक ही रास्ता खुला हो, क्रांति का रास्ता। क्रांति में जीत हासिल करके, युद्ध की सभी संभावनाओं, चाहे यह क्षेत्रीय युद्ध हो या अंतर-साम्राज्यवादी विश्व युद्ध, को मिटा दिया जाये।

सभी क्रांतिकारी कम्युनिस्ट, प्रगतिशील और लोकतान्त्रिक ताक़त, मज़दूर वर्ग, महिला और नौजवान, सभी शोषित-पीड़ित, देश के सभी मेहनतकश, इस चुनौती के लिए उठ खड़े हों, क्योंकि एक सुख, लाल, नयी सुबह का सूर्योदय हो रहा है। बीसवीं सदी की रोशनी, महान अक्टूबर क्रांति का मार्ग मिटा नहीं है। अक्टूबर के सबक, पहले की तरह और पहले से कहीं ज्यादा, आज भी उपयुक्त हैं। हमें अभी देखना है कि यह रोशनी

कितनी उज्ज्वल होगी, जब मज़दूर वर्ग और क्रांतिकारी ताक़तें वर्ग संघर्ष करने के लिए आगे आयेंगी और वर्तमान हालात को बदलेंगी। सभी कम्युनिस्ट ताक़तें एकजुट हो जाएँ और अपनी कथनी को करनी में बदल दें। समाज की प्रगति का रास्ता खोल दिया जाये। क्रांति आगे बढ़े! विजय हम सबकी है, जो अपने उत्तम उद्देश्यों को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं!

इंकलाब ज़िंदाबाद!

...कवर का शेष भाग

बाधाओं को हटा कर एकता बनाएं
24–25 जनवरी, 1998 को नई दिल्ली में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी की विस्तृत परिपूर्ण सभा द्वारा चर्चा के लिये जारी किया गया दस्तावेज़

नयी सदी की है यह मांग, हिन्दोस्तान का नवनिर्माण
हम हैं इसके मालिक, हम हैं हिन्दोस्तान, मज़दूर, किसान, औरत और जवान
30–31 दिसम्बर, 1999 को हुई हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की गोष्ठी में अपनाये फैसले

सिर्फ कम्युनिज्म ही हिन्दोस्तान को बचा सकता है
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव, कामरेड लाल सिंह द्वारा कानपुर कम्युनिस्ट गोष्ठी 2000 में प्रस्तुत किया पेपर

पूंजीवाद का संकट और हिन्दोस्तानी राज्य का खतरनाक रास्ता यह दिखाता है कि कम्युनिस्टों द्वारा इंकलाब के लिये तैयारी करना बेहद जरूरी है
"हिन्दोस्तानी राज्य और क्रांति" पर नवम्बर 2002 में हुई कानफरेंस में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह द्वारा दिया गया मुख्य भाषण

भ्रष्टाचार, पूंजीवाद और हिन्दोस्तानी राज्य
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह का मज़दूर एकता लहर के संपादक कामरेड चन्द्रभान के साथ साक्षात्कार, मार्च 2014

हिन्दोस्तानी गणराज्य का नवनिर्माण करने और अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिलाने के कार्यक्रम के इर्द–गिर्द एकजुट हों ताकि सभी को सुख और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके!
घोषणा पत्र 2014 : 16वीं लोक सभा चुनावों के अवसर पर

यह चुनाव एक फरेब है
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह का मज़दूर एकता लहर के संपादक कामरेड चन्द्रभान के साथ साक्षात्कार, जनवरी, 2015

प्रकाशनों की सूची

किस प्रकार की पार्टी?
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की दूसरी राष्ट्रीय सलाहकार गोष्ठी, जो 29–30 दिसम्बर 1993 को रखी गयी थी, में अपनाया गया दस्तावेज

हम हैं इसके मालिक, हम हैं हिन्दोस्तान, मज़दूर, किसान, औरत और जवान
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के दूसरे महाअधिवेशन में अपनाया गया कार्यक्रम, अक्टूबर 1998

मज़दूरों और किसानों की हुकूमत और स्वेच्छा पर आधारित हिन्दोस्तानी संघ की ओर
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के तीसरे महाअधिवेशन के दस्तावेज़, जनवरी 2005

कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के चौथे महाअधिवेशन के दस्तावेज़
अक्टूबर 2010

शेष भाग कवर के पीछे

पुनः अनुवादित संस्करण, नवंबर 2016

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के लिये
लोक आवाज पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स

ई–392, संजय कालोनी
ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज़–2
नई दिल्ली–110020 द्वारा प्रकाशित और वितरित

Web: www.cgpi.org,
Facebook: www.facebook.com/CommunistGhadar/
Email: info@cgpi.org